हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

22 फरवरी, 2019

खण्ड–1, अंक–3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (प्रथम बैठक)

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा के भूतपूर्व उप–मुख्यमंत्री का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनन्दन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

विभिन्न मामले उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

बैठक का समय बढ़ाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 22 फरवरी, 2019 (प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

To Increase The Capacity Of Hospital

***2945. Shri Aseem Goel:** Will the Health Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Civil Hospital, Ambala City from 200 beds to 300 beds, if so, the time by which its capacity is Likely to be increased?

Health Minister (Shri Anil Vij) : Yes, Sir Administrative approval of Rs. 64.71 Cr. has been issued on dated 20.12.2018. It will take approximately 24-36 months for completion of construction required for upgradation.

श्री असीम गोयलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 64 करोड़ 71 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित भवन के लिए मिल चुकी है। इस भवन के निर्माण के लिए कल ही 24 करोड़ 27 लाख का एक टैंडर भी लग चुका है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और अभी तक विपक्ष के सदस्य सदन में नहीं आए हैं। वे डिमॉरलाईज हो चुके हैं इसलिए वे सदन में समय पर नहीं आते हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो कोई भी माननीय सदस्य सदन में नहीं आया है। इस समय सदन में कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों की संख्या बिल्कुल जीरो है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, इस समय सदन में कुछ सदस्य इनेलो के, कुछ निर्दलीय सदस्य बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी के सभी सदस्य सदन में उपस्थित हैं।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य मैदान छोड़कर भाग गए हैं। सदन में हमारी पार्टी के ही सभी सदस्य बैठे हैं। आज विपक्ष के सदस्यों को विदाई पार्टी देनी चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार बेदीः अध्यक्ष महोदय, सदन में इनेलों के जो 5 माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये भी अपने ही हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य राजनीति की गंगा में किनारे पर बैठे हुए हैं।

.....

Premium Collected Under PMFBY

***2977. Shri Ram Chand Kamboj:** Will the Agriculture Minister be pleased to state -

(a) the total amount of premium collected from the farmers of Haryana under the Pardhan Mantri Fasal Bima Yojna during the year 2017-18; and

(b) the amount of compensation disbursed to the farmers of State for their damaged Rabi and Kharif crops during the year 2017-18 ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : (क) वर्ष 2017–18 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत हरियाणा के किसानों से 208.98 करोड़ रूपए की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई।

(ख) वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के किसानों को 849.73 करोड़ रूपये की राशि दावे के रूपमें वितरित की गई है।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सैशन में भी यह विषय उठाया था और आज भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सिरसा जिले के 77 गांवों के किसानों की फसल भी खराब हुई थी और वहां के किसान मुआवजे से वंचित रह गये थे। इस समय भी लगभग 19 गांवों में मुआवजा देने की घोषणा होने के बाद संबंधित गांवों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं लिस्ट भी भिजवा दूंगा। यह मुआवजा राशि वर्ष 2017 से पैंडिंग है। कम्पनीज द्वारा किसानों का बीमा प्रीमियम तो काट लिया गया था परन्तु अभी तक उन किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पायी है। अब वर्ष 2019 चल रहा है। इन 19 गांवों की लगभग 35–36 करोड़ रूपये की मुआवजा राशि पैंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह बकाया मुआवजा राशि कब तक संबंधित किसानों को दे दी जाएगी?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी भी है कि वह मुआवजा राशि क्यों पैंडिंग है तो उसके बारे भी सदन में जानकारी दे

दें और साथ ही साथ संबंधित गांवों की लिस्ट भी दे दें। उसके बाद इस पर कार्रवाई करेंगे।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि संबंधित 19 गांवों की गिरदावरी भी हो चुकी है। बीमा कम्पनीज द्वारा संबंधित गांवों की अथॉराईज्ड लिस्ट भी बनायी गयी थी और वह लिस्ट मैं माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संबंधित लिस्ट भिजवा दें उसके बाद मैं तुरंत कार्रवाई करवा दूंगा।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि वर्ष 2017 में मेरे हल्के के गांवों में कुछ पशुओं की डैथ हो गयी थी और पिछले सैशन के दौरान माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि जिन पशुओं की अचानक डैथ हो जाती है, उनको मुआवजा देने के लिए एक पॉलिसी बना दी है और जिन किसानों के पशुओं की अचानक डैथ हुई है, उनको दो–चार दिन में मुआवजा राशि भी दे दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन पिछले सैशन के दौरान दिया गया था, परन्तु अभी तक संबंधित लोगों को उनके मरे हुए पशुओं की मुआवजा राशि नहीं मिली है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा संबंधित मुआवजा राशि भिजवा दी गयी है और यदि किसी को यह मुआवजा राशि नहीं मिली है तो संबंधित डी.सी. से इसकी जानकारी ली जा सकती है। इसके लिए माननीय सदस्य भी डिप्टी कमीशनर से मिल सकते हैं।

श्री राम चन्द कम्बोजः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में अभी तक भी पशुपालकों को संबंधित मुआवजा राशि नहीं मिली है।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वे मुआवजा राशि लेने के लिए संबंधित डिप्टी कमीशनर से मिल लें। माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से मुआवजा राशि एप्रूव होकर डिप्टी कमीशनर्ज के पास भेजी जा चुकी है।

.....

हरियाणा के भूतपूर्व उप–मुख्यमंत्री का अभिनन्दन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आज श्री चन्द्रमोहन, पूर्व उप–मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार सदन की कार्यवाही देखने के लिए वी.आई. पीज़. गैलरी में विराजमान हैं । मैं पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री बलकौर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में गांव देसू मलकाना के किसानों की गेंहू की 80 एकड़ फसल आग की चपेट में आने से जलकर राख हो गई थी। हरियाणा सरकार ने अनाउंसमेंट भी की थी कि उन किसानों को 12000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा लेकिन अभी तक उन किसानों को कोई मुआवजा राशि नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन किसानों को कब तक मुआवजा दे दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह एक सैपरेट प्रश्न है। अगर माननीय सदस्य मुझे इस प्रश्न की पूरी जानकरी देंगे, तो हम इस बारे में संज्ञान लेंगे।

———————————

To Provide Subsidy on Electric Vehicles

***2984. Smt Prem Lata :** Will the Transport Minister be pleased to state

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide subsidy on purchase of electric/hybrid vehicles; if so, the details thereof and

(b) whether any policy has been formulated by the Government to set up charging stations for electric vehicles in the State?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : (क) व (ख) नहीं श्रीमान जी।

श्रीमती प्रेम लता : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का लगभग 65 प्रतिशत एरिया एन.सी. आर. में आता है और वहां पर डीजल/पैट्रोल की गाड़ियां जैसे ट्रक, बसें, थ्री व्हीलर, छोटे व्हीकल्स और ऑटो आदि चलते हैं, जिनसे बहुत प्रदूषण फैलता है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो प्रदूषण से सेहत खराब होने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इन गाड़ियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रदूषण के कारण जो

पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको चलते टाईम बहुत दिक्कतों का समाना करना पड़ता है क्योंकि कई बार ट्रकों का धुआं सीधे नाक की तरफ आता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रावधान किये गये हैं ? प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्र सरकार का भी नीतिगत फैसला है कि जितना हम प्रदूषण को कम कर सकेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। मेरा एक सुझाव है कि सी.एन.जी. या इलैक्ट्रिक बसें चलाई जायें और यदि संभव हो सके तो हाईब्रिड व्हीकल्ज़ भी चलाये जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं हाईब्रिड व्हीकल्ज़ के बारे में बताना चाहती हूं कि इनमें बैटरी और पैट्रोल/डीजल के इंजन इक्ट्ठे होते हैं। मान लो आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और पहले गाड़ी पैट्रोल पर चल रही थी और थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी का पैट्रोल खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक्ली गाड़ी का इंजन ट्रांसफर होकर बैटरी पर चलने लगेगा। इस प्रकार से प्रदूषण कम होगा और गाड़ी की कंडीशन भी ठीक रहेगी। प्रदूषण कम होने से हमारी सेहत भी ठीक बनी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से यही कहना है कि हमें लोगों की भलाई के लिए ही कदम उठाने चाहिएं और प्रदूषण को कम करने के लिए हर तरह की कोशिश करनी चाहिए।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या श्रीमती प्रेमलता जी मेरे गांव के हिसाब से बुआ जी लगती हैं। बुआ जी ने भतीजे से सवाल पूछा है लेकिन सवाल पूछने का हक भतीजे को बुआ जी से होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि इस तरह की गाड़ियों की खरीद के बारे में सब्सिडी देने के लिए सरकार के पास कोई प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रिक हाईब्रिड वाहनों के मोटर वाहन की कोई विशेष दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। हालांकि यह सूचना दिनांक 29.9.2017 के अनुसार बैटरी चालित या सी.एन.जी. वाहनों के पंजीकरण के मामले में एकमुश्त 20 प्रतिशत की छूट दी जाती है। हाईब्रिड वाहनों को गैर परिवहन वाहनों के नये पंजीकरण के मामले में एकमुश्त 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है। जैसा कि माननीय सदस्या ने सवाल पूछा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए जैसे एन.सी.आर. में 10 साल डीजल की पुरानी गाड़ी और 15 साल पैट्रोल की पुरानी गाड़ी नहीं चल सकती है । अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटिड को पर्यटन विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव आया है कि दिल्ली राज मार्ग पर राई, समालखा, पानीपत, करनाल,

कुरूक्षेत्र और अम्बाला में इलैक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जर स्टेशन लगाए जाएं ताकि इन गाड़ियों की बैटरी रिचार्ज हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि अभी इसके लिए प्रस्ताव विचाराधीन है, जैसे ही केन्द्र सरकार इस बारे में कोई फैसला करेगी वैसे ही हम इसे हरियाणा प्रदेश में लागू कर देंगे ।

श्रीमती प्रेमलता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि प्रस्ताव तो आते रहते हैं लेकिन इसका कोई टाईम पीरियड फिक्स तो होना चाहिए कि यह कार्य एक साल में होगा या दो साल में हो होगा क्योंकि यह एक बैटरी चार्ज सिस्टम है जो पेट्रोल पम्प की तरह नहीं होता है। जैसे कि हमें मोबाईल बैटरी चार्ज करने में समय लगता है वैसे ही व्हीकल्ज़ की बैटरी चार्ज होने में भी समय लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ऐसा कोई प्रावधान करें जिससे सड़क पर चलने वाले व्हीकल्ज़ मालिक अपनी गाड़ी की बैटरी को वहां रिचार्ज कर सकें। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी कि मान लो कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी की बैटरी को चार्जिंग पर लगाकर आधे–पौने घंटे के लिए बाजार में काम करने के लिए चला जाये तो वापिस आने पर उसको अपनी गाड़ी रिचार्ज हुई मिलेगी। इससे एक फायदा तो यह होगा कि प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा उसके पैसे भी बचेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया था कि भारत में दो करोड़ इलैक्ट्रिक गाड़ियां और हाई ब्रिड व्हीकल्ज़ लेकर आयेंगे। मैं चाहती हूं कि हरियाणा सरकार इसके बारे में भी विचार करे क्योंकि दिल्ली के तीनों तरफ से हरियाणा की सीमा लगती है और बहुत सी गाड़ियां दिल्ली में आती जाती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, कहने का अभिप्राय यह है कि दिल्ली में चारों तरफ से व्हीकल्ज़ आते जाते रहते हैं, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण का लैवल काफी बढ़ गया है ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि यहां पर व्हीकल्ज़ की बैटरी रिचार्जिंग की बात आई है इस सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि हम इसकी रिचार्जिंग की व्यवस्था पी.पी.पी. मोड के तहत सोलर सिस्टम से करवाने की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। जो सोलर सिस्टम से हमें एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी वह हमारे इलैक्ट्रिक पूल में चली जायेगी। इससे बैटरी इत्यादि भी रिचार्ज़ होती रहेंगी। अभी यह पूरा मामला अण्डर प्रोसैस है।

.....

The Total Quantity of Drinking Water

***2943. Smt Seema Trikha :** Will the Urban Local Bodies Ministerbe pleased to statethe total quantity of drinking water required in Badkhal Assembly Constituency togetherwith the quantum of water being supplied alongwith the number of boosters thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन): श्रीमानजी, बड़खल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को कुल 81 एम.एल.डी. पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है।वर्तमान में 15 बूस्टिंग स्टेशनों के माध्यम से 77 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

श्रीमती सीमा त्रिखा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी को यह बताना चाहती हूं कि फरीदाबाद जिले में जो बड़खल विधान सभा क्षेत्र है उसमें इस समय 10 वार्ड हैं जो कि पूरे जिले में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं। फरीदाबाद के एक औद्योगिक शहर होने की वजह से देश के अलग–अलग हिस्सों से लोगों के आने के कारण यहां पर लगभग 56 परसैंट या यूं कह लें कि पूरे शहर का स्लम भी इसी विधान सभा क्षेत्र में ही रहता है। हमारे वहां पर पानी की सप्लाई ददसिया में ट्यूबवैल लगाकर दी जा रही है। जो पाईप लाईन इसके लिए डाली गई हैं वे बहुत सी जगहों पर पंक्चर हैं जिससे हमारे किसी भी बूस्टिंग स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाई नहीं हो पाती है। वहां पर ट्यूबवैल्ज़ लगवाने के लिए माननीय मंत्री महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों में कहीं भी कोई कमी नहीं रही है। आज के दिन गुरूग्राम और फरीदाबाद की जमीन में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदया जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमें दो बूस्टिंग स्टेशन और दिये जायें और इसके साथ ही साथ ददसिया के किनारे 10 बड़े ट्यूबवैल्ज लगाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की पर्याप्त आपूर्ति की जाये।

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्या को यह बताना चाहती हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बड़खल विधान सभा क्षेत्र में 4 एम. एल.डी. पानी की कमी है यह बात हम भी स्वीकार करते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के स्तर पर सम्भावनायें तलाश करने के लिए विस्तृत तौर पर इस विषय को एग्जामिन किया गया है। जैसा कि माननीय

सदस्या ने स्वयं भी माना है कि वहां पर हमने काफी मात्रा में बड़े ट्यूबवैल्ज़ भी लगाये हैं। भविष्य में इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसमें हम यमुना नदी के किनारे पर 119 लाख रूपये की लागत से 12 नये ट्यूबवैल्ज लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 502.18 लाख रूपये की राशि से हम मेवला, सैक्टर–48 और लक्कड़पुर में तीन बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रीष्मकालीन सीजन आने से पहले इनको स्थापित कर दिया जायेगा ताकि वहां की जनता को गर्मियों के दिनों में पानी की कमी की वजह से कोई भी परेशानी न हो। हमारे पास फरीदाबाद में टोटल 15 एम.एल.डी. पानी की कमी है। इसके लिए नगर निगम, फरीदाबाद में हमने 210 अतिरिक्त ट्यूबवैल्ज़ लगाने की योजना तैयार की है। इन ट्यूबवैल्ज को भी हम शीघ्रातिशीघ्र लगवायेंगे।

श्रीमती सीमा त्रिखा : स्पीकर सर, मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगी।

.....

To Increase the Capacity of Sugar Mill

***2865. Shri Parminder Singh Dhull :** Will the Minister of State for Co-operation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Co-operative Sugar Mill, Jind, if so, the time by which the capacity of above said Sugar Mill is likely to be increased ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : हां, श्रीमान जी। उम्मीद है कि 1600 टी.सी.डी से 2200 टी.सी.डी की क्षमता अगले पिराई सत्र 2019–20 के आरंम्भ होने से पहले बढ़ा दी जाएगी।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : स्पीकर सर, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि यह हमारी एक बहुत पुरानी मांग थी कि जींद शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मंत्री जी ने वायदा किया है कि इस पिराई सत्र से जींद शुगर मिल की कैपेसिटी को बढ़ा दिया जायेगा लेकिन मैं यहां पर यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसी प्रकार का वायदा तो वर्ष 2017 और 2018 में भी किया गया था। मंत्री जी ने कहा है कि इस साल से जींद शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ा दी जायेगी। यह बहुत अच्छी बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मंत्री जी इस बार अपना

वायदा पूरा कर देंगे। मैं मंत्री जी से एक बात यह भी पूछना चाहूंगा कि जींद शुगर मिल को मुनाफे में लाने के लिए क्या गन्ने की खोई से बिजली बनाने की सरकार की कोई योजना है? इसी प्रकार से क्या वहां पर मिथाईल–एल्कोहल बनाने का भी कोई प्लांट सरकार लगाने के बारे में विचार कर रही है? इससे प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और जींद शुगर मिल को घाटे से भी उबारा जा सकेगा। शुगर मिल के घाटे से उबरने से पूरे इलाके को भी फायदा होगा। आज गन्ने की पूरी की पूरी वेस्ट इस्तेमाल हो सकती है इसलिए सरकार को इस दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिएं।

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय साथी को यह कहना है कि उन्होंने यह सही चिंता जाहिर की है ताकि हमारी सभी शुगर मिल्ज़ प्रोफिट में रहें। हमारे यहां पर गन्ने का रेट 340/– रूपये प्रति क्विंटल है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। चीनी का रेट 2,940/– रूपये प्रति क्विंटल से 3,000/– रूपये प्रति क्विंटल तक है। एक क्विंटल चीनी के उत्पादन में कुल लागत 4300/– रूपये से 4400/– रूपये के बीच से आती है। शुगर मिल्ज़ को घाटे से उबारने के लिए हम एथनॉल, अल्कोहल के साथ ही साथ दूसरे सम्बंधित प्लांट्स लगाने की भी योजना बना रहे हैं। पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रदेश की लगभग सभी शुगर मिल्ज़ में बहुत ज्यादा स्टॉफ की भर्तियां की हुई हैं जिसके कारण हमें उनकी सैलरी पर बहुत ज्यादा धनराशि खर्च करनी पड़ रही है जबकि शुगर मिल्ज़ की उतनी कमाई नहीं होती है। इस कारण सरकार शुगर मिल्ज़ को मदद कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए पानीपत, सोनीपत, जींद और शाहबाद की शुगर मिल्ज़ की कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया है।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या जीन्द की शुगर मिल की भी कैपेस्टी बढ़ाई जायेगी?

श्री मनीष ग्रोवरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हम हर शुगर मिल की कैपेस्टी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आने वाले पिराई सत्र में जींद शुगर मिल की कैपेसिटी 2200 टी.सी.डी. करेंगे लेकिन 2200 टी.सी.डी. की कैपेसिटी भी बहुत कम है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी तो मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि इन सभी शुगर

मिल्स की कैपेस्टी 3500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक होनी चाहिए क्योंकि हमारा गन्ने का एरिया भी बढ़ा है।

.....

To Double the Income of Farmers

***2885. Shri Kehar Singh :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to double the income of the farmers in State; if so, the details thereof ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त किया जाना है।

विवरण

राज्य सरकार ने कृषि उपज की लागत को कम करने तथा कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल, पशुधन तथा डेयरी विभाग तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित विभिन्न स्कीमों तथा परियोजानाओं के लागूकरण के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए है।

कृषि तथा किसान कल्याण विभागः

- न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की मात्राः

न्यूनतम समर्थन मूल्य (रू0 प्रति क्विंटल)			
क्र0सं0	**फसल**	**वर्ष 2014**	**वर्ष 2018**
1	गेहूं	1450	1840
2	चना	3175	4620
3	सरसों	3100	4200
4	धान (ग्रेड–ए)	1400	1770
5	धान	1360	1750
6	मक्का	1310	1700
7	बजरा	1250	1950
8	ज्वार	1530	2430
9	गन्ना	310	340
10	कपास	4050	5450
11	मूंग	4600	6975
12	मूंगफली	4000	4890
13	सूरजमुखी	3750	5388

- गेहूं और बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिकतम वृद्धि।
- बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतिहास में पहली बार गेहूं से अधिक है।
- गन्ने का मूल्य 340/–रू0 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो कि देश में उच्चतम है।

- राज्य आपदा प्रबंधन निधि के अधीन प्राकृतिक आपदाओं के मामले में 12000/– रूपये प्रति एकड़ तक फसल नुकसान का मुआवजा दिया गया है।
- रबी 2018 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत 5.98 लाख किसानों को 1140.98 करोड़ रूपये का मुआवजा दावा दिया गया है।
- वर्ष 2018–19 के दौरान 1950/– रूपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1.84 लाख एमटी बाजरा की रिकार्ड खरीद की गई है।
- प्रत्येक ऐसे किसान को 6000/– रूपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान लघु तथा सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पी0एम0–किसान) स्कीम के अधीन घोषणा की गई है।
- पहली बार 10694 क्विंटल मूंग की खरीद 5225/– रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई।
- उचित समय पर गुणात्मक इनपुट (बीज, कीटनाशक और उर्वरक) की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- 8259 औजारों के लिए तथा 1194 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए 171.73 करोड़ रूपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।
- किसानों को प्रथम चक्र के दौरान 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण और दूसरे चक्र के दौरान 10.95 लाख का वितरण।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी0एम0के0एस0वाई0) को अधीन सूक्ष्म सिंचाई तथा जल दक्षता के अधीन क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि।
- किसानों की विभिन्न वित्तीय, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन।
- 54 मंडियों में ई–नाम प्रारम्भ करके, किसान ताजा बाजारों की स्थापना से बेहतर विपणन अवसरों का सृजन।
- 11 मुख्य प्रांगण, 12 उप प्रांगण की स्थापना तथा 2 नए मुख्य प्रांगण तथा 3 उप प्रांगण निर्माण के अधीन है।
- पिछले 4 वर्षों में 650 करोड़ रूपये की लागत से 2115.60 कि0मी0 लम्बी सड़के जोड़ी गई हैं।

बागवानी विभागः

- किसानों को अंतर मूल्य के भुगतान के द्वारा चार सब्जियों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करने हेतू "भावांतर भरपाई योजना"।
- आलू तथा टमाटर का 400/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से तथा प्याज तथा फूलगोभी का 500/– रूपये प्रति क्विंटल की दर से विक्रय मूल्य का निर्धारण।
- ग्राम अंजनथली, जिला करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना।
- 340 बागवानी गांवों को मिलाकर फल तथा सब्जी के 140 समूह की स्थापना। यह समूह 3 वर्षों से 510/– करोड़ रूपये के बजट से फसल समूह विकास कार्यक्रम के अधीन पैक गृह सुविधाएं दे रहे हैं।
- बागवानी के तहत क्षेत्र को दोगुना करने और तीन गुना तक उत्पादन को बढ़ाने के लिए बागवानी विजन 2030 का लक्ष्य।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए 6 उत्कृष्ठ केन्द्रों की स्थापना।
- किसान सदस्यों के रूप में 34219 के साथ 22 जिलों में 96 एफ0पी0ओ0 स्थापित किए गए जो तीन वर्ष की अवधि से अधिक प्रौद्योगिकी, विपणन तथा व्यापार विकास के लिए सहायता दे रहे हैं।
- संरक्षित खेती प्रोत्साहन जिसके परिणामस्वरूप 527 हेक्टेयर को 169.44 करोड़ रूपये की सब्सिडी राशि के साथ कवर किया गया है।

पशुधन तथा डेयरी विभागः

- डेयरिंग इकाइयों की स्थापना करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करते हुए अतिरिक्त आमदनी के लिए स्त्रोत मुहैया कराना।
- 20 पशुओं की डेयरी की स्थापना के लिए ब्याज मुक्त ऋण की उपलब्धता।
- 3 से 5 देसी नस्ल की गायों की डेयरी की स्थापना पर 50 प्रतिशत अनुदान।
- उच्च दुग्ध देने वाली मुर्रा भैंसो के लिए 15000/– से 30000/– रूपये के नकद प्रोत्साहन के द्वारा पशुधन की प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि तथा अधिक दूध देने वाली देसी गायों के लिए 10000/– से 20000/– रूपये का नकद प्रोत्साहन के द्वारा पशुधन की प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि।
- पशु देखभाल और प्रजनन सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित पशु चिकित्सा संस्थान।
- राज्य में दूध के 24 प्रतिशत उत्पादन, अंडे में 21.98 प्रतिशत तथा मांस में 22.34 प्रतिशत उत्पादन की रिकार्ड वृद्धि।

मत्स्य विभागः

- 400 हेक्टेयर खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में उच्च मूल्य की सफेद झींगा मछली संस्कृति को बढ़ाना तथा अतिरिक्त 160 हेक्टेयर को चालू वर्ष के दौरान कवर किया जाएगा।
- 8.5 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की परियोजना लागत के साथ किसानों को 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत सब्सिडी देकर ताजे पानी एक्वाकल्चर का विकास।
- एक्वाकल्चर के लिए इनलैण्ड लवणिय/क्षारीय जल का उत्पादकता उपयोग
- रिसर्कूलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली (आर0ए0एस0) की स्थापना। रिसर्कूलेटरी एक्वाकल्चर प्रणाली के अधीन 13 इकाईयों की स्थापना की जा रही है जो उत्पादकता को दोगुनी तक बढ़ाएगी।
- किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16000 एकड़ जलमग्न बंजर भूमि का उपयोग मछली संस्कृति के लिए कवर किया जाएगा।

सिंचाई विभागः

- राज्य में सिंचाई की मात्रा में वृद्धि के परिणामस्वरूप तथा किसानों की आमदनी को पूरा करने के लिए कल्चरलएबल कमांड एरिया (सी0सी0ए0) को 24 फुट से 40 फुट प्रति एकड़ की वर्तमान मानदंड से पंक्तिबद्ध जलमार्ग की लंबाई में विस्तार।
- मानसून के मौसम में लगभग 4000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की आपूर्ति करने के लिए वाहक प्रणालियों की क्षमता बढ़ाना।
- जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के विभिन्न पंप हाउसों और नहरों की क्षमता में सुधार के लिए परियोजना, जिसकी लागत वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान 143 करोड़ रूपये पूरे हो चुके हैं।
- 8000 करोड़ रूप्ये की अनुमानित लागत पर लगभग 220 चैनलों का प्रमुख पुनर्वास/रीमॉडेलिंग कार्य को वित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। इससे नहरों में विभिन्न नुकसानों में कमी आएगी, जिससे राज्य भर में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जो अंततः राज्य में किसानों की आय का पूरक होगा।

श्री केहर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछले साढ़े चार साल में मैंने इस सदन में प्रश्न किये हैं तथा अपने क्षेत्र के किसानों की परेशानी को सदन के सामने रखने का काम किया है। साढ़े चार साल में मैंने 3 बार भूख हड़ताल भी की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का 15

प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो गुरूग्राम कैनाल की तलहटी में आता है जिसके कारण लगभग 20 हजार एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें पिछले 20 सालों से अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 45 गांव ऐसे हैं जहां पर जमीन के नीचे पानी नहीं है और नहरी पानी टेल तक नहीं पहुंचता है जिसके कारण किसानों की आर्थिक हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। मैंने उनके लिए भूख हड़ताल भी की थी। उसके लिए सरकार ने एक प्रोपोजल तैयार की थी कि हम 90 दिन तक ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि हर टेल तक पानी पहुंच सके। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वहां के किसानों की आर्थिक हालत को सुधारा जा सके?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य इस बारे में पार्टीकुलर सवाल पूछते तो मैं उसकी अलग से एक–एक डिटेल लेकर आता। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने इनके एरिया पलवल में एक एकीकृत बागवानी केन्द्र की स्थापना की है जिसका उद्घाटन भी हो चुका है। बागवानी के क्षेत्र में कैसे किसान आगे बढ़ें उस पर काम शुरू हो चुका है और उसका शिलान्यास भी हमारी सरकार के द्वारा ही किया गया था। अगर किसान बागवानी का काम करना चाहते हैं तो अब इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने भिन्न–भिन्न किसानों की आमदनी एम.एस.पी. के माध्यम से 5 हजार से लेकर 12 हजार रुपये तक बढ़ाने का काम किया है। अगर किन्हीं दो फसलों के कम्बीनेशन का औसत निकाल लिया जाये तो शायद कोई कम्बीनेशन ऐसा नहीं बैठेगा जिसमें 12 हजार रुपये से कम आमदनी हुई हो। अगर गेहूं और धान का कम्बीनेशन, सरसों और बाजरे का कम्बीनेशन देख लिया जाये या गन्ने का जो कि सालभर की फसल है, देखा जाये तो वह 12 हजार के आसपास ही बैठता है। गन्ने का मूल्य हमारी सरकार ने 30 रुपये बढ़ा कर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। उस हिसाब से अगर औसतन 300 क्विंटल मान लिया जाये तो भी 9000 रुपये की आमदनी बढ़ जाती है और यदि फसल अच्छी लगी हुई है तो 400 क्विंटल तक भी गन्ना निकल आता है जिससे 12 हजार रुपये की आमदनी बढ़ जाती है। इस प्रकार से हमने एम.एस.पी. के माध्यम से किसानों की आमदनी बढ़ाने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि जब अच्छी फसल पैदा हो जाती है तो उसको बेचने की दिक्कत आती है। इसके लिए हमारी सरकार ने किसानों की फसल का एक–एक दाना खरीदने की व्यवस्था

की है तथा बढ़े हुये दामों पर किसान की फसल खरीदकर उसकी आमदनी बढ़ाने का काम किया है। तीसरी बड़ी व्यवस्था हमने जोखिम फ्री खेती करने के लिए की है। मुझे यह बताते हुये खुशी हो रही है कि जब–जब किसानों पर कोई जोखिम आई है तो हमारी सरकार ने किसानों का मुआवजा प्रति एकड़ 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया है। उसको बढ़ाते हुये हम यहां तक लेकर गये कि आज की तारीख में हम 2651 करोड़ रुपये किसानों को डिजास्टर मैनेजमैंट के मुआवजे के रुप में दे चुके हैं। इसमें भी 25–30 प्रतिशत किसान अलग–अलग फसलों के बीमे में कवर होते हैं और 1140 करोड़ 58 लाख हम उनको बीमे के मुआवजे के रुप में दे चुके हैं। इसी प्रकार से 4 करोड़ 27 लाख रुपये का मुआवजा भावांतर भरपाई योजना के तहत हम आलू के किसानों को दे चुके हैं और आज की तारीख तक हम 3796 करोड़ 27 लाख रुपये जोखिम फ्री योजना के तहत किसानों के खाते में जमा करवा चुके हैं जोकि रिकॉर्ड राशि है । जबकि पिछले 10 साल में यह राशि 1158 करोड़ रुपये दी गई थी । हम इस समय 3796 करोड़ 27 लाख रुपये भिन्न–भिन्न रूप में किसानों को कम्पन्सेशन के रूप में दे चुके हैं । जैसे मैंने बागवानी का जिक्र किया है । इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि केवल इनके यहां ही हमने एंटीग्रेटिड सैंटर खोला है । हमने श्यामगढ़ में आलू का एंटीग्रेटिड सैंटर खोला है, राम नगर में बी–किपिंग का सैंटर खोला है, लाडवा में ऊष्णकटिबन्ध फलों का सैंटर खोला है। इस तरह से हम हर जिला में एक उत्कृष्टता केन्द्र अर्थात एक्सीलैंसी सैंटर खोलते जा रहे हैं । हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें 140 क्रोप कलस्टर सैंटर बनाए हैं । हमने 340 गांवों को बागवानी के लिए 510 करोड़ रुपये बजट दिया है ताकि हमारे किसान क्रोप डाईवर्सिफिकेशन के तहत बागवानी की तरफ आ जाएं । पशु पालन को भी हमने तेजी से बढ़ावा दिया है । दूध प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली भैंस को 30 हजार रुपये और गाय को 20 हजार रुपये ईनाम दिया जाता है । इस तरह से हम अपनी सरकार के समय में किसानों को अब तक 33 करोड़ रुपये ईनाम के रूप में दे चुके हैं । पशुओं की सबसे अच्छी नस्ल पर भी हमने ढ़ाई–ढ़ाई लाख रुपये का ईनाम देना शुरू किया है । प्रथम आने वाली मुर्रा नस्ल के पशु पर ढ़ाई लाख रुपये और पहले रनरअप अर्थात दूसरे स्थान पर आने वाली नस्ल को एक लाख रुपये दिया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आप भी पशु मेले में आए थे । आज के दिन हमारे हरियाणा प्रदेश के पशुओं की नस्ल पूरे देश में सर्वोच्य है । पशुओं की नस्लों के बारे में बहुत चर्चा

होती है क्योंकि इस बार महामहिम राष्ट्रपति जी भी मेले में आए थे तो हमने भी उनको एक बैस्ट मुरर्रा नस्ल की भैंस दिखाई थी । आज के दिन एक कहावत है कि 'जिसके घर में मुर्राह उसका ऊंचा तुर्रा ।' हमने उनको एक साहीवाल नस्ल की गाय पहुंचाने की बात कही है । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दूध डेरी खोलने के लिए ऋण बिना ब्याज के दिया जाता है । अगर कोई आदमी 50 गाय या भैंस तक की डेरी खोलेगा तो हम उससे ब्याज नहीं लेते हैं । इसी तरह से देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए पांच गायों तक की खरीद के लोन पर सब्सिडी भी दी जाती है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मछली पालन को भी हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है । मछली पालन के क्षेत्र में भी जब हमारी सरकार आई थी तब विभाग 5 करोड़ रुपये की सब्सिडी देता था । अब हम उसमें 80 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे हैं । उसमें भी हम आगे बढ़े हैं । इस तरह से हमने हर सैक्टर के किसान की आमदनी बढ़ाई है । माननीय सदस्य का एक सवाल बिल्कुल वाजिब है जिसको मैं भी मानता हूं । जिस तरह से सरकार भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी जिलों में नहरी पानी को टेल तक पहुंचाने में अच्छी प्रकार से कामयाब हुई है उतनी अच्छी कामयाबी हमें मेवात और पलवल में अभी नहीं मिली है । सरकार पूरे प्रदेश में विशेषकर मेवात और पलवल में भी नहरी पानी का बेहतर इन्तजाम करने की कोशिश कर रही है । मेवात कैनाल के माध्यम से हम वहां टेल तक नहरी पानी पहुंचाना चाहते हैं जिसके लिए हमारी एक सभी विधायकों की कमेटी भी बनी है कि हम इस क्षेत्र के लिए पानी का कैसे बेहतर इन्तजाम करें । जहां किसान को रेट फायदा देता है वहां पानी भी डबल इन्कम करता है । नहरी पानी मिलने से किसान दो फसल लेने में कामयाब हो जाता है । नहरी पानी किसानों को मिल सके इस व्यवस्था की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है और इस बारे में माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है ।

श्री केहर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि वहां के किसानों को सिंचाई का पानी देने के लिए कोई विशेष स्कीम बनाई जाए । वहां उटावड़ डिस्ट्रिब्यट्री के ऊपर गोछी ड्रेन पड़ती है वहां हथीन डिस्ट्रिब्यूट्री के ऊपर चार–चार, पांच–पांच पम्प सैट लगा दिए जाएं और महीने में 7–7 दिन उस डिस्ट्रिब्यट्री से पानी दे दिया जाए । उससे हमारे किसान की आमदनी दो गुणी बढ़ जाएगी ।

.....

Outdoor Publicity Policy

***2920. Shri Umesh Aggarwal :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any outdoor publicity policy in Gurugram Municipal Corporation Area; if so, the details thereof;

(b) the time since outdoor publicity tenders have not been invited;

(c) per year loss to Gurugram Municipal Corporation for not offering outdoor publicity tenders; and

(d) the yearwise income of MCG from outdoor publicity tenders during last 5 years?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) :

(क) हां श्रीमान, हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपविधि, 2018 गुरूग्राम के नगरपालिका क्षेत्र में लागू है;

(ख) अंतिम निविदा 07.07.2015 को आमंत्रित की गई और दिनांक 01.03.2016 को आवंटित कार्य 28.02.2018 तक मान्य था;

(ग) शुन्य;

(घ) पिछले पांच वर्षो के दौरान विज्ञापन से नगर निगम, गुरूग्राम क्षेत्र की आय का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	**निविदाओं के माध्यम से प्राप्त राशि (लाख रूपये में)**	**निविदाओं और अनुमतियां सहित कुल राशि (लाख रूपये में)**
2014–15	87.89	2124.72
2015–16	40.00	738.47
2016–17	820.27	1607.07
2017–18	823.07	1298.00
2018–19 (9 फरवरी 2019 तक अर्जित राजस्व)	.....	1104.50

श्री उमेश अग्रवालः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें निविधाओं के माध्यम से वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 में केवल 87 लाख तथा 40 लाख रूपये की नगर निगम, गुरूग्राम की आय बताई गई है, जबकि वास्तव में यह आय लगभग 100 करोड़ रूपये सालाना होनी चाहिए थी। इसी प्रकार

पिछले दो सालों में लगभग 8–8 करोड़ रूपये की आय निविधा के माध्यम से हुई बताई गई है। मंत्री महोदया ने रिप्लाई के माध्यम से यह भी बताया है कि अंतिम टैंडर की वैलिडिटी 28.2.2018 को समाप्त हो गई थी और इसके बाद कोई नया टैंडर जारी नहीं किया गया। एक साल की लंबी अवधि बीत चुकी है। इस एक साल के दौरान में नगर निगम, गुरूग्राम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का आउटडोर पब्लिसिटी का कोई भी टैंडर जारी नहीं किया गया है। इसी प्रकार से टैंडर्ज एंड परमिशंज के माध्यम से वर्ष 2014–15 में जो नगर निगम, गुरूग्राम की आय 2124 करोड़ रूपये के लगभग थी जबकि यदि बाद के वर्षों में देखें तो यह आय लगातार घटती रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि गुरूग्राम नगर निगम के अंदर आउटडोर पब्लिसिटी की ठीक ढंग से योजना बनाई गई होती या बनाई जाये तो लगभग 100 करोड़ रूपये सालाना की आय निगम को हो सकती है। मैं एक बात और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हाल ही में केवल मात्र यूनिपोल विज्ञापन हेतु टैंडर जारी किए गए जबकि विज्ञापन के लिए पोलक्योशक, मोबाईल वैन प्राइवेट बिल्डिंग्ज तथा बस क्यू शैलटज जैसे दूसरे माध्यम भी अपनाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले पांच साल में इनमें से किसी भी आइटम का कोई भी टैंडर जारी नहीं किया गया है और इसका फायदा अनअथोराइज्ड मीडिया पिछले चार से लगातार उठाता आ रहा है और इसके कारण से नगर निगम गुरूग्राम को लगभग 100 करोड़ रूपये सालाना का नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यहां पर केवल मात्र यूनिपोल विज्ञापन हेतु टैंडर ही क्यों जारी किए गए जबकि अन्य विज्ञापनों के माध्यमों के लिए भी टैंडर जारी करने चाहिए थे और भविष्य में दोबारा ऐसा न हो इसके लिए क्या सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई है?

श्रीमती कविता जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूँ कि जैसाकि माननीय सदस्य ने यूनिपोल का जिक्र भी किया है, पहले हमारी विज्ञापन की जो पॉलिसी होती थी उसमें रोड्ज के साइड में विज्ञापन लगाने का प्रावधान था । यहां पर पहले 69 यूनिपोल थे जिनका टैंडर जारी करने के पश्चात नगर निगम, गुरूग्राम को आय प्राप्त होती थी लेकिन बाद में नगर निगम ने हाई कोर्ट की एप्रूवल व गाइडेंस के बाद बिल्डिंग बाईलाज नोटिफाई कर दिए गए और इस प्रकार आर.ओ.डब्ल्यू. की भी जो परिभाषा पहले हुआ करती थी, उसको बदल दिया गया और इस नई परिभाषा के तहत रोड्ज के साईड में चाहे वह बरम्स

हों या चाहे ग्रीन बैल्ट हो, अब वह यह सारा एरिया आर.ओ.डब्ल्यू. में शामिल होता है जोकि पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टड एरिया है और यहां पर किसी भी सूरत में एडवर्टिजमैंट नहीं किया जा सकता, यही वे कारण रहे जिनकी वजह से विज्ञापन के दूसरे माध्यमों के लिए टैंडर जारी नहीं किए गए लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टैंडर जारी न करने की वजह से निगम को किसी तरह का नुकसान हुआ हो। इसका कारण यह है कि नए बिल्डिंग बाईलाज में प्राइवेट प्रापर्टी जैसे मोबाईल वैन या अपनी प्रापर्टी की दीवारों पर यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन लगाना चाहता है तो इसके लिए भी रेट्स को नोटिफाई किया हुआ है। 21 मई को हमने रेट्स को नोटिफाई किया है जिसका नतीज़ा यह रहा है कि हर साल हमारी आय बढ़ती ही जा रही है। इससे आगे बढ़ते हुए हमने इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा लोगों का रूझान बढ़ाने के लिए ताकि वे बड़ी संख्या में एप्लाई कर सकें, आन लाईन पोर्टल की सुविधा भी प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने अभी जो चिंता जाहिर की है, वह चिंता भी वाजिब है क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह की डेफिनेशन की आड़ में तमाम प्रकार के खेल भी खेले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कम्पीटिशन बहुत ज्यादा है एजेंसियां अगर कोई भी इलीगल तरीके से काम करने की कोशिश भी करती हैं तो एक दूसरे की शिकायत पर भी तुरंत एक्शन लिया जाता है। गुरूग्राम में ज्वाईंट कमिश्नर की अध्यक्षता में इंफोर्समैंट विंग खाली एडवरटाईजमैंट के लिए लगाई हुई है। इसका फायदा यह होता है कि गलत तरीके से कोई भी एजेंसी प्रचार नीति का गलत यूज़ करेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। दूसरा हम माननीय उच्च न्यायालय में भी इस बात को लेकर जाने का प्लान कर रहे हैं कि जो आर.ओ.डब्ल्यू. की परिभाषा है उसको थोड़ा रिलैक्स किया जाये ताकि दूसरी संभावनों को भी तलाशा जा सके। जिससे नगर निगम, गुरूग्राम की आय को बढ़ाया जा सके।

श्री उमेश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने बताया है कि अन्तिम निविदा जो थी वह दिनांक 01.03.2016 से लेकर दिनांक 28.02.2018 तक दो साल तक की अवधि तक थी। लेकिन दिनांक 28.02.2018 को निविदा समाप्त हो गई थी जिसको समाप्त हुए लगभग एक साल हो गया है। इसमें पहली बात तो यह आती है कि एक साल के अंदर–अंदर नये टैंडर की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि क्या सवा चार साल के दौरान महकमें ने यूनिपोल

को छोड़कर मोबाईल वैन, बस क्यू शैल्टर, ट्री गार्ड या किसी पोलक्योशक का कोई टैंडर किया है? क्या इस तरह के टैंडर्ज से कोई आय महकमें को प्राप्त हुई है?

श्रीमती कविता जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दिनांक 28.02.2018 को निविदा समाप्त होने के बारे में पूछा है, इस बारे में पहले भी जवाब दे चुकी हूँ। फिर से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि आर.ओ.डब्ल्यू. की परिभाषा आने के बाद मैक्सिमम जो नगर निगम का एरिया है, जहां पर यूनिपोल्स लगते थे, वे उस परिभाषा के अंदर आ गए हैं। इसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी एप्रूव कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर्ज के मुताबिक ही विभाग के बायलॉज बने हुए हैं, जिनके तहत आज के दिन ऐसा एरिया यूनिपोल्स का नहीं बनता जिनके लिए टैंडर कर सके। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि महानगर विकास प्राधिकरण गुरूग्राम बन गया है और परिवहन विभाग के बस क्यू शैल्टर असके अधीन आ गए हैं। वैसे महानगर विकास प्राधिकरण गुरूग्राम इनका शीघ्र ही टैंडर करने जा रही है। जहां तक मोबाईल वैन की बात है, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल पर भी एप्लाई कर सकते हैं। इसको पूरी तरह से लागू कर रखा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहती हूँ कि एजेंसियों के बीच में बहुत ज्यादा कम्पीटिशन है, अगर कोई भी एजेंसी बिना अनुमति के चाहे वह मोबाईल वैन पर हो, चाहे बस क्यू शैल्टर पर हो, पब्लिक प्रॉपर्टी पर हो या प्राईवेट प्रॉपर्टी पर हो उसके बारे में उनकी आपसी शिकायत से और हमारी इन्फोर्समैंट विंग के माध्यम से भी पता चल जाता है और तुरंत एक्शन लिया जाता है।

.....

To Extend the Metro Rail Project

***2940. Shri Tek chand Sharma :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the metro rail from Ballabhgarh up to Palwal; if so, the time by which it is likely to be extended?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नही, श्रीमान् जी।

श्री टेक चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश चहूंमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है। हमारे यहां के.एम.पी. ऐक्सप्रेस–वे परियोजना और के. जी.पी. ऐक्सप्रेस–वे परियोजना बनकर तैयार हो गई है। पलवल जिला एन.सी.आर. के अन्तर्गत आता है। अध्यक्ष महोदय, सरकार मैट्रो रेल परियोजना को एक तरफ

बावल दूसरी तरफ बहादुरगढ़ तक विस्तार करना चाहती हो। अभी तक आज के दिन मैट्रो रेल नोएडा से भी जुड़ चुकी है। अध्यक्ष महोदय, पलवल जिला पिछड़ा क्षेत्र रहा है लेकिन मौजूदा सरकार ने पलवल जिला में स्किल यूनिवर्सिटी वगैरह काफी विकास के काम किए हैं, पृथला औद्योगिक क्षेत्र भी डिवैल्प हो रहा है। फिर भी आज के दिन पलवल जिला को मैट्रो रेल से जोड़ना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि जहां पांच शहर के.एम. पी. ऐक्सप्रेस–वे पर बसाने की बात है, वहां तक पलवल की मैट्रो रेल से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो एन.सी.आर. में भी ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री टेक चन्द शर्मा ने मैट्रो रेल की पलवल तक विस्तार की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूँ कि मैट्रो रेल का विस्तार दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ और कुण्डली तक हुआ है। फरीदाबाद और ग्रुरूग्राम के अलावा फरीदाबाद की दिशा में बल्लबगढ़ तक तो पहले ही मैट्रो का विस्तार हो चुका है। बल्लबगढ़ से आगे पलवल का रास्ता लगभग 24 किलोमीटर का है और वहां नैशनल हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है। अब वहां पर नई बसासत और नया विकास आ रहा है। गांव झाड़सेतली और सिकरी में बसासत बढ़ रही है। मैट्रो रेल की आवश्यकता फुटफॉल्ज के आधार पर तय की जाती है। वहां भी फुटफॉल्स के आधार पर ही मैट्रो रेल चलाने पर विचार किया जाएगा । इसका कारण यह है कि मैट्रो ट्रेन चलाने का प्रति किलोमीटर 200–300 करोड़ रूपये खर्च आता है । इसके अलावा अगर लैण्ड की ज्यादा रेट पर एक्विजीशन होती है तो यह खर्च और बढ़ जाता है। अतः इन्हीं चीजों को देखते हुए फिलहाल वहां के लिए मैट्रो ट्रेन चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । आज के दिन हर तरफ तेजी से विकास हो रहा है । वहां पर के. एम.पी. और के.जे.पी. एक्सप्रैस वे चालू हो चुके हैं और इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट तेजी से हो रही है । इन चीजों को देखते हुए भविष्य में वहां पर मैट्रो ट्रेन चलाने के विषय में अवश्य विचार किया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि वहां पर आर.आर.टी.एस. नैटवर्क का डिवैल्पमैंट हो रहा है । इसका ओवरऑल कंसैप्ट भारत सरकार ने बनाया है । इसका रूट दिल्ली से शुरू होकर गुरूग्राम, रिवाड़ी से होते हुए अलवर तक जाता है । आर.आर.टी.एस. के चौथे फेज़ के इस कंसैप्ट में भी इसको इन्कलूड किया हुआ है लेकिन उसमें भी समय–सीमा देना संभव नहीं है ।

श्री टेक चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है । अतः माननीय मंत्री जी को मुझे कम से कम आश्वासन तो देना ही चाहिए । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैट्रो नैटवर्क पृथला तक तो बढ़ाने का आश्वासन देना ही चाहिए जिससे आगे चलकर उस क्षेत्र का अच्छा विकास हो सके । अगर आज माननीय मंत्री जी सदन में यह आश्वासन देंगे तो सरकार बनने पर अगले 5 साल के कार्यकाल में पृथला में भी मैट्रो रेल चलने की संभावना पैदा होगी ।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवा लेंगे । उसके बाद वहां पर मैट्रो रेल चलाने की जैसी संभावना होगी हम उसी हिसाब से कार्य करेंगे ।

पं. मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि किसी भी शहर के विकास के लिए मैट्रो रेल जीवन रेखा है । बदरपुर से बल्लभगढ़ तक के मैट्रो के रूट में जो बड़खल और फरीदाबाद का एरिया आता है उसके एक–एक किलोमीटर के दायरे में आने वाली बहुत–सी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं । जो फैक्ट्रीज चल रही हैं उनमें बहुत कम काम चल रहा है । अतः इन कारणों से वहां पर मैट्रो की सर्विस शुरू करने पर उसके खर्च के अनुरूप इनकम नहीं हो पाएगी । मेरा कहना है कि जब तक उन एरियाज की जमीन को कमर्शियल जोन में तबदील नहीं किया जाएगा और उसका एफ.सी.आर. नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक मैट्रो रेल का खर्च पूरा नहीं हो पाएगा । अतः माननीय मंत्री जी को वहां के लिए कोई पोलिसी तैयार करनी चाहिए । इसके बाद ही मैट्रो रेल वहां पर सफल हो पाएगी । वैसे चाहे मैट्रो रेल का सारे देश में विस्तार कर दें लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर माननीय सदस्य ने जितने भी सुझाव दिए हैं हम उन पर निश्चित रूप से विचार करेंगे । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि अगर वे इस तरह के सुझाव विभाग में आकर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ।

.....

To Open an Academic University at Nuh

***2882. Shri Zakir Hussain** : Will the Education Minister be pleased to state the steps taken by the Government to open an academic university at District Nuh?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

अध्यक्ष महोदय, चौधरी जाकिर हुसैन सदन के एक बहुत ही मौजिज सदस्य हैं और यह सौभाग्य की बात है कि इनकी 3 पीढ़ियां इस महान सदन की सदस्य रही हैं। इन्होंने नूँह में किसी विश्वविद्यालय के लिए प्रश्न पूछा है । गुरूग्राम जिले में और जिस क्षेत्र को माननीय सदस्य रिप्रैजेंट करते हैं वहां पर 11 प्राईवेट विश्वविद्यालय और 3 स्टेट गवर्नमैंट विश्वविद्यालय पहले से ही चल रहे हैं। पलवल जिले के दुधोला गांव में अभी कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया है और एम.वी.एन. विश्वविद्यालय पलवल जिले के औरंगाबाद गांव में है। जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद जिले में है। अल–फलाह विश्वविद्यालय, धोज में है और मानव रचना विश्वविद्यालय, फरीदाबाद जिले में है। इसके अतिरिक्त प्राईवेट विश्वविद्यालय नॉर्थ– कैंप सैक्टर 23, गुरूग्राम में है। अमेटी विश्विद्यालय गांव ग्वालियर, पचगांव मानेसर के नजदीक है। ए.पी.जे. सत्या विश्वविद्यालय (ए.एस.यू.) गांव सिलानी तहसील सोहना में है। अंसल विश्वविद्यालय सैक्टर 55, गुरूग्राम में है। श्री गुरू गोबिंद सिंह ट्राईसैंटनरी (एस.जी.टी.) विश्वविद्यालय गांव चंदू बुढ़ेड़ा में है। जी.डी. गोईंका विश्वविद्यालय सोहना रोड., गुरूग्राम में है। के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय सोहना रोड़ गुरूग्राम में है। बी.एम.एल. मुंजाल विश्वविद्यालय, गुरूग्राम में है। स्टारैक्स विश्वविद्यालय गांव बोहड़ा कलां में है। इसके अतिरिक्त गुरूग्राम में सरकारी विश्वविद्यालय भी है। आई.आई.एल.एम. विश्वविद्यालय, गुरूग्राम में है। मेवात राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेवात जिले में पहले से ही चल रहा है। मैं माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी से पूछना चाहूंगा कि वे कहां पर विश्वविद्यालय खुलवाने की रूचि रखते हैं ?

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी ने सारी बातें तस्दीक से रखी हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हरियाणा प्रदेश में कुल 55 यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें से 21 सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं। माननीय मंत्री जी ने गुरूग्राम जिले की जिन 13 यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया है

उनमें से 11 यूनिवर्सिटीज प्राईवेट हैं और बिनोला में 2 डिफैंस यूनिवर्सिटीज हैं। गुरूग्राम जिले में केवल एक सरकारी यूनिवर्सिटी है। पलवल जिले में कौशल विकास यूनिवर्सिटी है। मेरे पास हरियाणा प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। माननीय मंत्री जी मेवात जिले से भलीभांति परिचित हैं कि इन सभी यूनिवर्सिटीज में से फिरोजपुर–झिरका बॉर्डर तक 70–80 किलोमीटर से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सदन में बार–बार कहा जा रहा है कि यह इस सरकार का आखिरी बजट सैशन है। हमें सरकार से बड़ी भारी उम्मीद थी कि हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोली जाए। सरकार द्वारा माननीय सदस्यों की रिश्तेदारी के नाते से कामों को मंजूर किया जा रहा है, कहीं पर भाईचारे के नाते से कामों को मंजूर किया जा रहा है और कहीं पर पड़ोस का क्षेत्र होने के नाते से काम मंजूर किये जा रहे हैं। हमारे मेवात जिले से माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी का पुराना नाता है और उन्होंने खुद ही जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी का मंत्री जी से भाईयों वाला संबंध रहा है। हम भी माननीय मंत्री जी को अपने चाचा जी के तौर पर मानते हैं और माननीय मंत्री जी भी हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। कल मेरी बिटिया यहां पर आयी थी तो माननीय मंत्री जी ने उन्हें शगुन भी दिया था। हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। मेरे वालिद साहब और माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद जी के वालिद साहब चौधरी शकरूल्ला जी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे मेवात जिले के लिए एक यूनिवर्सिटी मंजूर हो जाएगी। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी मेवात जिले को पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने के कारण 115 जिलों में से स्पायरल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर चुना है। हमारे मेवात जिले के साथ एजूकेशन के मामले में पहले भी भेदभाव किया जाता था और आज भी भेदभाव किया जा रहा है। मेवात जिले में यूनिवर्सिटी बनाना आज वक्त की जरूरत है क्योंकि हम लड़कियों को पढ़ने के लिए 70–80 किलोमीटर दूर नहीं भेज सकते। इसके अतिरिक्त एक और बात में हमारे जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। चूंकि आज पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। हमारे देश के सभी लोगों ने शहीदों का मान–सम्मान किया है और अब भी कर रहे हैं। हमें शहीदों का सम्मान करना भी चाहिए। कुछ महीने पहले हमारे क्षेत्र के कुरथला गांव की बेटी लेफ्टिनैंट किरण शेखावत शहीद हो गयी थी। यह राजपूतों का बहुत बड़ा गांव है। पूरे देश ने

उस बेटी के शहीद होने का दुःख मनाया था। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री ने लेफ्टिनेंट किरण शेखावत के नाम से एक महिला राजकीय कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने लगभग सभी क्षेत्रों में कॉलेज बनवा दिये हैं परन्तु इस महान सदन में पिछले 3 सालों से महिला राजकीय कॉलेज बनाने की कोई चर्चा नहीं हुई है । अध्यक्ष महोदय, इन्होंने खुद माना है कि मेवात और पंचकुला जिले में पढ़ाई की कमी है । मेवात जिले के 34 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए दिनांक 18.6.2015 को पॉलिसी में रिलेक्सेशन किया गया लेकिन आज तक यह लिस्ट पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है। मैं इन स्कूलों की लिस्ट सदन के पटल पर रख दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन में यह बात नोटिस में लाना चाहता हूं कि आज हमारे नूंह जिले की जनता ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' के नारे से बहुत मायूस है क्योंकि हमारे जिले में यूनिवर्सिटी न होने की वजह से हमारी बेटियां और बेटे समाज में उन्नति नहीं कर रहे हैं । मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि अपने इस फैसले पर दोबारा से विचार करने का काम करें । अध्यक्ष महोदय, मैं नूंह जिले का विधायक होने के नाते से नहीं कह रहा हूं क्योंकि हर विधायक की अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष महोदय, मुझ पर मेवात का चौधरी होने के नाते से 36 बिरादरी की जिम्मेदारी बनती है । सरकार को जहां भी उचित लगे या मेवात जिले के सैंटर के आस पास यूनिवर्सिटी बनाने का कष्ट करें । आज हमें इस महान सदन के माध्यम से यूनिवर्सिटी बनाने का आश्वासन दें क्योंकि पूरे मेवात के लोगों की निगाह इस विधान सभा सत्र पर टिकी हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री राम बिलास शर्मा जी को कहना चाहता हूं कि मेवात में पांडव कालीन प्राचीन शिव मंदिर झिर बना हुआ है, उसका ध्यान करते हुए इस यूनिवर्सिटी की घोषणा करने की कृपा करें । हमें इन पर पूरा विश्वास है कि यूनिवर्सिटी बनाने का विचार जरूर करेंगे । आप हम से सच पूछो तो आज हमारा दिल खून के आंसू रोने को मजबूर है क्योंकि हम हनुमान जी नहीं है जो अपना दिल चीर कर दिखा सकें। हमें माननीय शिक्षा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है कि मेवात जिले में यूनिवर्सिटी बनाने के लिए हमारी इस जायज मांग को अवश्य ही पूरा करने का कष्ट करेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में हमारे मेवात जिले में बच्चे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे लड़के/लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने के

लिए दिल्ली की जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, कोटा राजस्थान, गुरूग्राम, रेवाड़ी और बैंग्लोर तक पढ़ाई करने के लिए दूर–दूर तक जाना पड़ता है। यह बहुत ही अफसोस की बात है कि मेवात जिले में एक भी यूनिवर्सिटी न होने के कारण हमारे जिले के लड़के/लड़कियों को पढ़ाई के लिए इधर–उधर भटकना पड़ रहा है । अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि ''पड़ोसी खाये दही, कैसे जाये सही'' । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पड़ोसियों को तो दही और मलाई खाने को मिल रही है और हमारे विधान सभा क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर–दूर तक भागना पड़ रहा है । जो हमारा बड़कली चौक है, उसे मेवात का गढ़ भी कहते हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा के नांगल गांव में 110 एकड़ जमीन यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को नांगल गांव की पंचायत ने रेजोल्यूशन भी दिया हुआ है और इसको लेकर मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड की मीटिंग भी हुई थी । हमने इस मीटिंग में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अनुरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, वहां पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है और हमने इसकी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी हुई है । आज इस महान सदन के माध्यम से मैं दोबारा से माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेवात की जनता और बच्चों का उद्धार करना है तो नांगल गांव में यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करने का कष्ट करें। आज मेवात जिले के लड़के–लड़कियां को पढ़ने के लिए चाहे वह राजस्थान हो, चाहे वह यू.पी. हो या हरियाणा के अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन है कि नांगल गांव में यूनिवर्सिटी बनाई जाये ताकि हमारे बच्चे भी पढ़–लिखकर समाज के अच्छे नागरिक बन सकें । हम इनका मान सम्मान तो पहले भी करते थे और आज भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि श्री राम बिलास शर्मा जी का धार्मिक स्थलों में बहुत गहरा विश्वास है। मैं मंत्री जी से विनती करता हूं कि हमारे फिरोजपूर–झिरका में शिव मंदिर बना हुआ है, उसके दर्शन करने के लिए आ जायें और इस बहाने से यूनिवर्सिटी का पत्थर लगाने के लिए आ आए जिससे मंदिर के दर्शन भी हो जायेंगे।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में शिक्षा के मामले में दो क्षेत्रों में क्रमशः एक मेवात और दूसरा मोरनी को

आगे बढ़ाने का काम किया है । हमारी सरकार ने इन साढ़े चार सालों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विशेष प्रावधान किये हैं । हमारी सरकार ने मेवात जिले के नूंह में 31 स्कूलों को आउट ऑफ वे जाकर अपग्रेड किये हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश में मिडल स्कूल को अपग्रेड करने के लिए 14 कमरों की आवश्यकता होती है। (विघ्न) मेवात जिले का मेवात डिवैल्पमैंट बोर्ड है, वह एक अलग संस्था है और वह एक मैडीकल कॉलेज चला रही है । (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, यह संस्था तो सिर्फ स्कूल ही चला रही है । (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से श्री जाकिर हुसैन जी और श्री नसीम अहमद जी को यह बताना चाहूंगा कि ये मेरी भावुकता का दुरूपयोग न करें। यह बात ठीक है कि ये मेरे भतीजा लोग हैं। इनके साथ मेरी पूरी ममता है और जितना सम्भव हो सकता है मैं इनकी प्रत्येक मांग को पूरी करने की कोशिश करता हूं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि साल्हाहेड़ी (नूंह) में कालेज चल रहा है उसमें 388 बच्चे हैं, गवर्नमैंट कालेज फॉर वुमैन, पुन्हाना में 208 बच्चे हैं। इसी तरह से गवर्नमैंट कॉलेज, नगीना में 1049 बच्चे हैं, हरद्वारी लाल गवर्नमैंट कॉलेज, तावडु में 484 बच्चे हैं और एडीशनल वाई.एम. डिग्री कॉलेज, नूंह में 720 बच्चे हैं। स्पीकर सर, मैं सदन के माध्यम से दोनों भाई लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि जैसे नांगल में इन्होंने 110 एकड़ जमीन की बात की है उसको ये जल्दी से जल्दी फाईनल करवायें। स्पीकर सर, मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु उस यूनिवर्सिटी को चलाना बड़ा कठिन काम है। पिछली सरकार द्वारा चुनाव के समय में जाते–जाते आनन–फानन में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ खोलने की घोषणा कर दी गई थी। दो–दो कमरों के अंदर यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई थी। जींद और भिवानी में यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा भी की गई थी। उस समय आई.टी.आई. के कमरे में केवल नाम के लिए यूनिवर्सिटीज़ खोल दी गई। स्पीकर सर, जो चुनाव का साल होता है यह बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें सरकारों द्वारा जाते–जाते बहुत सी घोषणायें कर दी जाती हैं। हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जो सिर्फ घोषणा करने के लिए ही घोषणा नहीं करती बल्कि जिस काम की घोषणा करती है उस काम को वास्तव में करती भी है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जिन कार्यों की घोषणा हो गई है उन्हें

हम अपनी सरकार के इसी कार्यकाल में पूर्ण करें और अगर कोई काम रह भी गया तो उसको हम अपनी सरकार के अगले कार्यकाल में पूर्ण कर देंगे क्योंकि यह बात तो तय है कि ये काम करने तो हमें ही हैं। स्पीकर सर, मैं जाकिर भाई और नसीम भाई को यह बात कहना चाहता हूं कि जो नांगल गांव की 110 एकड़ जमीन है ये उसका प्रस्ताव वहां की ग्राम पंचायत से या जो उस जमीन का मालिक हो उसकी तरफ से सरकार को जल्दी से जल्दी भिजवायें। मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार उस जमीन पर विश्वविद्यालय बनाने के बारे में जरूर विचार करेगी।

श्री जाकिर हुसैन : स्पीकर सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनकी सरकार ने बहुत से स्कूल्ज़ को अपग्रेड कर दिया है। सर, मैं यह लिस्ट प्लेस करता हूं। वर्ष 2015 में ये ऑर्डर हुए हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में रिलैक्सेशन के ऑर्डर किए थे लेकिन पिछले सवा चार साल निकल गए फिर भी अभी तक ये ऑर्डर लागू नहीं हुए हैं। मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर ये सभी स्कूल्ज़ 2015 में ही अपग्रेड हो जाते तो आज हमारे क्षेत्र का वास्तव में फायदा होता। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह कही कि बच्चे कॉलेजिज में अवेलेबल हैं। मेरा इस सम्बन्ध में यही कहना है कि कॉलेजिज के बच्चों को आगे पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी की जरूरत है। जहां पर अभी यूनिवर्सिटी सजैस्ट की गई है यह जो जमीन है इसका प्रस्ताव पहले ही सरकार के पास आया हुआ है। हम इस सम्बन्ध में प्रस्ताव फिर से सरकार के पास भिजवा देंगे। वहां पर यह यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी बनाई जाये क्योंकि वहां पर 50–50 किलोमीटर तक उच्च शिक्षा का कोई संस्थान नहीं है जहां पर हमारे क्षेत्र के कॉलेजिज में पढ़ने वाले बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्री राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, जब मेरे सामने यहां पर चौधरी जाकिर हुसैन जी खड़े होते हैं तो मुझे चौधरी तैयब हुसैन जी नज़र आते हैं और जब यहां पर नसीम अहमद जी खड़े होते हैं तो मुझे चौधरी शक्करूला याद आते हैं। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि शिक्षा विभाग में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने हमारी बेटियों के लिए 43 महाविद्यालयों को स्थापित करने की एकमुश्त घोषणा की थी जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है और 10 फरवरी, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक साथ 22 महाविद्यालयों की नींव भी रखी गई थी।

श्री तेजपाल सिंह तवरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सरकार ने नूंह जिले के कई स्कूलों को अपग्रेड किया है और मेरे विधान सभा क्षेत्र का कुछ एरिया नूंह जिले में भी पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 8 स्कूल पहले भी अपग्रेड हो चुके हैं लेकिन 10 स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिनमें बच्चों की पर्याप्त संख्या है और वे नार्म्स भी पूरे करते हैं लेकिन उनको अपग्रेड नहीं किया गया है। पिछले 40 सालों से वहां पर 5वीं तक के स्कूल हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भी अपग्रेड कर दिया जाये।

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि कुछ ही दिन पहले बीसर गांव में कॉलेज की स्थापना मैं करवाकर आया हूं और माननीय सदस्य को पगड़ी बंधवाकर लाया हूं। माननीय साथी मेरी भावुकता का फायदा उठा रहे हैं।

मीडिया प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के मीडिया प्रोद्योगिकी संस्थान के सहायक प्रोफैसर और विद्यार्थी सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका हार्दिक स्वागत करता है।

.....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर पुनरारम्भ

Scholarship to Scheduled Caste as Students

***3002. Shri Ravinder Singh Baliala :** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) The amount disbursed to students belonging to scheduled caste as scholarship in the schools of Haryana during the academic year 2018-19; and

(b) The number of students to whom the amount of scholarship has not been disbursed till to date ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : हां, श्रीमान् जी,

(क) शैक्षणिक सत्र 2018–19 के दौरान कक्षा पहली से बारहवीं तक हरियाणा के स्कूलों में अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों को छात्रवृति के रूप में लगभग 106 करोड़ 39 लाख की राशि वितरितकी गई है ।

(ख) कक्षा 1 से 12वीं तक में 345940 विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि वितरित नहीं की गई ।

11:00 बजे

श्री रविन्द्र बलियाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार का शुरू में जो विजन डॉक्यूमैंट था वह यह था कि 'सबका साथ, सबका विकास' और अन्तोदय । यानी जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है सबसे पहले सरकार उसका विकास करेगी और उसको सहायता देने का काम करेगी। हमें लगता है कि आज सरकार के ये दोनों ही वायदे खोखले साबित हुए हैं। हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति की सबसे ज्यादा जरूरत है । अनुसूचित जाति के ऐसे 3,45,940 विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक छात्रवृति नहीं मिली है और यह सैशन खत्म होने वाला है । इसको देखते हुए यह समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस तरह का विकास करेगी। सरकार का यह नारा कि 'सबका साथ, सबका विकास' कैसे सार्थक होगा? अध्यक्ष महोदय, जिन छात्रों को छात्रवृति की सबसे ज्यादा जरूरत है उनको छात्रवृति देने में सरकार को क्या दिक्कत है ? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी अन्त्योदय की परिभाषा क्या है ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को कब तक छात्रवृति बांटी जाएगी ?

श्री राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, **वी आर प्राउड ऑफ अवर परफॉरमैंस ।** पं. दीन दयाल उपाध्याय हमारे ऋषि पुरूष हुए हैं । उन्होंने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया था । माननीय विधायक श्री रविन्द्र बलिया जी ने पूछा है कि अन्तोदय का क्या अर्थ है? मैं उनको बताना चाहूंगा कि अन्तोदय का अर्थ है कि जो व्यक्ति अन्तिम पंक्ति में खड़ा है सरकार उसका भी विकास करेगी। विकास की दृष्टि से छप्पर वाले मकान में रहने वाला वह आदमी जो गांव में सबसे गरीब है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, जिसके पास इन्कम का कोई जरिया नहीं है, ऐसे आदमी को हमने अन्त्योदय की परिभाषा में शामिल किया था । सबसे पहले वर्ष 1967 में संविद सरकारें बनी थीं और पं. दीन दयाल उपाध्याय जी

के अन्तोदय के विचार के अनुसार श्रीमान भैरो सिंह शेखावत ने राजस्थान में और पण्डित शांता कुमार जी ने हिमाचल में अन्तोदय को लागू किया था । (शोर एवं व्यवधान) रविन्द्र जी, आप तो प्रोफेसर हैं । आपने अच्छी बात पूछी है मैं उसका जवाब तो भूमिका के साथ ही दूंगा । यह मेरा प्रिवलेज है । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जितना बड़ा सवाल पूछा है उतना बड़ा जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा । श्री रविन्द्र बलियाला जी ने बहुत उपयुक्त सवाल पूछा है । आज हमारी सरकार भी अन्तोदय की भावना के अनुरूप ही काम कर रही है । हमारी पार्टी की वर्ष 1967 से सरकारें बननी शुरू हुई थी । शांता कुमार जी ने अन्तोदय की भावना से पहाड़ों पर काम किया था । भैरो सिंह जी ने भी अन्तोदय की भावना से गांव में डी.ई.ओ., डी.सी., व बैंक मैनेजर उपलब्ध करवाकर भेड़–बकरी पालने वालों को तत्काल लोन वितरण करवाया था । आज हमारी सरकार भी उसी अन्त्योदय के ऊपर काम कर रही है । अब तक हमने अनुसूचित जाति के 28 लाख 55 हजार लाभान्वित विद्यार्थियों को 106 करोड़ रुपये छात्रवृति के रूप में बांटा है । अभी जो विद्यार्थी रह गये हैं वह इसलिए रह गये हैं क्योंकि हमने यह वितरण आधार कार्ड के आधार पर किया है और उनके आधार कार्ड में कोई कमी थी । मैंने स्वयं माना है कि 3 लाख 55 हजार छात्रों की छात्रवृति अभी पाईप लाईन में है । अध्यक्ष महोदय, हम जो भी काम करते हैं बड़े सिस्टेमैटिक्ली ढ़ंग से करते हैं । अब आगे आने वाले समय में हम उन सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति वितृत करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Four Lane Road

***2906. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the four lane road from Fatehabad to Hanspur road; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी, इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Registration of Houses

***2895. Shri Makhan Lal Singla :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether it is a fact that the houses allotted to the oustees family from village Thehar have not been registered on allottees name if so, the reason thereof.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : हां, श्रीमान जी, जिस भूमि से इनको निष्काषित किया गया है, वह भूमि आवास बोर्ड हरियाणा की नही है और इस बारे आवश्यक कार्यवाही अन्तर मन्त्रालय की चल रही विचार विमर्श के पूर्ण होने पर की जाएगी।

.....

Exemption from Toll Charges

***2912. Shri Om Parkash Barwa :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state - whether it is a fact that Toll charges have been collected from the residents of village Barwa on the Toll Plaza set-up near village Barwa on Hisar-Rajgarh road on NH-52; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to exempt the residents of village Barwa from paying toll charges on the above said Toll Plaza?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हां, श्रीमान् जी; ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

.....

Survey For BPL

***2872. Shri Jagbir Singh Malik** : Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state whether it is fact that B.P.L. survey has not been conducted by the present Government since its inception; if so, the time by which it is likely to be conducted?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हाँ, श्रीमान जी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ग्रामीण गरीब परिवार जोकि SECC-2011 के

स्वतः शामिल मापदंडों अथवा कोई भी तीन वंचित मापदण्डों के अन्तर्गत बी.पी.एल. सूची में सत्यापन के उपरान्त शामिल किया जायेगा। यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

.....

Shortage of Urea

***2877. Smt Kiran Chaudhry :** Will the Agriculture Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that there is acute shortage of Urea in State; and

(b) if so, the steps taken by the Government to meet out the shortage of Urea in State togetherwith the details thereof ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनकड़) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी, राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है।

.....

Exemption from Toll Charges

***2932. Shri Ravinder Machhrouli :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state -

(a) whether it is fact that toll charges are being collected from the local residents on the Toll Plaza of L&T installed on G.T. Road at Panipat; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to exempt local residents of Panipat from paying toll charges on the above said toll plaza?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Give Possession of Houses

***2924. Shri Lalit Nagar :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the Sharmik Vihar Colony has been developed in Tigaon Assembly Constituency in 1993 but the possession of the 725 houses of said colony have not given to the owners even after depositing the money in the Year 2007; and

(b) if so, the reasons thereof together with the time by which the possession of the above said houses is likely to be given to its owners alongwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

श्रीमान जी, कुल 725 आवेदकों में से 183 आवेदकों द्वारा 500/– रू. प्रति वर्ग गज की दर से राषि जमा करवा दी गई है। 153 आवेदकों ने कोई राषि जमा नहीं करवाई है। 52 आवेदकों ने भूखण्ड को अस्वीकार कर दिया। यह 388 (188+153+52) आवेदक दिंनाक 04.07.1993 को निकाली गई लाटरी उपरान्त सफल हुए थे। शेष 337 आवेदकों को टोकन दिया गया है। आबंटन पत्र केवल निम्नलिखित वॉछित दस्तावेज जमा होने पर जारी किया जाता हैः–

(i) वास्तविक निवासी होने बारे सबूत।

(ii) 10 वर्षों के भीतर ब्रिकी, उपहार, गिरवी या हस्तान्तरण न करने के सम्बन्ध में शपथ–पत्र।

(iii) इस आश्य का शपथ–पत्र कि उनके पास फरीदाबाद में कोई अन्य रिहायषी इकाई/मकान नहीं है।

यहां यह कहना उचित होगा कि 375 आवेदक पहले ही स्थान्तरित हो चुके हैं और श्रमिक विहार कालोनी में रह रहे हैं।

.....

Purchases from Ambala Central Co-Operative Consumer Store Ltd

***2959. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Animal Husbandry and Dairy Minister be pleased to state-

(a) The details of various items purchased by the Haryana Livestock Development Board from the Ambala Central Cooperative Consumer Store Ltd. during the year 2014-15 to 2016-17 on single quotation basis;

(b) whether it si a fact that the Ambala Central Cooperative Consumer Store Ltd. was an approved source declared by the State Government during the year 2014-15 to 2016-17; and

(c) If so, the action taken by the Government against the delinguent officers of Haryana Livestock Development Board for effecting purchase from unapproved source?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्रह ओमप्रकाश धनखड़) : महोदय इस बारे बयान सदन के पटल हेतू प्रस्तुत है ।

बयान

(क) हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान अम्बाला केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड से एकल निविदा आधार पर खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा अनुलग्नक ए पर है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी ।

(ग) मामला जांचाधीन है ।

अनुलग्नक (क)

~~Annexure - A~~

Statement showing details of the items purchased by Haryana Livestock Development Board from the Ambala Central Cooperative Consumer Store Ltd. from the year 2014-15 to 2016-17 on single quotation basis.

Sr. No.	Particular	Specification	Rate	Quantity	Amount	Service Charge	VAT	Total
Year 2014-15								
1.	Office Steel Chair High Back	Revolving Chair High back, PU foam with quality fabric cloth	7500 each	2	15000	0	1875	16875
2.	Office Steel Chair Medium Back	Revolving Chair Medium back, PU foam with quality fabric cloth	5200 each	37	192400	0	24050	216450
3.	Almirah Big	Almirah size 72"x36"x19". Door made of 22 gauge sheet, Body made of 24 gauge sheet Four shelves, Five compartments with proper locking facility	8800 each	51	448800	0	56100	504900
4.	Almirah Small	Almirah size 50"x30"x17". Door made of 22 gauge sheet, Body made of 24 gauge sheet Two shelves, Three compartments with proper locking facility	5600 each	34	190400	0	23800	214200
5.	Bench standard size	Bench standard size made of 22 gauge sheet 1.5" iron angle	5500 each	26	143000	0	17875	160875
		Total			**989600**	**0**	**123700**	**1113300**
Year 2015-16								
6.	Barbed wire	Barbed wire made of 3 layers of GI wire of 14	4.40 per running foot	6.32 Lac	2780800	0	139040	2919840

		gauge		feet				
7.	Bigger Size Coolers	Size 28.5" x 28.5" x 48" made of GP sheet 20 gauge, 4 sides made of angle iron and wiremesh 11gauge, 1" square and pad fitted. With cromton greaves exhaust fan 0.25 HP 18" and water lifting pump 18 watt made khaitan with ducting system with grill, duct size 0.63 mm thick made of GP sheet, stand made of angle iron 1.25" x 1.25" x 1.5" x 1.5"' height 30" approx. Aluminium partition work for duct purpose 20" x 17", electric fitting.	30500 per cooler	13	396500	0	19825	416325
8.	Normal Size Coolers	Size 26" x 26"x 35" made of GP sheet, 20 gauge, 3 sides made of wiremesh 11 gauge 1" and cooler kit make khaitan and khaitan pump.	8000 per cooler	6	48000	0	2400	50400
9.	Towel Turkish	Size 22"x44"	160 /- each	8300	1328000	66400	66400.	1460800
10.	Hand Duster	Size 20"x20"	20/- each	20,000	400000	20000	0	420000
11.	Hand Duster	Size 18"x18"	18/- each	12,000	216000	10800	0	226800
12.	Doctor Coat	Half sleeve white terri coat assorted size	335/- each	1914	641190	32059	32059	705308
13.	Apron	Plastic 48" length	105/- each	4600	483000	24150	24150	531300
14.	Sisal Rope	Size 18mm	105/- per Kg	9000 Kg	945000	47250	47250	1039500
15.	Gum Boots	PVC, Assorted Sizes	315/- each	3060	963900	48195	0	1012095
16.	Wheel barrow	Wheel barrow capacity 5 CFT body make of 16 gauge GP sheet properly welded and reinforced with MS round 10mm and 35 x 2mm with two	5200/- each	450	2340000	117000	292500	2749500

.		flat iron supports and the Bottom with 12" rubber wheels fitted ball bearings and coat paint and stencilled.						
17.	-DO-	Wheel Barrow capacity 2.5 CFT body made of 16 gauge GP sheet Properly welded and reinforced with MS round 10 mm and 20 x 5 mm with two flat iron supports and the Bottom with 12" rubber wheels fitted ball bearings and coat paint and stencilled.	3200/- each	370	1184000	59200	148000	1391200
18.	Waste Bin	Size 2' height made of GP sheet 24 gauge properly welded and proper open top facility with iron rod and inner side one iron perforated bucket for garbage.	1500/- each	1500	2250000	112500	281250	2643750
19.	Liquid hand wash	Liquid soap 500 ml Pack with dispenser	75/- each	26500	1987500	99375	99375	2186250
20.	Lubricating jelly	Paraffin Lubricating jelly 1 ltr. pack	350/- each	5770	2019500	100975	100975	2221450
21.	Animal registration (T-01)	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	9000	42/- Each	378000	18900	18900	415800
22.	Artificial Insemination, Pregnancy Diagnosis and Calving (T-02, T-03 and T-	Register size 8"x14"containing 100 leafs each of 4 colours Pink, Yellow, Green and white duly numbered. Single side single colour printing. Pucci Binding with Gutta.	6000	102/- Each	612000	30600	30600	673200

	04) as per sample							
23.	Milk Recording (T-05)	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	42/- Each	126000	6300	6300	138600
24.	Animal Re-registration (T-06)	Register size 8.5"x11.25" containing 50 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	32/- Each	96000	4800	4800	105600
25.	Animal Movement (T-07)	Register size 8.5"x11.25" containing 50 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	32/- Each	96000	4800	4800	105600
26.	Ear Tag Change (T-08)	Register size 8.5"x11.25" containing 50 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	32/- Each	96000	4800	4800	105600
27.	First Body Measurement of Female Calves(T-09)	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	42/- Each	126000	6300	6300	138600
28.	Subsequent Body Measurement of Female Calves(T-10)	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	42/- Each	126000	6300	6300	138600
29.	Milk recording Schedule (T-11)	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	6000	42/- Each	252000	12600	12600	277200

	Milk recording Card(T-12)	Card size 4"x7"120 gsm art card. Single colour both side printing.	500000	1.32/- Each	660000	33000	33000	726000
31.	Miscellaneous Services	Register size 8.5"x11.25" containing 100 leafs of 58gsm paper duly numbered. Single side single colour printing. Title 230 gsm. Pin Binding.	3000	42/- Each	126000	6300	6300	138600
32.	Fencing Concrete Poles	Fencing Concrete Pole width 4" X 4", length 8' of mix concrete ratio cement 1, crusher 3, bajri 3 with 4 iron bars of 6mm with 4 rings.	4080	635 each	2590800	129540	129540	2849880
		Total			**23268190**	**1002144**	**1517464**	**25787798**
		Grand Total			**24257790**	**1002144**	**1641164**	**26901098**
Year 2016-17		**No purchase was affected from The Ambala Central Cooperative Consumer Store Ltd.**						

Sewerage Line and Drinking Water Pipe line

***2913. Shri Mool Chand Sharma :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the time by which 50 years old sewerage line and drinking water pipe lines laid down in Ballabhgarh City are likely to be replaced?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमान जी, नगर निगम, फरीदाबाद ने बल्लभगढ़ शहर में पुरानी सीवर लाईन का पुनरूद्धार करने के लिए, राशि मु0 127.00 लाख रू0 के दो अनुमान पत्र स्वीकृत किए है।नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा इन कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की गई है जो कि 26.2.2019 को खोली जानी है, तथा इन कायों को 6 महीनों की अवधि में पूर्ण किया जाना संभावित है। बल्लभगढ़ शहर में स्थापित जलापूर्ति की लाईनें ठीक से काम कर रही है और इन लाईनों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

.....

Construction of Mini Secretariat in Kalayat

***2927. Shri Jai Parkash :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building of Mini Secretariat in Kalayat; if so, the time by which it is likely to be constructed?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : हां श्रीमान् जी, भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है तथा इसके पश्चात् भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Close Wool Procurement Centre

770. Shri Om Parkash Barwa : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to close the wool procurement centre established in Loharu Town; if so, the reasons thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : नहीं, श्रीमान जी।

To Regularize the Services of Sweepers

763. Smt. Kiran Chaudhary: Will the Development and Panchayat Minister be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the services and raise the pay of sweepers appointed in each village of the state; if so, the details thereof?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : महोदय, राज्य की ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । उनके वेतन के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है कि अभी हाल ही में दिनांक 01.02.2019 से सफाई कर्मचारियों का वेतन 10,000/– रूपये से बढ़ाकर 11,000/– रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है । उन्हें दिये जाने वाले वर्दी भत्ते को भी 2500/– रूपये से बढ़ाकर 3500/– रूपये प्रति वर्ष कर दिया गया है ।

.....

To Release the Tubewell Connections in Dark Zone

732. Shri Ravinder Machhrouli : Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the tubewell connections are likely to be released for the fields falling under the dark zone in the State?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, इस समय इस संदर्भ में कोई भी समय सीमा नहीं दी जा सकती क्योंकि केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के तहत 16.11.2015 से अधिसूचित क्षेत्रों/डार्क जोन में कोई भी कृषि टयूबवैल कुनैक्शन जारी नहीं किया जा सकता।

.....

Length of Approach Roads

748. Shri Karan Singh Dalal : Will the PW(B&R) Minister be pleased to state the constituency wise length of approach roads constructed by Public Works (B&R) Department from the year 2014-15 to 2018-19, togetherwith the amount spent on it?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, अपेक्षित जानकारी सदन के पटल पर रखी गई है।

जानकारी

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा निर्वाचनक्षेत्र वार निर्मित की गई पहुंच सड़कों की लम्बाई (कि0मी0 में)	वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान पहुंच सड़कों के निर्माण पर खर्च की गई राशि (लाखों में)
1	2	4	5
1	कालका	10.72	673.95
2	पंचकुला	-	-
3	नारायणगढ़	-	-
4	अम्बाला कैंट	7.10	404.09
5	अम्बाला सिटी	-	-
6	मुलाना	9.63	498.06
7	सढौरा	-	-
8	जगाधरी	7.35	1083.50
9	यमुनानगर	-	-
10	रादौर	-	-
11	लाड़वा	2.45	101.12
12	शाहबाद	-	-
13	थानेसर	-	-
14	पिहोवा	-	-
15	गुहला	11.74	535.74
16	कलायत	9.57	272.81
17	कैथल	9.86	1574.81
18	पुंडरी	1.01	38.08
19	नीलोखेड़ी	3.10	162.43
20	इंद्री	-	-
21	करनाल	6.30	4835.48
22	घरौंड़ा	1.60	85.85
23	असंध	3.76	133.88
24	पानीपत रूरल	-	-
25	पानीपत सिटी	-	-
26	इसराना	-	-
27	समालखा	3.18	94.22
28	गनौर	2.90	96.54
29	राई	-	-
30	खरखौदा	4.13	247.25
31	सोनीपत	5.60	4066.32
32	गोहाना	-	-
33	बरौदा	5.82	286.50
34	जुलाना	5.68	325.68
35	सफीदों	6.21	375.08
36	जींद	13.51	913.96
37	उचाना कलां	5.83	17.02
38	नरवाना	-	-
39	टोहाना	3.00	197.41
40	फतेहाबाद	-	-
41	रतिया	34.19	1197.86
42	कलांवाली	-	-
43	डबवाली	-	-

44	रानिया	-	-
45	सिरसा	-	-
46	ऐलनाबाद	-	-
47	आदमपुर	35.33	634.55
48	उकलाना	7.92	316.71
49	नारनौंद	14.43	782.37
50	हांसी	-	-
51	बरवाला	-	-
52	हिसार	2.22	522.83
53	नलवा	22.32	644.40
54	लौहारू	1.40	31.08
55	बाढडा	12.14	389.96
56	चरखी दादरी	4.20	279.00
57	भिवानी	2.37	395.93
58	तोशाम	-	-
59	बवानी खेड़ा	-	-
60	महम	8.74	503.96
61	गढ़ी सॉंपला किलोई	7.12	614.86
62	रोहतक	-	-
63	कलानौर	9.78	4673.71
64	बहादुरगढ़	7.50	722.55
65	बादली	8.65	875.20
66	झज्जर	2.67	180.89
67	बेरी	4.86	890.00
68	अटेली	6.44	268.90
69	महेंदगढ़	7.06	465.76
70	नारनौल	12.88	1803.57
71	नंगल चौधरी	23.64	1349.21
72	बावल	59.49	1727.62
73	कोसली	16.20	236.64
74	रेवाड़ी	18.47	766.04
75	पटौदी	15.29	1263.16
76	बादशाहपुर	9.80	3112.19
77	गुरूग्राम	-	-
78	सोहना	13.66	829.85
79	नूंह	4.56	437.08
80	फिरोज़पुर झिरका	-	-
81	पुनहाना	2.54	95.73
82	हथीन	10.60	208.86
83	हौडल	-	-
84	पलवल	3.99	73.22
85	पृथला	3.92	280.39
86	फरीदाबाद एन.आई.टी.	1.27	40.92
87	बडखल	-	-
88	बल्लबगढ़	-	-
89	फरीदाबाद	-	-
90	तिगॉंव	2.70	158.25
	कुल	**538.36**	**43793.03**

.....

Present Status of Widening of Road

767. Shri Parminder Singh Dhull : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state the present status of widening of the Rohtak-Jind-Narwana Highway togetherwith the time by which the above said Highway is likely to be widened?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान् जी, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग–71 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–352) के रोहतक–जीन्द भाग के चौड़ीकरण का कार्य रियायतकर्ता

और एन.एच.ए.आई. के बीच विवाद के कारण रूका हुआ है, इसलिए अभी कार्य पूरा होने की समय सीमा नहीं दी जा सकती। हालाँकि, राष्ट्रीय राजमार्ग–71 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग–352, 52) के जीन्द–नरवाना–पंजाब बोर्डर भाग के चौड़ीकरण का कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है।

.....

Amount Received by Municipal Committee

753. Shri Ved Narang: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the amount received by Municipal Committee Barwala from State Government during the financial year 2015-16 to 2018-19 togetherwith the details of development works executed in the above said period ?

शहरी स्थानीय निकाय (श्रीमती कविता जैन) : श्रीमानजी, नगरपालिका, बरवाला को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 तक प्राप्त राशि निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	योजना का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (12.02.2019rd)	कुल योग (राशि लाखोंमें)
1 (d)	रा. गा. श. वि. मि. ह. किस्त	602.18	671.00	773.00	357.77	2403.95
(Ik)	मुख्यमंत्री घोषणा	0.00	0.00	896.62	0.00	896.62
	कुलराषि रा. गा. श. वि. मि. ह.	**602.18**	**671.00**	**1669.62**	**357.77**	**3300.57**
2.	राज्य वित्तआयोग	91.90	100.46	104.01	79.99	376.36
3.	दीनदयालउपाध्याय सेवाबस्तीउत्थान	26.25	34.09	35.04	0.00	95.38
4.	14वां केन्द्रीय वित्तआयोग	63.07	125.38	180.24	0.00	368.69
5.	स्वच्छभारतमिशन	88.51	0.00	0.00	0.00	88.51
	कुल	**871.91**	**930.93**	**1988.91**	**437.76**	**4229.51**

नगरपालिका, बरवाला द्वारा निष्पादित किए गए विकास कार्यो का ब्यौरा पताका 'क' पर रखा गया है।

पताका–क

मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 13757 के तहत निष्पादित विकास कार्य–

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	काम के प्रकार	खर्चा(राशिलाखोंमें)
1	08,09,10,11	Streets and Drain	41.76
2	15,16,17,18	Streets and Drain	42.00

3	08,09,10	Streets and Drain	07.40
4	01	Shamshan Ghat	19.60
5	13,15,16,17	Streets and Drain	24.57
6	19	Streets and Drain	09.87
7	14	Streets and Drain	15.22
8	Various	Iron Grills on Main road,	51.24
		कुल	**211.66**

मुख्यमंत्री घोषणा के अलावा प्राप्त अनुदान राशि में से निष्पादित किए गए विकास कार्य–

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	काम के प्रकार	खर्चा (राशि लाखों में)
1	01	Construction of 12 no. Streets and Drain	38.24
2	02	Construction of 12 no. Streets and Drain	29.78
3	03	Construction of 10 no. Streets and Drain	42.45
4	04	Construction of 08 no. Streets and Drain	28.62
5	05	Construction of 08 no. Streets and Drain	29.01
6	06	Construction of 19 no. Streets and Drain	94.11
7	07	Construction of 04 no. Streets and Drain	13.01
8	08	Construction of 09 no. Streets and Drain	26.28
9	09	Construction of 04 no. Streets and Drain	09.16
10	10	Construction of 11 no. Streets and Drain	48.04
11	11	Construction of 08 no. Streets and Drain	32.91
12	12	Construction of 19 no. Streets and Drain	131.75
13	13	Construction of 03 no. Streets and Drain	14.64
14	14	Construction of 26 no. Streets and Drain	177.57
15	15	Construction of 07 no. Streets and Drain	21.88
16	16	Construction of 14 no. Streets and Drain	61.88
17	17	Construction of 11 no. Streets and Drain	34.93
18	18	Construction of 11 no. Streets and Drain	29.18
19	19	Construction of 09 no. Streets and Drain	30.87
20	Sign boards on Hansi road		2.65
21	Sign boards on Jind road		2.65
22	Sign boards on Agroha road		2.65
23	Sign boards of Municipal Committee and Ward Councilors		07.28
24	Construction / Repair of Nandishala		9.89
25	Footpath on NH 65/52		12.27
26	Construction / Repair of Nalla in W. no. 13		5.08
27	MC Barwala Drain		4.94
28	Construction of RavidassChaupal		63.78
29	Construction of JangraChaupal		54.00
30	Construction of KumaharChaupal		54.50
31	Construction of CFC Centre		4.72
32	Construction of Saini Chaupal		22.94
33	Repair of Pothole		04.78
34	Shop no. 56		04.32
35	RCC Bench		04.58
36	Street Light		09.91
37	Boundary Wall in W. 01		02.24
		कुल	**1167.49**

मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 13757 के अर्न्तगत प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों का विवरण–

क्रम संख्या	काम के नाम	खर्चा (राशि लाखों में)
1	Development work of Sursen Dharamshala	60.33
2	Const. of vibrating clored paver block street and drain DeshrajKiryana to Ram meharbhimsinghfouji via Pulla Ram in ward no 19	14.93
3	Const. of Nala along with Daultpur Road to Master Nihal Singh ward no 1	25.86
4	Const. of Park in ward no 10	65.00
5	Const. of vibrating clored paver block street and drain Rajender	30.78

	Kiryana to Master Jaibhagwan Dass ward no 02	
6	Const. of vibrating clored paver block street and drain Daulatpur Road to Via H/o Pankaj Badal Ward no 01	14.35
7	Construction of Shed, Waiting Hall and Street etc. in Shamshan Ghatt Tohana Road Ward No. 01, Barwala.	20.00
	कुल	**231.25**

मुख्यमंत्री घोषणाके अलावा प्राप्त अनुदान राशि से प्रगति पर चल रहे विकास कार्यों का विवरण–

कम संख्या	काम के नाम	अनुमानितलागत (राशिलाखोंमें)
1.	P/F of Iron Grill on Main Road Barwala	48.82
2.	Const. of Nala From RavidassChaupal To CBC School in ward no 06	24.00
3.	Const. of vibrating clored paver block street and drain H/o BalbirChahal to Bhaga Driver in ward no 07	45.04
4.	const. of ipb street from devendersoniki shop to kala, sajjanbalmiki wali gali, devi lalsoni to devi kumhar, rishi soni to nareshbalmiki, satbir to phol kumar balmiki and darshancornner to rameshfoji ward no. 1 barwala.	9.44
5.	const. of ipb street from subhashshuttring to jagdishgondali ward no. 1 barwala.	8.84
6.	const. of ipb street from pappujaat to bitushuttring ward no. 1 barwala.	9.22
7.	const. of ipb street from chunnicornner to rishi soni, partab to chanderbhan and jaggi toiler to manoj ward no. 1 barwala.	9.68
8.	const. of ipb street from kapura to dolatpur road ward no. 1 barwala.	8.87
9.	const. of ipb street from rishi soni to rampalbalmiki, dr. ram to prem, deepa to dolatpur road and rattan notha to dolatpur road ward no. 1 barwala.	8.13
10.	const. of ipb street from parkashhalwai to dr. mahipal ward no. 1 barwala.	9.19
11.	const. of ipb street from dr. mahipal to chowk ward no. 1 barwala.	9.19
12.	const. of ipb street from sandeepvalmiki to chowk ward no. 1 barwala.	8.67
13.	const. of ipb street from rameshwar to chanki and ishvar to bharat ward no. 1 barwala.	9.00
14.	const. of ipb street from dolatpur road to surenderbalmiki and shamsher to surenderbalmiki ward no. 1 barwala.	9.91
15.	const. of ipb street from harisunar to mahender ward no. 1 barwala.	1.60
16.	const. of ipb street from main road to dalkaur, main road to subhashmalik and omparkash to tarachand gosai in ward no. 2 barwala	9.92
17.	const. of ipb street from rajeshshokand to banboriraod and bekari to pardeepkathuria in ward no. 2 barwala	8.93
18.	const. of ipb street from gajesingh via shiv puri school to main road in ward no. 2 barwala	9.29
19.	const. of ipb street from devi lal park to kharkada road in ward no. 2 barwala	9.07
20.	const. of ipb street from banbori road to sannimandir in ward no. 2 barwala	7.96
21.	const. of ipb street from ram kumar to master shyamlal and main road to rutta in ward no. 2 barwala.	6.32
22.	const. of ipb street from kewaldeewan to pujara chowk via mahenderkaturia to rajenderarora and vijay to nihal electrical in ward no. 3 barwala	8.64
23.	const. of ipb street from aanadbuitik to kimtilal and hanuman mandir wali gali and kalu to dr. ved in ward no. 3 barwala	10.00
24.	const. of ipb street from amit to kuttia, amit to manoj, balimida to kamalmida and branch gali in ward no. 3 barwala	9.44
25.	const. of ipb street from dr. baldev to busting station ward no. 3 barwala	4.83

26.	const. of ipb street from sushil shop to sattibajaj ward no. 3 barwala	8.72
27.	const. of ipb street from sushil shop to mahender ward no. 3 barwala	8.31
28.	const. of ipb street from main road to sabji mandi wali gali and h/o rohtashsoni ward no. 3 barwala	7.25
29.	const. of ipb street from dr. subash wali gali, annahajare chowk and ramesh dish wali gali ward no. 3 barwala	9.19
30.	const. of ipb street from ram avtarsharma wali gali chowk and other streets ward no. 3 barwala	4.90
31.	const. of ipb street from dhana ram to mukesh and mata chowk to ramesh in ward no. 5 barwala	9.37
32.	const. of ipb street from mange ram to pappi, ramesh to mange ram and main road to rameswar in ward no. 5 barwala	8.07
33.	const. of ipb street from bharthu to chiranji, prithvi to baba and jai bhagwan to hawasingh in ward no. 5 barwala	9.98
34.	const. of ipb street from mange ram saini to babe in ward no. 5 barwala	14.82
35.	const. of ipb street from papi to main road in ward no. 5 barwala	8.43
36.	const. of ipb street from samat to darasaini and so to nagar khera in ward no. 5 barwala	8.63
37.	const. of ipb street from mange ram to rajeshsaini in ward no. 5 barwala	7.54
38.	const. of ipb street from h/o lilu to samat ward no. 5 barwala	8.50
39.	const. of ipb street from h/o kalapanjabi to subhash ward no. 5 barwala	8.05
40.	const. of ipb street from main road to chhatrawas in ward no. 5 barwala	4.78
41.	const. of ipb street from naiyo wali gali ward no. 5 barwala	4.89
42.	const. of ipb street from mukesh to main road in ward no. 5 barwala	3.83
43.	const. of ipb street from raj kumar ex. mc to dhoopsingh to rohtashsaini and raja pyara in ward no. 6 barwala	9.56
44.	const. of ipb street from rohtashsaini to satish kumar and raj kumar dalel to subhashbaddi in ward no. 6 barwala	9.39
45.	const. of ipb street from ravidas choupal to rajenderkriyana store in ward no. 6 barwala	9.92
46.	const. of ipb street from sadhu bhukal to banarsi and premmahender to jhandiwalakuaa in ward no. 6 barwala	6.17
47.	const. of ipb street from rajeshgharishyam to ram singh in ward no. 6 barwala.	14.77
48.	const. of ipb street from jaggachopra to sajjanbhukal ward no. 6 barwala	8.84
49.	const. of ipb streets bhiramistri to inderdhipu and kuaa to rajesh ward no. 6 barwala.	7.08
50.	const. of ipb street from dharambirjugati to ram singh in ward no. 6 barwala	8.34
51.	const. of ipb street from main road to pond and shankar ward no. 6 barwala.	4.85
52.	const. of ipb street from nirmla to papu shop and ghyan to ashok dairy ward no. 8 barwala	9.54
53.	const. of ipb street from mangat ram to ishwardayal and prem to h/o ex. mc pal ward no. 8 barwala	9.60
54.	const. of ipb street from satish kumar to shop of baljeet, satbir shop to parlad and prembhagat to jaipalnayak in ward no. 8 barwala	8.64
55.	const. of ipb street from rameshfoji to durgabhatt via main road, rajkali to rameharrana ward no. 8 barwala	9.13
56.	const. of ipb street from valmikikuaa to azad, ramkumar and tarsem to dalbir ward no. 8 barwala	9.65
57.	const. of ipb street from bhagwandass to shop of bittu and vikram to shop of ramesh ward no. 8 barwala	9.85

58.	const. of ipb street from surender to govt. school and valmikikuaawala chowk ward no. 8 barwala	9.86
59.	const. of ipb street from hanuman to rohtashjatt, vedakriyana to vikram and surender to master roopchand in ward no.8 barwala	9.82
60.	const. of ipb street from azad to gyan and anil to rameshfoji ward no. 8 barwala	8.39
61.	const. of ipb street from gurmelkaur to mehta was dev, kailash to nathuraheja in ward no. 9 barwala	5.47
62.	const. of ipb street from bharatdharamshala to sardargurubaksh and gorav to vikaspahwa ward no. 9 barwala	6.02
63.	const. of ipb street from mahenderpatwari to chc road, chc road to subesinghjangra in ward no. 10 barwala	9.94
64.	const. of ipb street from krishan master to sat satyanand school, master khakur to deshrajmistri in ward no. 10 barwala	9.11
65.	const. of ipb street from subesinghjangra to mani ram goyal to harji ram verma in ward no. 10 barwala	9.48
66.	const. of ipb street from harji ram verma to dharampal dairy in ward no. 10 barwala	5.17
67.	const. of ipb street from jai kishandingra to sarla madam in ward no. 10 barwala	5.77
68.	const. of ipb street from ashwani to hemraj in ward no. 10 barwala	6.85
69.	const. of ipb street from kathuria hospital to jainmandir in ward no. 10 barwala	8.36
70.	const. of ipb street from lohiyadharamshala to shyamkriyana store and ram lal to janta tailor in ward no. 11 barwala	8.45
71.	const. of ipb street from h/o sanjeevsingla to dharambirbajaj and pawansharma shop to barulohia and dr. amitraheja to h/o amitraheja in ward no. 11 barwala	5.52
72.	const. of ipb street from lohiyadharamshala to vedgrover and lohiadharamshala to aanganwari center in ward no. 11 barwala	9.45
73.	const. of ipb street from sanjay to radhakrishanmandir ward no. 11 barwala	7.84
74.	const. of ipb street from guru dawara to raju, pritamchanna to chaneki shop in ward no. 11 barwala	9.13
75.	const. of ipb street from durgamandir to mahendersetia ward no. 11 barwala	6.52
76.	const. of ipb street from suresh to chhajupansari, jaivir to manoj in ward no. 12 barwala	14.15
77.	const. of ipb street from shop of vikas to jagar and subhash to sushil in ward no. 12 barwala	8.80
78.	const. of ipb street from rameshsoni to satywan in ward no. 12 barwala	8.32
79.	const. of ipb street from rajesh data to mahendersingh and subhash to rajbir in ward no. 12 barwala	9.27
80.	const. of ipb street from baljit to hanuman and chandan to fool singh in ward no. 12 barwala	9.64
81.	const. of ipb street from sharma service station to bps school and jind road to hansi road in ward no. 12 barwala	9.25
82.	const. of ipb street from gargkriyana to vikas mobile kakar market in ward no. 12 barwala	9.67
83.	const. of ipb street from pawanchakki to sab ram in ward no. 12 barwala	13.77
84.	const. of ipb chowk from shamsan ghat near shiv puri school kharkara road mc barwala.	9.07
85.	const. of ipb street from rameshrajli to kali ram seth, papu to balbirsansi, balabhagat to nathu, sureshmittal to shiv kumar in ward no. 14 barwala	9.12
86.	const. of ipb street from sanjay to sajjanbhyanakhera,sanny to satishbabu in ward no. 14 barwala	10.00
87.	const. of ipb street from bharatseth to dr. mahender,ved ashram to ram savrup master in ward no. 14 barwala	9.42
88.	const. of ipb street from jai mata to lalu ward no. 14 barwala	10.91
89.	const. of ipb street from lalubihari to jaswantaara ward no. 14 barwala	12.25

90.	const. of ipb street from lalu to sambhu, ram savrup master to hisar road in ward no. 14 barwala	8.36
91.	const. of ipb street from jaswant to mahanseth ward no. 14 barwala	8.19
92.	const. of ipb street from kali ram to ranbirteli, balbirshansi to satish in ward no. 14 barwala	9.88
93.	const. of ipb street from chatersaishi to birbhanseth, birbhanseth to lakhmikumhar in ward no. 14 barwala	9.88
94.	const. of ipb street from lakhmikumhar to nafajatt, nafajatt to shambubihari in ward no. 14 barwala	9.88
95.	const. of ipb street from sharmaji to harpal,jaswant to danodewalasharma in ward no. 14 barwala	9.75
96.	const. of ipb street from nafesingh to sureshfoji, mohansaini to duffajatt in ward no. 14 barwala	10.00
97.	const. of ipb street from bhanaseth to karurajli in ward no. 14 barwala	9.00
98.	const. of ipb street from rakesh to ranbirteli, prince electronic to vishalgernal store in ward no. 14 barwala	9.48
99.	const. of ipb street from rohtashbaddi to raj kumar, kala to harpal and karurajli to suresh in ward no. 14 barwala	9.87
100.	const. of ipb street from suresh to birbhan in ward no. 14 barwala	6.78
101.	const. of ipb street from satbir gurana to bedukhedi in ward no. 14 barwala	7.57
102.	const. of ipb street from mandi gate to khera and khera to fci road in ward no. 15 barwala	12.90
103.	const. of ipb street from baljeetdahank to peer baba in ward no. 15 barwala	11.30
104.	const. of ipb street from ramphaldahank to ramniwas, mukesh to evadahank, manfooldahank to dalbirdahank, subhash to karambirdahank and ramniwas to goludahank in ward no. 15 barwala	9.47
105.	const. of ipb street from billo to subedhanak, ramdiya to ratan and infront of nagar khera in ward no. 15 barwala	7.71
106.	const. of ipb street from roshan to raghbirsoni in ward no. 15 barwala	11.30
107.	const. of ipb street from dalipsaini to dharampal in ward no. 15 barwala	12.69
108.	const. of ipb street from pal to prithvikumhar, deep chand to rajinderparsad, nunnasaini to narayan odd, dhansinghsaini to baghu ram and ghyanikumhar to ram singh in ward no. 18 barwala	9.13
109.	const. of ipb street from mani ram kumhar to badharsunar, dharambirsaini to badharsunar in ward no. 18 barwala	8.74
110.	const. of ipb street from chanderbhan to krishansaini in ward no. 18 barwala	8.76
111.	const. of ipb street from krishansaini to lilasaini and risalkumhar in ward no. 18 barwala	9.03
112.	const. of ipb street from khemchand to krishan in ward no. 18 barwala	3.49
113.	const. of ipb street from kala ram odd to dayanandkumhar and other side street in ward no. 18 barwala	7.71
114.	const. of ipb street from shamsan ghat near shiv puri school kharkara road mc barwala.	8.68
	कुल	**1088.93**

To Set Up Separate Boosting Station

729. Shri Balkaur Singh : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that an announcement was made by the Government on 25.08.2016 to set up separate boosting

station (mini water works) in ward No.2,3,4 at Kalanwali; if so, the time by which the said works are likely to be started?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : हां श्रीमान् जी, कालांवाली कस्बे के वार्ड न0 2, 3, 4 के लिए चौधरी देवी लाल पार्क मे अलग से बुस्टिंग स्टेशन (लघु जलघर) स्थापित करने के लिए सरकार की दिनांक 25.08.2016 की घोषणा के अनुसार पहले ही प्रशासिनिक मंजूर अनुमान 1271.00 लाख रुपये के तहत पूरा किया जा चुका है और वर्तमान में कार्यरत है।

.....

Pension For Small Farmers

739. Shri Pirthi Singh : Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start pension for the small farmers having less than 5 acres of land; if so, the details thereof ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हां श्रीमान जी, एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

.....

To Start Bus Service

771. Shri Ravinder Singh Baliala : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start the Bus Service from Ratia to Bhatinda (Punjab) via Pilchhiyan; if so, the time by which the above said Bus Service is likely to be started ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) :श्रीमान् जी, नहीं। रतिया से बठिण्डा (पंजाब) वाया पिलछियां बस सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Railway Line from Panipat to Palwal

758. Shri Zakir Hussain : Will the PW (B&R) Minister be please to state the total amount likely to be incurred an laying down the railway

line from Panipat to Palwal via Sohna together with the date on which the proposal of the said project had been made?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HRIDC) ने पलवल से पानीपत रेलवे लाइन (वाया सोहना, मानेसर होते हुए) "हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर" नाम की एक परियोजना विकसित की है, जिसकी लागत **4100** करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना असौटी को राठधाना से 130 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत दोहरी लाइन के द्वारा जोड़ेगी। परियोजना को शुरू करने के प्रस्ताव को नवंबर, 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

Construction of Rooms and Boundary Wall

762. Smt Kiran Choudhry : Will the Education Minister be pleased to state will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct 7 rooms and boundary wall of Government High School in village Dharwan Bass of Tosham Constituency; if so, the details thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी, तोशाम विधानसभा क्षेत्र के गांव धरवान बांस में राजकीय उच्च विद्यालय के 7 कमरें और चारदीवारी के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। विद्यालय में 85 विद्यार्थियो के लिये कमरें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

.....

To Stop Black Marketing of Liquor

733. Shri Ravinder Machhrouli : Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state the steps taken by the Government to stop black marketing of liquor in the State?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

"शराब की कालाबाजारी को रोकने हेतु"

हरियाणा सरकार की आबकारी नीति का उद्वेश्श्य शराब माफिया की मिलीभगत और अनैतिक वर्चस्व को तोड़ना, अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देकर व्यापार को व्यापक आधार देना, थोक विक्रेता को ही खुदरा लाईसैंस प्रदान कर थोक आपूर्ति को सरल बनाना, खुदरा

दूकानों के आबंटन में पारदर्शी प्रणाली की स्थापना करना, नकली शराब की निर्माण/बिक्री पर रोक लगाना, आबकारी कर की चोरी के प्रयासों को विफल करना, राजस्व का अनुकूलन करना, जायज और जिम्मेवारी से शराब पीने का माहौल प्रदान करना तथा अच्छे स्तर की शराब को उचित दरों पर उपलब्ध कराना है।

पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1)(aaa) उन व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने से सम्बन्धित है जो राज्य में अवैध शराब की पूर्ति व बिक्री करते है। इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से शराब को आयात, निर्यात, अपवाहन करता है या अपने पास रखता है, तो वह जुर्माना भरने के लिए उत्तरदायी होगा। 750 मिलीलीटर की बोतल पर कम से कम पचास रूपए तथा अधिकतम पांच सौ रूपए तक का जुर्माना लगाने में समाहर्ता सक्षम है बशर्ते कि यह केस समाहर्ता द्वारा न्यायालय न भेजा गया हो।

प्रत्येक जिले में तैनात आबकारी कर्मचारी/अधिकारी आकस्मिक तौर पर चैकिंग करते हैं ताकि मद्य–तस्करों द्वारा जिले व उनके गॉव में अवैध शराब की बिक्री न हो। इसके अतिरिक्त जब भी किसी व्यक्ति या किसी अन्य माध्यम के द्वारा अवैध शराब की बिक्री बारे शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तो उप आबकारी व कराधान आयुक्त के द्वारा टीम गठित करके चैकिंग करवाई जाती है।

हरियाणा राज्य में स्थित सभी आसवनी/बांटलिंग संयत्र को विभाग द्वारा तैयार किये गये मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा हर पखवाडे विस्तृत रूप से चैक किया जाता है। इसी तरह इनके गोदाम, शराब के थोक एंवम खुदरा विक्रेताओं को भी नियमित रूप से चैक किया जाता है ताकि शराब के अवैध संचलन को रोका जा सके। तदानुसार उंल्लगना के केस तैयार किये जाते हैं और अगर कोई कमी मिलती है तो नियमानुसार जुर्माना लगा दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त पुलिस एवम मुख्य मंत्री के उडनदस्ते के द्वारा भी आकस्मिक चैकिंग की जाती है और अगर पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की अवहेलना पाई जाती है तो उक्त द्वारा प्राथिमिकी दर्ज की जाती है। वर्ष 2018–2019 में मुख्य मंत्री उडनदस्ते द्वारा शराब के अवैध संचलन बारे कुल 10 प्राथिमिकी दर्ज की गई । इसी प्रकार बिना लाईसैंस शराब के अवैध उत्पादन मे लिप्त विभिन्न लोगो के खिलाफ इस वर्ष 4 प्राथिमिकि दर्ज की गई।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि वर्ष 2017–18 में अवैध शराब की 48247 पेंटियां पकडी गई और उन पर 6,67,85,750/–रूपए का जुर्माना लगाया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में जनवरी माह तक अवैध शराब की 51304 पेटियां पकड़ी गई और उन पर 5,55,54,170/– रूपए का जुर्माना लगाया गया।

अभी हाल में उत्तरी राज्यों के आबकारी आयुक्तों की एक बैठक भी आयोजित की गई थी जिसमे विभिन्न मुद्वों पर सहमति वयक्त की गई, जैसे कि आधुनिक तकनीक के प्रयोग से आसवनी/यवासवनी पर कडी निगरानी रखना ताकि सरकार के राजस्व की चोरी कम हो

सके, ऐसे तंत्र को तैयार करना जिसके तहत सम्बन्धित राज्यों द्वारा शराब के अवैध संचलन बारे वास्तविक काल की सुचना सांझी की जा सके तथा ऐसी सम्भावनायें तलाशना जिससे कि सभी पडोसी राज्यों मे शराब के दाम तुलनीय और संकीर्ण सीमा में रहे ताकि अन्तर–राज्जीय तस्करी को रोका जा सके ।

.....

Eligibility Criteria of BPL Families

749. Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of state for Food and Supplies Minister be pleased to state-

(a) the eligibility criteria for inclusion in the list of BPL families; and

(b) the district wise total numbers of SC, BC and general category BPL families as on 31.12.2018 ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़): श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर रखी है।

विवरणी

(क)

- **ग्रामीण क्षेत्र**

ग्रामीण क्षेत्रों में अन्तिम बी.पी.एल. सर्वेक्षण निम्न मापदण्डों के अनुसार 2007 में आयोजित किया गया :–

(क) भूमि (ख) मकान (ग) घरेलू उपकरणों की स्थिति (घ) शिक्षा स्तर (ड) आजीविका का साधन एवं रहन सहन का स्तर।

प्रत्येक मद को 0 से 10 अंक दिये गये थे तथा शिक्षा के मद को 0 से 5 अंक दिए गये थे। इन मापदण्डों के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर जिलावार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को बी.पी.एल. घोषित किया गया था।

सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना–2011

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना–2011 द्वारा हरियाणा राज्य में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। अन्तिम सूची का प्रकाशन सम्बन्धित जिला प्रशासन द्वारा सितम्बर, 2015 में किया गया था।

वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ग्रामीण गरीब परिवार जोकि SECC-2011 के स्वतः शामिल मापदंडों अथवा कोई भी तीन वंचित मापदण्डों के अर्न्तगत बी.पी.एल. सूची में सत्यापन के उपरान्त शामिल किया जायेगा। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है।

- **शहरी क्षेत्र**

शहरी गरीबों के उत्थान हेतु भारत सरकार की योजना नामतः "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" (SJSRY) योजना के अन्तर्गत योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड रूपये 443.21 प्रति सदस्य अनुसार शहरी क्षेत्रों के बी०पी०एल० परिवारों की पहचान हेतू सर्वेक्षण का कार्य वर्ष 2007 में पूर्ण किया गया तथा राज्य सरकार के निर्णय अनुसार इस सूची को अपडेट करने का कार्य वर्ष 2009 में पूरा किया गया था।

(ख)

- **<u>शहरी क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र</u>**

जिलावार अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व समान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों का ब्यौरा दिनांक 31.12.2018 के अनुसार अनुबंध–I व II पर सलंग्न है।

अनुबन्ध-I[57]

हरियाणा राज्य में बी.पी.एल. सूची (ग्रामीण क्षेत्र) का विवरण (दिनांक 31.12.2018 तक)

क्रं सं०	जिले का नाम	बी.पी.एल. सर्वेक्षण 2007 के अनुसार ग्रामीण बी.पी.एल. परिवारों की संख्या (दिनांक 31.12.2018 तक)				एस.ई.सी.सी. सर्वेक्षण 2011 के अनुसार ग्रामीण बी. पी.एल. परिवारों की संख्या (दिनांक 31.12.2018 तक)				अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	कुल जोड़
		अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	जोड़	अनुसूचित जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य वर्ग	जोड़				
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7	8	9	10 (7+8+9)	11	12	13	14 (11+12+13)
1	अम्बाला	24542	13465	4246	**42253**	11	15	8	**34**	24553	13480	4254	**42287**
2	भिवानी	22198	11297	9497	**42992**	1131	142	50	**1323**	23329	11439	9547	**44315**
3	चरखी दादरी	8965	4415	3354	**16734**	122	15	10	**147**	9087	4430	3364	**16881**
4	फरीदाबाद	4064	2672	3417	**10153**	137	40	10	**187**	4201	2712	3427	**10340**
5	फतेहाबाद	26971	11483	3635	**42089**	2092	348	1047	**3487**	29063	11831	4682	**45576**
6	गुरूग्राम	8636	5553	8022	**22211**	105	4	48	**157**	8741	5557	8070	**22368**
7	हिसार	34297	12160	5178	**51635**	535	140	61	**736**	34832	12300	5239	**52371**
8	झज्जर	13502	6595	4155	**24252**	34	0	0	**34**	13536	6595	4155	**24286**
9	जीन्द	29161	16289	6179	**51629**	273	11	2	**286**	29434	16300	6181	**51915**
10	कैथल	25498	17136	10098	**52732**	251	0	35	**286**	25749	17136	10133	**53018**
11	करनाल	23545	17318	5874	**46737**	1083	801	282	**2166**	24628	18119	6156	**48903**
12	कुरूक्षेत्र	16602	18146	3861	**38609**	486	191	152	**829**	17088	18337	4013	**39438**
13	नूह	6208	12597	17898	**36703**	170	445	168	**783**	6378	13042	18066	**37486**
14	महेन्द्रगढ़	19219	13657	5438	**38314**	162	98	57	**317**	19381	13755	5495	**38631**
15	पलवल	11011	9432	7772	**28215**	68	35	21	**124**	11079	9467	7793	**28339**
16	पंचकुला	2530	2646	1263	**6439**	142	9	10	**161**	2672	2655	1273	**6600**
17	पानीपत	15166	10212	5062	**30440**	6	0	0	**6**	15172	10212	5062	**30446**
18	रेवाड़ी	18476	9870	4609	**32955**	182	30	0	**212**	18658	9900	4609	**33167**

19	रोहतक	15176	6499	4573	**26248**	165	26	8	**199**	15341	6525	4581	**26447**
20	सिरसा	29765	12466	3402	**45633**	33	10	7	**50**	29798	12476	3409	**45683**
21	सोनीपत	18635	15415	6647	**40697**	229	67	30	**326**	18864	15482	6677	**41023**
22	यमुनानगर	20696	11736	4761	**37193**	25	10	23	**58**	20721	11746	4784	**37251**
	कुल जोड़	**394863**	**241059**	**128941**	**764863**	**7442**	**2437**	**2029**	**11908**	**402305**	**243496**	**130970**	**776771**

अनुबंध-II

राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा

क्रं सं०	जिले का नाम	शहरी बी.पी.एल. परिवार							शहरी बी.पी.एल. जनसंख्या						
		सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल बी.पी.एल.	सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		कुल बी.पी.एल.
		परिवार	प्रतिशत	परिवार	प्रतिशत	परिवार	प्रतिशत	परिवार	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या
1	अम्बाला	**11505**	**36.87**	**8803**	**28.21**	**10896**	**34.92**	**31204**	**42656**	**34.30**	**36822**	**29.61**	**44877**	**36.09**	**124355**
2	भिवानी	**12375**	**37.14**	**10352**	**31.07**	**10590**	**31.79**	**33317**	**49684**	**34.73**	**46585**	**32.56**	**46785**	**32.70**	**143054**
3	फरीदाबाद	**33006**	**50.28**	**15812**	**24.09**	**16832**	**25.64**	**65650**	**152284**	**47.98**	**80334**	**25.31**	**84771**	**26.71**	**317389**
4	फतेहाबाद	**4700**	**32.98**	**6546**	**45.94**	**3004**	**21.08**	**14250**	**18951**	**29.34**	**31579**	**48.90**	**14050**	**21.76**	**64580**
5	गुरूग्राम	**11853**	**49.64**	**6417**	**26.88**	**5606**	**23.48**	**23876**	**48879**	**49.20**	**27615**	**27.79**	**22859**	**23.01**	**99353**
6	हिसार	**12898**	**33.03**	**13892**	**35.58**	**12256**	**31.39**	**39046**	**53323**	**31.24**	**62272**	**36.49**	**55082**	**32.27**	**170677**
7	झज्जर	**5789**	**37.24**	**4676**	**30.08**	**5081**	**32.68**	**15546**	**26118**	**35.91**	**22481**	**30.91**	**24142**	**33.19**	**72741**
8	जीन्द	**7431**	**29.66**	**7447**	**29.72**	**10178**	**40.62**	**25056**	**30337**	**27.59**	**33781**	**30.73**	**45827**	**41.68**	**109945**
9	कैथल	**7261**	**29.89**	**7369**	**30.33**	**9664**	**39.78**	**24294**	**29002**	**27.23**	**33082**	**31.06**	**44431**	**41.71**	**106515**
10	करनाल	**13588**	**36.84**	**10229**	**27.74**	**13063**	**35.42**	**36880**	**54472**	**34.18**	**46704**	**29.31**	**58184**	**36.51**	**159360**
11	कुरूक्षेत्र	**4634**	**28.23**	**5082**	**30.96**	**6700**	**40.81**	**16416**	**18029**	**26.00**	**22451**	**32.37**	**28867**	**41.63**	**69347**
12	नारनौल	**1440**	**15.11**	**2213**	**23.22**	**5878**	**61.67**	**9531**	**5240**	**13.43**	**9188**	**23.55**	**24591**	**63.02**	**39019**
13	नूह	**2753**	**31.71**	**1822**	**20.99**	**4106**	**47.30**	**8681**	**12862**	**29.27**	**8879**	**20.20**	**22208**	**50.53**	**43949**

14	पंचकुला	**3498**	**26.54**	**4082**	**30.97**	**5601**	**42.49**	**13181**	**15432**	**25.41**	**19537**	**32.17**	**25755**	**42.41**	**60724**
15	पानीपत	**16205**	**38.23**	**18686**	**44.09**	**7492**	**17.68**	**42383**	**63868**	**36.00**	**81477**	**45.93**	**32056**	**18.07**	**177401**
7	रेवाड़ी	**4412**	**25.88**	**5113**	**30**	**7521**	**44.12**	**17046**	**17049**	**24.04**	**21721**	**30.63**	**32135**	**45.32**	**70905**
17	रोहतक	**9887**	**37.83**	**9231**	**35.32**	**7014**	**26.84**	**26132**	**37126**	**33.66**	**41853**	**37.95**	**31306**	**28.39**	**110285**
18	सिरसा	**12706**	**39.83**	**10404**	**32.62**	**8787**	**27.55**	**31897**	**49871**	**36.74**	**47633**	**35.09**	**38228**	**28.16**	**135732**
19	सोनीपत	**9002**	**30.33**	**9512**	**32.05**	**11167**	**37.62**	**29681**	**36355**	**27.23**	**44245**	**33.14**	**52917**	**39.63**	**133517**
20	यमुनानगर	**12244**	**41.96**	**5796**	**19.86**	**11141**	**38.18**	**29181**	**49167**	**39.65**	**26532**	**21.39**	**48315**	**38.96**	**124014**
21	पलवल	**6165**	**43.74**	**4356**	**30.9**	**3575**	**25.36**	**14096**	**27899**	**42.72**	**20252**	**31.01**	**17154**	**26.27**	**65305**
कुल जोड़		**203352**	**37.15**	**167840**	**30.66**	**176152**	**32.18**	**547344**	**838604**	**34.97**	**765023**	**31.90**	**794540**	**33.13**	**2398167**

Total Number of deaths in Road Accidents

766. Shri Parminder Singh Dhull : Will the Chief Minister be pleased to state the district wise total number of deaths occurred in road accidents in State during the tenure of present Government ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, जिलावार विवरण निम्नलिखित है–

विवरण

जिला	सड़क दुर्घटनाओं में मौतों की संख्या					
	2014 (अक्टूबर से दिसंबर)	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019 (जनवरी 2019)**
अंबाला	54	258	301	243	262	19
पंचकुला	22	96	101	95	105	8
यमुनानगर	60	229	220	290	284	17
कुरुक्षेत्र	48	272	234	245	258	18
कैथल	44	161	170	169	165	9
करनाल	88	318	390	382	353	28
पानीपत	76	271	292	303	261	26
सोनीपत	104	401	425	378	432	36
रोहतक	59	213	241	250	210	23
झज्जर	68	293	255	263	267	29
हिसार	64	263	253	199	152	7
हांसी	-	-	-	54	74	5
फतेहाबाद	23	104	110	109	131	13
सिरसा	33	148	118	110	120	7
भिवानी	76	238	249	155	171	15
चरखी दादरी	-	-	-	55	98	7
जींद	42	174	190	191	202	14
गुरुग्राम	112	435	415	421	446	49
फरीदाबाद	56	206	195	225	235	17
पलवल	47	210	205	227	211	30
रेवाड़ी	66	265	274	284	277	19
नारनौल	45	178	199	236	190	15
मेवात	33	146	187	236	214	18
कुल	**1220**	**4879**	**5024**	**5120**	**5118**	**429**

Construction of Road

736. Shri Ved Narang : Will the PW(B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Rajli to village Khanpur Sindhar of Barwala Constituency; if so, the details thereof?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : हाँ, श्रीमान् जी, सरकार द्वारा इस सड़क के निर्माण के लिए 262.02 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति नवम्बर, 2018 के दौरान दी जा चुकी है। निविदाएँ प्रक्रिया में हैं।

.....

Vacant Post of Lecturers and Teachers

740. Shri Pirthi Singh: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that many posts of school lecturer and teachers in Government Senior Secondary School, Kalwan are lying vacant; and

(b) if so, the time by which above said posts are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान्, नरवाना विधानसभा श्रेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कालवान मे अध्यापकों की रिक्तियों का वर्णन निम्नानुसार है–

वर्णन

क्रमांक संख्या	विषय	रिक्त पद
1.	स्नातकोत्तर अध्यापक गणित	1
2.	स्नातकोत्तर अध्यापक संस्कृत	1
3.	स्नातकोत्तर अध्यापक भौतिक विज्ञान	1
4.	स्नातकोत्तर अध्यापक कम्प्यूटर सांईस	1
5.	प्राथमिक मुख्याध्यापक	1

नयी सीधी भर्ती और पदोन्नति के बाद अध्यापकों द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार रिक्तियों को भरने का प्रयास किया जाएगा।

.....

To Metal the Unmetalled Passage

769. Shri Ravinder Singh Baliala : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to metal the unmetalled passage from Village Bhirdana to Village Chandrawal; if so, the time by which the said passage is likely to be metalled?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी, इस समय जिला फतेहबाद के गाँव भिंडराणा से गाँव चंद्रावल तक की सड़क को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Details of Universities

757. Shri Zakir Hussain : Will the Education Minister be pleased to state the district wise details of the universities established in Haryana?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : श्रीमान् जी, कथन सदन के पटल पर रखा गया है।

कथन

श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य में स्थापित जिलावार् राज्य, केन्द्रीय, निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक न0	विश्वविद्यालय का नाम	विश्वविद्यालय का प्रकार
अम्बाला		
1	एम0एम0 विश्वविद्यालय, मुलाना।	डीम्ड विश्वविद्यालय
2	महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय, सदोपुर।	निजी विश्वविद्यालय
भिवानी		
1	चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी।	राजकीय विश्वविद्यालय
फरीदाबाद		
1	जे0सी0बोस0 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद।	राजकीय विश्वविद्यालय
2	लिंग्याज विश्वविद्यालय, नचौली, पुराना फरीदाबाद, जसाना रोड, फरीदाबाद।	डीम्ड विश्वविद्यालय
3	मानव रचना इन्टरनैशनल विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	डीम्ड विश्वविद्यालय
4	अल्–फलाह विश्वविद्यालय, धौज, फरीदाबाद।	निजी विश्वविद्यालय
5	मानव रचना विश्वविद्यालय, सैक्टर–43, अरावली हिल्स, दिल्ली– सुरजकुण्ड रोड़, फरीदाबाद–121004	निजी विश्वविद्यालय
गुरूग्राम		
1	गुरूग्राम विश्वविद्यालय, गुरूग्राम।	राजकीय विश्वविद्यालय
2	इन्डियन नैशनल डिफैन्स विश्वविद्यालय, बिनौला, गुरूग्राम।	राजकीय विश्वविद्यालय
3	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, मानेसर, गुरूग्राम।	डीम्ड विश्वविद्यालय

4	नार्थकैप (पूर्व आई0टी0एम0) विश्वविद्यालय, सैक्टर 23–ए, गुरूग्राम।	निजी विश्वविद्यालय
5	एमिटि विश्वविद्यालय, गांव–ग्वालियर, पंचगांव (नजदीक मानेसर), जिला गुरूग्राम (हरियाणा)।	निजी विश्वविद्यालय
6	ए0पी0जे0 सत्या विश्वविद्यालय, गांव–सिलानी, तहसील सोहना, पलवल रोड, जिला गुरूग्राम–122103	निजी विश्वविद्यालय
7	अंसल विश्वविद्यालय, सैक्टर–55, गुरूग्राम हरियाणा	निजी विश्वविद्यालय
8	श्री गुरू गोबिन्द सिंह ट्राइसेन्टनेरी, (एस0जी0टी0) विश्वविद्यालय गांव चंदु बुढेरा, जिला गुरूग्राम–122505	निजी विश्वविद्यालय
9	जी0डी0 गोयन्का विश्वविद्यालय, सोहना रोड, गुरूग्राम, (दिल्ली एन0सी0आर0) 122103	निजी विश्वविद्यालय
10	के0आर0 मंगलम् विश्वविद्यालय, सोहना रोड़, गुरूग्राम–122103	निजी विश्वविद्यालय
11	बी0एम0एल मुंजाल विश्वविद्यालय, 67 किमी0 स्टोन गांव सिधरावली एन0एच0–8, गुरूग्राम–122413	निजी विश्वविद्यालय
12	स्टारैक्स विश्वविद्यालय, ग्राम बिनौला, तहसील मानेसर, जिला गुरूग्राम	निजी विश्वविद्यालय
13	आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय, 1 नोलेज सैन्टर, गोल्फ कोर्स रोड, सैक्टर 53, गुरूग्राम।	निजी विश्वविद्यालय
हिसार		
1	चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	राजकीय विश्वविद्यालय
2	गुरू जम्भेश्वर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (जी0जे0यू0एस0टी0), हिसार।	राजकीय विश्वविद्यालय
3	लाला लाजपतराय पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार।	राजकीय विश्वविद्यालय
झज्जर		
1	जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़।	निजी विश्वविद्यालय
2	पी0डी0एम0 विश्वविद्यालय, बहादुरगढ़	निजी विश्वविद्यालय
जीदं		
1	चौ0 रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।	राजकीय विश्वविद्यालय
कैथल		
1	महर्षि बाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय, मुन्दड़ी कैथल।	राजकीय विश्वविद्यालय
2	एन0आई0आई0एल0एम0 विश्वविद्यालय, 9 के0एम0 माईलस्टोन, मेन एन0एच0 65, कैथल, हरियाणा–136027	निजी विश्वविद्यालय
करनाल		
1	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	डीम्ड विश्वविद्यालय
2	महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, अंजनथली, करनाल	राजकीय विश्वविद्यालय
3	पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, करनाल	राजकीय विश्वविद्यालय
कुरूक्षेत्र		
1	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।	राजकीय विश्वविद्यालय
2	नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, (एन0आई0टी0 कुरूक्षेत्र), कुरूक्षेत्र।	डीम्ड विश्वविद्यालय
3	श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र।	राजकीय विश्वविद्यालय
महेन्द्रगढ		

1	हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांव जांट पाली, महेन्द्रगढ।	केन्द्रीय विश्वविद्यालय
पलवल		
1	एम0वी0एन0 विश्वविद्यालय, 74 कि0मी0 स्टोन, एन0एच0– 2, दिल्ली आगरा हाईवे, तहसील होडल, गांव औरंगाबाद, पलवल, हरियाणा–121105	निजी विश्वविद्यालय
2	श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, दुधोला पलवल।	राजकीय विश्वविद्यालय
रेवाड़ी		
1	इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर	राजकीय विश्वविद्यालय
रोहतक		
1	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।	राजकीय विश्वविद्यालय
2	पंडित बी0डी0 शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (बी0डी0एस0यू0एच0एस0), रोहतक।	राजकीय विश्वविद्यालय
3	भारतीय प्रबन्धन संस्थान, (आई0आई0एम0) रोहतक।	डीम्ड विश्वविद्यालय
4	राज्य प्रदर्शन एवं द्वश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक	राजकीय विश्वविद्यालय
5	आई0सी0ए0आर0 केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, लाहली, रोहतक।	डीम्ड विश्वविद्यालय
6	बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक, हरियाणा।	निजी विश्वविद्यालय
सोनीपत		
1	दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय, मुरथल	राजकीय विश्वविद्यालय
2	डा0 बी0आर0 अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आर0जी0ई0सी0, सोनीपत।	राजकीय विश्वविद्यालय
3	भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां,	राजकीय विश्वविद्यालय
4	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता व प्रबंधन संस्थान, (एन0आई0एफ0टी0ई0एम0), सोनीपत	डीम्ड विश्वविद्यालय
5	एस0आर0एम0 विश्वविद्यालय, प्लॉट न0 39, आर0जी0ई0सी0, डा0 राई, दिल्ली एन0सी0आर0, सोनीपत (हरियाणा)–131029	निजी विश्वविद्यालय
6	अशोका विश्वविद्यालय, प्लॉट न0 #2, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, एन0सी0आर0 डा0 राई, सोनीपत 131029	निजी विश्वविद्यालय
7	विश्व डिजाइन विश्वविद्यालय, प्लॉट न0 1, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, राई, सोनीपत।	निजी विश्वविद्यालय
8	ओ0 पी0 जिन्दल ग्लोबल विश्वविद्यालय, गांव जगदीशपुर, सोनीपत।	निजी विश्वविद्यालय
सिरसा		
1	चौधरी देवी लाल विश्वद्यिालय, सिरसा।	राजकीय विश्वविद्यालय

.....

Length of Approach Roads

750. Shri Karan Singh Dalal : Will the Agriculture Minister be pleased to state the constituency wise length of approach roads constructed by the Marketing Board from the year 2014-15 to 2018-19 ?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान् जी, ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ब्यौरा

वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक विपणन मण्डल द्वारा निर्वाचनक्षेत्र–वार निर्मित की गई पहुंच सड़कों की लम्बाई

क्रमांक संख्या	विधान सभा क्षेत्र	सड़कों की संख्या	लम्बाई (कि0 मी0 में)	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि (लाख रूपये में)
1	आदमपुर	10	38.26	1178.05
2	अम्बाला छावनी	1	3.41	108.48
3	अम्बाला शहर	7	14.35	358.93
4	असन्ध	10	36.72	1332.20
5	अटेली	12	32.65	903.91
6	बाढ़ड़ा	7	20.33	614.93
7	बड़खल	-	-	-
8	बादली	29	79.20	3397.29
9	बादशाहपुर	2	7.22	247.07
10	बंहादुरगढ़	2	4.39	129.36
11	बल्लभगढ	-	-	-
12	बडौदा	18	64.84	1826.52
13	बरवाला	10	27.81	1021.69
14	बावल (SC)	5	7.96	246.93
15	बवानी खेडा (SC)	9	34.17	977.34
16	बेरी	8	28.35	882.70
17	भिवानी	4	9.14	259.84
18	डबवाली	28	125.94	4245.09
19	दादरी	4	15.02	505.04
20	ऐलनाबाद	8	30.45	901.80
21	फरीदाबाद	-	-	-
22	फरीदाबाद NIT	3	3.83	114.82
23	फतेहाबाद	5	15.85	488.66
24	फिरोजपुर झिरका	6	11.92	313.33
25	गन्नौर	8	20.87	765.55
26	गढी सापंला – किलोई	3	6.34	206.45
27	घरौंडा	9	17.32	556.30
28	गोहाना	13	45.89	1395.52
29	गुहला (SC)	11	26.18	909.74
30	गुरूग्राम	2	4.19	140.33
31	हांसी	3	7.12	214.46
32	हथीन	8	18.40	597.93
33	हिसार	2	7.51	301.46
34	होडल (SC)	3	9.60	303.43
35	इन्द्री	16	35.69	947.73
36	इसराना (SC)	17	60.48	1818.22
37	जगाधरी	3	3.22	134.11
38	झज्जर (SC)	12	32.51	896.41
39	जीन्द	9	30.85	1009.53
40	जुलाना	8	35.30	1146.00
41	कैथल	3	8.45	327.04
42	कलानौर (SC)	6	22.22	777.96
43	कालांवाली (SC)	3	5.66	180.73
44	कलायत	17	48.15	2216.21
45	कालका	-	-	-

46	करनाल	2	4.06	147.79
47	खरखौदा (SC)	9	19.16	587.57
48	कोसली	25	70.38	2161.26
49	लाडवा	4	8.41	287.05
50	लोहारू	9	33.85	965.07
51	महेन्द्रगढ़	2	8.39	217.07
52	महम	2	6.68	199.36
53	मुलाना (SC)	11	17.87	575.18
54	नलवा	10	37.59	1042.85
55	नागंल चौधरी	14	35.45	1054.27
56	नारायणगढ़	7	12.25	336.45
57	नारनौल	8	24.50	800.25
58	नारनौन्द	9	39.98	1151.68
59	नरवाना (SC)	9	34.73	1309.60
60	नीलोखेड़ी (SC)	7	10.17	387.17
61	नुंह	22	52.95	2058.51
62	पलवल	12	27.96	835.59
63	पंचकुला	3	6.82	113.13
64	पानीपत शहर	-	-	-
65	पानीपत ग्रामीण	3	3.47	115.99
66	पटौदी (SC)	3	9.88	373.76
67	पेहवा	8	21.11	831.11
68	पृथला	3	11.26	410.70
69	पुंडरी	6	23.38	853.48
70	पुन्हाना	21	40.16	1247.83
71	रादौर	10	17.12	568.62
72	राई	29	57.17	2042.74
73	रानिया	5	18.22	551.49
74	रतिया (SC)	12	31.65	1252.52
75	रेवाडी	-	-	-
76	रोहतक	-	-	-
77	साढ़ौरा (SC)	4	11.38	400.84
78	सफीदों	25	59.60	2393.06
79	समालखा	19	44.64	1831.89
80	शाहबाद (SC)	14	26.23	796.19
81	सिरसा	3	12.70	362.85
82	सोहना	1	1.56	45.76
83	सोनीपत	-	-	-
84	थानेसर	6	11.90	353.90
85	तिगांवा	3	6.44	223.61
86	टोहाना	15	41.82	1387.37
87	तोशाम	11	39.27	937.99
88	उचाना कलां	11	65.83	2354.04
89	उकलाना (SC)	16	72.28	2151.88
90	यमुनानगर	-	-	-
	Total	**737**	**2135.92**	**70616.56**

To Desilt the Rivulets and Sub-Minors

752. Shri Ved Narang : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to

desilt the rivulets and sub-miners falling under Barwala Assembly Constituency; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, छोटी नदियों (नालों) से गाद निकालने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है । परन्तु, सब माईनरों से गाद निकालने का कार्य वर्ष 2019 के मई/जून महीनों के दौरान किया जाएगा । इससे पहले वर्ष 2018 के दौरान, कुल 70.59 लाख रू0 की लागत से बरवाला निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले लगभग 159 किलोमीटर लम्बाई के चैनलों की गाद निकालने का कार्य मई–जून, 2018 तथा अक्तूबर–नवम्बर, 2018 के दौरान किया गया था।

.....

Upgradation of School

7**41. Shri Pirthi Singh** : Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the Government Girls High School of village Ujhana of Narwana Constituency upto Government Girls Senior Secondary School; if so, the time by which above said school is likely to be upgraded?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :जी हां, श्रीमान्। इस विद्यालय का स्तरोन्नति मामला विचाराधीन है।

.....

Construction of Under Pass

742. Shri Prithi Singh : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an Under Pass on the railway crossing on the Narwana to Samain road; if so, the time by which the said Under Pass is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (श्री नरबीर सिंह) : श्रीमान जी, लेवल क्रोसिंग नं0 139 पर आरओबी (उपरगामी पुल) के निर्माण का प्रस्ताव है और इसकी जीएडी अन्तिम निरीक्षण के बाद रेलवे को अनुमोदन हेतु भेजी जा चुकी है।

.....

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला शहर में कुछ साल पहले वाटिका सिटी सैंटर के नाम से एक रेजिडेंशियल–कम–कमर्शियल टाउनशिप आई थी जिसमें किसानों को सैक्शन–4 के तहत नोटिस दिए गए जबकि उस जमीन का अधिग्रहण अलास्का कंपनी ने किया था। पिछली सरकार के समय में जब अम्बाला में यह टाउनशिप कटी थी तो तत्कालीन सरकार ने किसानों को डरा–धमकाकर जबरदस्ती के साथ किसानों की जमीन का अधिग्रहण करवाया था । इस मामले की जांच सी. बी.आई. से करवाने के बारे में मैंने एक कालिंग अटैंशन नोटिस दिया हुआ है। मुझे उसका फेट बताया जाये?

श्री अध्यक्ष : असीम जी, आपका कालिंग अटैंशन नोटिस अभी विचाराधीन है।

श्री असीम गोयल : धन्यवाद सर ।

श्री करण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, पलवल, हथीन व पृथला विधान सभा क्षेत्र में भवंडर की वजह से उजड़े गांवों के बारे में मैंने कालिंग अटैंशन नोटिस दिया था। इन गांवों में जनधन के साथ पशुधन की भी बहुत हानि हुई है और काफी लोगों को चोटें भी लगी हैं। लोगों के घरों से छतें तक उड़ गई हैं लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से इन प्रभावित लोगों की कोई सुध नहीं ली गई है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने, डॉ रघुवीर सिंह कादियान जी और हमारी कांग्रेस पार्टी के आठ–दस अन्य सदस्यों द्वारा हरियाणा प्रदेश में बिजली पानी के लिए जगह–जगह धरने प्रदर्शन पर बैठे किसानों की समस्याओं पर कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए हैं। अध्यक्ष महोदय, झज्जर के छारा गांव में किसान धरने पर बैठे हैं। मेरे इलाके में भी किसान मुआवजा न मिलने की वजह से धरने पर बैठे हुए हैं। किसान बहुत दुखी व परेशान हैं। उनके खेतों से आज तक फ्लड का पानी तक नहीं निकला है। इन तमाम विषयों पर जो कालिंग अटैंशन नोटिसिज दिए गए हैं, हमें उनका फेट बताया जाये क्योंकि अभी तक हमें इनका कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इन कालिंग अटैंशन नोटिसिज को स्वीकार करते हुए सदन में चर्चा करने की इजाजत दें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, छारा गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। इस विषय पर हमने कालिंग अटैंशन नोटिस दिया हुआ है। इन किसानों के साथ मुआवजे पर डिस्क्रिमिनेशन हुई है। छारा गांव के लोगों को 40 लाख रूपये मुआवजा दिया गया है जबकि साथ लगते एक अन्य गांव में 1 करोड़ 30 लाख

रूपये का मुआवजा दिया गया है। इस विषय पर हमने आपको कालिंग अटैंशन मोशन दिया था और आपने कहा था कि आपने इसको कमेंट्स के लिए भेजा है। मुझे इसका फेट बताया जाये।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपका यह कालिंग अटैंशन नोटिस अभी लंबित है क्योंकि इसको सरकार के पास कमेंट्स के लिए भेज दिया गया है ।

विभिन्न मामले उठाना

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, माण्डी खेड़ा, नूंह में हैल्थ विभाग का डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है । वहां पर पिछले 17 दिन से एन.एच.एम. कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वहां 72 घण्टे से 7 लोग भूख हड़ताल पर भी हैं जिनमें से दो बहनों की और एक भाई की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है । वे बिल्कुल खतरे में हैं। इसके बावजूद भी सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है । यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार उनके प्रति इतनी संवेदनहीन है । सी.एम.ओ. भी वहीं बैठते हैं लेकिन उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा है, न उनकी कोई सुध ले रहा है। प्रशासन की तरफ से भी उनसे मिलने कोई नहीं गया है। आज उन सात लोगों को भूख हड़ताल पर बैठे हुए 72 घण्टे का समय हो गया है और वे मरने के कगार पर हैं। यह बड़ा गम्भीर और दुःख का विषय है। अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि सरकार उन एन.एच.एम. कर्मचारियों से बात करके उनकी बात को सुना जाए और जो जायज मांगें हैं उनको माना जाए ताकि उनका यह गतिरोध और भूख हड़ताल हटे। यदि किसी की भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई तो यह बड़ा गम्भीर मामला हो जाएगा क्योंकि उन तीनों लोगों की हालत बहुत ज्यादा गम्भीर है।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जैसाकि भाई जाकिर हुसैन जी ने एन.एच. एम. वर्कर्ज की बात कही है, मैं भी इस संबंध में सदन में बताना चाहूंगा कि एन. एच.एम. वर्कर्ज अलग–अलग जगहों पर सभी विधायकों से मिले हैं। इन वर्कर्ज में कुछेक वर्कर्ज तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं जिनमें से दो–तीन वर्कर्ज की तो हालत बहुत खराब है। इनके लिए मेरा भी सरकार से आग्रह है कि इनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए।

श्री केहर सिंह रावतः अध्यक्ष महोदय, मेरे हथीन विधान सभा क्षेत्र के गांवों नामतः किशोरपुर, टहरकी तथा मन्दपुरी तथा पलवल विधान सभा क्षेत्र के गांव धतीर तथा पृथला विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांवों में बहुत भयंकर तूफान में सैंकड़ों घरों की

छतें उड़ गई हैं। यहां के बाशिंदों के पास न खाने के लिए कुछ बचा है न इनके पास कपड़े हैं और न ही सिर छिपाने के लिए कोई छत ही बची है। अतः सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इन गांवों ने बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा को झेला है इसलिए इनके उपर सरकार को ध्यान देने की बहुत जरूरत है।

श्री जाकिर हुसैनः अध्यक्ष महोदय, केहर जी ने बहुत महत्वपूर्ण इशु सदन में उठाया है। यहां के जो प्रभावित लोग हैं, वे दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा ने पूरे गांव को बर्बाद करके रख दिया है। अतः भाई केहर सिंह के साथ–साथ में भी सरकार से निवेदन करता हूँ की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जाना चाहिए।

श्री अनूप धानकः अध्यक्ष महोदय, मेरे उकलाना विधान सभा क्षेत्र में पिछले 10–15 दिन पहले भौरी अकबरपुर गांव में सुरेश कुमार व श्री प्रभू के परिवार में शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 मौतें हो चुकी हैं। श्री सुरेश कुमार तो अभी भी 50–60 परसेंट जला हुआ है। जब यहां पर संबंधित ए.डी.सी. गया तो राहत के तौर पर मात्र दो लाख रूपये देने की घोषणा करके आ गया लेकिन आज तक भी सरकार की तरफ से इस परिवार की कोई सुध तक नहीं ली गई है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस परिवार को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाये और इनका इलाज भी बढ़िया तरीके से करवाया जाये।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु): अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सदन में अभी प्राकृतिक आपदा भवंडर को लेकर इशु उठाया गया है कि चार गांव इस प्राकृतिक आपदा रूपी भवंडर से प्रभावित हुए है, के परिपेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गांवों का नाम लिखकर दे दें, हम उनका सर्वे करवाकर डिजास्टर रिलीफ डिपार्टमैंट के माध्यम से उन्हें हर संभव सहायता दिलाने का काम करेंगे।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुलः अध्यक्ष महोदय, मेरे जुलाना हल्के में नैशनल हाइवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी लेकिन किसानों को जो मुआवजा दिया गया उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और आपने इस डिस्क्रिमिनेशन को सोल्व करने के लिए वर्ष 2018 में सदन में लिखित में पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच कराई जाये और जांच कराने के बाद जो सही मुआवजा बनता है उसे दिलवाने का काम किया जाये तथा आपको भी इसकी रिपोर्ट की जाये

इसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा बाकायदा तौर पर हाउस में जांच कराने व डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने का आश्वासन दिया गया था लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बावजूद भी आज तक इस संबंध में न तो कोई जांच हो पाई है और न ही मुआवजा संबंधी डिस्क्रिमिनेशन ही दूर हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मुआवजे में डिस्क्रीमीनेशन की हालत यह है कि मेरे क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण के मुआवजा के तौर पर जहां वर्ष 2013 में प्रति एकड़ 12 लाख रूपये की ही राशि दी गई थी वहीं उसी वर्ष रोहतक में प्रति एकड़ 70 लाख रूपये की राशि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के तौर पर दी गई थी। यही नहीं जैसे ही मेरा हलके जुलाना की सीमा खत्म होती है, अगले गांव में उसी वर्ष जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि 45 लाख रूपये दी गई। अभी भी जुलाना हल्के के साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक ग्रीन फिल्ड हाई–वे निकल रहा है। उस हाई–वे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण के नाम पर केवल 14 लाख रुपये प्रति एकड़ दिए जा रहे हैं। जुलाना एरिया से बाहर जहां पर मारू जमीन है, वहां पर 70–70 लाख रुपये तक मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। जुलाना हल्के के लिजवाना कलां, बुढ़ाखेड़ा, लाठर, सिरसा खेड़ी, फतेहगढ़, लिजवाना खुर्द आदि कई गांवों की बहुत बढ़िया जमीन है, वहां पर जमीन अधिग्रहण के नाम पर किसानों को साढ़े चौदह लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जा रहे हैं। इस तरह से जुलाना हल्के के साथ इस तरह का भेदभाव अब भी किया जा रहा है और पहले भी किया जाता रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका कोई जवाब सदन में देंगे।

डॉ0 अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाईवे अथॉरिटी कलैक्टर रेट से जमीन के रेट कैलकुलेट करता है। यह गलती कलैक्टर रेट की फिक्सेशन में है। किसी गांव में कलैक्टर रेट 8 लाख रुपये कर दिया है और उसी के साथ लगते गांव में 20 लाख रुपये कलैक्टर रेट फिक्स कर दिया है और कहीं पर 50 लाख रुपये कलैक्टर रेट कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के नांगल चौधरी म्यूनिसिपल कमेटी के कलैक्टर रेट 55 लाख रुपये है और उसी के साथ लगती जमीन का कलैक्टर रेट मात्र 7 लाख रुपये है। एक को तो मुआवजे के तौर पर केवल 21 लाख रुपये मिले और दूसरे को मुआवजे के तौर पर करीब 1 करोड़ रुपये के आस–पास मिले है। अध्यक्ष महोदय, यदि हरियाणा सरकार सभी डी.सीज.

को आदेश दे कि कलैक्टर रेट को रेशनलाइज करके रिजनेबल कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। यदि फिर भी नहीं होता तो उसमें आर्बीट्रेटर में अपील का प्रौविजन है। अपील में सबको कम्पनसेशन मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर जरूर ध्यान दें।

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, डॉ0 अभय सिंह यादव हमारे यहां डी.सी. के पद पर रह चुके हैं, इसलिए इनको सब चीजों का पता है। इस तरह का भेदभाव जुलाना हल्के के साथ किया जा रहा है।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि जो यह कलैक्टर रेट का मामला है, यह बेसिक्ली मूलरूप से डी.सी. के अधिकार क्षेत्र का मामला है। (विघ्न)

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में भी इस तरह का भेदभाव किया गया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, नूंह हल्के के देवला गांव में भी इस तरह का भेदभाव किया गया है। (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में वर्ष 2013 में भी इस तरह का भेदभाव किया गया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : ढुल साहब, इस तरह का भेदभाव जुलाना हल्के के साथ इस सरकार के समय हुआ है या फिर पहले की सरकार में भी हुआ था। (विघ्न)

श्री परमेन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, जुलाना हल्के के साथ इस तरह का भेदभाव पहले की सरकारों में भी होता रहा है। (विघ्न)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहता हूँ कि एक गांव से दूसरे गांव का मुआवजे में काफी अंतर है। किसी गांव में 1 करोड़ रुपये, किसी गांव में 70 लाख रुपये और किसी गांव में 50 लाख रुपये कलैक्टर रेट है। इस तरह से एक ही तहसील और एक कानूनगो सर्कल में अलग–अलग रेट हैं। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि कलैक्टर रेट मुआवजे का आधार है। कलैक्टर रेट को तय करने का अधिकार डी.सी. के पास है। अध्यक्ष महोदय, हर जिले में जिलाधिकारी एक प्रक्रिया के तहत ही कलैक्टर रेट को तय करता है। डी.सी. एक महीने के लिए पब्लिक डोमेन में ले जाने के बाद ही कलैक्टर रेट तय करता है। (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सैन्टर के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट, 2014 में चार गुणा तक मुआवजा देने का प्रावधान है। (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, डी.सी. एक महीने के लिए पब्लिक डोमेन में ले जाने के बाद ही कलैक्टर रेट तय करता है। अब साल–भर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सभी डी.सीज. को कलैक्टर रेट साल–भर की प्रक्रिया को छोड़कर प्रति 6 माह में तय करने के निर्देश दे दिये हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से जमीन के भाव बहुत तेजी से ऊपर–नीचे हो रहे हैं । इसके अलावा नैशनल हाइवे के लिए लैण्ड की एक्विजिशन के संबंध में यह प्रावधान है कि जिस दिन लैण्ड एक्विजिशन का नोटिस निकलता है उस जमीन का उस दिन तक जो क्लैक्टर रेट होता है वह बेस बन जाता है । अगर उसके बाद एनहांसमैंट/कंपनसेशन देना हो तो वह एक कानूनी प्रक्रिया के द्वारा दे सकते हैं । अभी सदन में नजदीक के दो जिलों के गांवों के कलैक्टर रेट के भिन्न होने का विषय आया है । इस संबंध में मेरा कहना है कि अगर दो गांव अलग–अलग जिलों में आते हैं तो उन दोनों गांवों की जमीन का क्लैक्टर रेट वहां दोनों जिलों के अलग–अलग डी.सी. तय करते हैं । आज इसमें रैशनेलाइजेशन की आवश्यकता महसूस की जा रही है । यह एक लाइनीयर एक्विजीशन का विषय है । (शोर एवं व्यवधान) यह व्यवस्था पहले से चली आ रही है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि क्लैक्टर रेट तय करने का एक प्रोसीजर है । मेरा कहना है कि समस्या यह है कि क्लैक्टर रेट को तय करने का आधार सही नहीं है । जब सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम तहसील के दो गांवों की जमीनों का क्लैक्टर रेट तय किया जाता है तो डी.सी. को पड़ोस के गांवों की जमीन की होने वाली रजिस्ट्री के रेट का भी ध्यान करना चाहिए । उदाहरणतः छारा और बापड़ोदा दोनों गांव साथ–साथ बसे हुए हैं लेकिन एक गांव की जमीन का कलैक्टर रेट 60 लाख रूपये है और दूसरे गांव की जमीन का कलैक्टर रेट 1 करोड़ रूपये है । मेरा कहना है कि डिप्टी कमिश्नर को किसान हित का ध्यान रखते हुए क्लैक्टर रेट तय करना चाहिए । अगर किसी जगह का कलैक्टर रेट ठीक तय नहीं किया गया हो तो सरकार डी.सी. को आदेश दे सकती है कि वे कलैक्टर रेट को रिव्यू/एग्जामिन करके ठीक करें ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, पहले जिस हिसाब से क्लैक्टर रेट तय किया जाता था अब उसमें काफी सुधार कर दिया गया है । हमने इसमें काफी

रैशनेलाइजेशन किया है । मैं हाउस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने नैशनल हाइवे और रेलवे के लिए अब जितनी भी जमीन का अधिग्रहण किया है उस सारी जमीन का नये भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। अब मैं पलवल जिले के उन 5 गांवों – सहराला, कहरकी, किशोरपुर, पत्थरचटी और कलवाखां के बारे में पुष्टि करना चाहूंगा जिनमें बवंडर आया था । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करण सिंह जी, बवंडर से पीड़ित 2 गांवों के नाम अभी आये हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात सुन लें । इनका सुनने का स्वभाव ही नहीं है । (विघ्न) जिन 5 गांवों में बवंडर आया था उनकी विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही किये जा चुके हैं । अब मेरे पास 2 और गांवों – मंदपुरी और धतीन के नाम आए हैं । हम इन दोनों गांवों की विशेष गिरदावरी के आदेश भी कर रहे हैं । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह गिरदावरी करने में तो पता नहीं कितना वक्त लगेगा । आप देखिये कि बवंडर ने लोगों के घरों की छतें उड़ा दी हैं जिस वजह से उनके ऊपर छत नहीं रही, पशुओं की मौत हुई है, चोटें आई हैं, किसान अस्पताल में पड़े हुए हैं । ऐसे में सरकार को चाहिए था कि पीड़ित लोगों को सीधे–सीधे मुआवजा देना चाहिए था । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि इनकी इंसानियत तभी जागती है जब ये विपक्ष में बैठे हों । इतिहास गवाह है कि इन्होंने 10 सालों में आई हुई प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओला, बाढ़, सूखा इत्यादि की एवज में 80 करोड़ रूपये सालाना एवरेज से मुआवजे के दिए हैं जबकि हमारी सरकार ने 1000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष दिए हैं । इस बात का इतिहास साक्षी है । जब ये सत्ता के मद में चूर थे तो उस समय इनकी इंसानियत दब चुकी थी । अब इनकी इंसानियत धीरे–धीरे जाग रही है । मैं इस बात का स्वागत करता हूं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । आज तक सरकार का कोई भी मंत्री या कोई अधिकारी इन गांवों में लोगों की हालत को देखने के लिए नहीं गया है । वहां के लोग सड़कों पर पड़े हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा उन प्रभावित गरीब आदमियों के लिए खाने का भी इन्तजाम नहीं किया गया है। उस एरिया के सामाजिक लोग ही प्रभावित लोगों के

खाने का इन्तजाम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारा कॉलिंग अटैंशन मोशन एडमिट कर लें ताकि इस विषय पर चर्चा हो सके।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, अभी मेरे द्वारा दिये गये मेरे कॉलिंग अटैंशन मोशन के फेट के बारे में जानने पर माननीय मंत्री जी ने कलैक्टर रेट के बारे में जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे बेरी हल्के के छारा गांव में हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं और उन किसानों की ग्रीवेंस उचित है। सरकार का 3 साल की रजिस्ट्री की एवरेज का फार्मूला है। छारा गांव में चकबंदी शुरू हो चुकी है परन्तु वहां पर 3 सालों से कोई रजिस्ट्री नहीं हुई है। इसलिए छारा गांव के लोगों को 40 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया है जबकि साथ लगते गांव के लोगों को 1 करोड़ 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया है। मैंने तो सिर्फ इस डिस्पैरिटी को दूर करने के संदर्भ में कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है कि छारा गांव के किसानों के साथ घोर अन्याय किया गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आपका कॉलिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास कमेंट्स के लिए भेज दिया गया है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, ये पिछली सरकार के बोए हुए बीज हैं और मैं इस बात को प्रूव भी कर सकता हूं। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटालाः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सभी माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। अभय सिंह जी, आप अपनी बात रखें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भ

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा पुनरारम्भ होगी।

श्री अभय सिंह चौटाला (ऐलनाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आपसे निवेदन किया था कि आज सदन का समय समाप्त होने वाला है इसलिए मुझे कल भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया जाए। आपने मुझे आज फिर से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं कल चर्चा के दौरान फसलों का समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लागू करने के लिए कह रहा था और किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य से 50 फीसदी समर्थन मूल्य ज्यादा दिया जाए। इस बात का भी जिक्र किया था। मैं इस बात पर सदन के नेता को अवगत करवा रहा था कि आपकी सरकार की यह प्राथमिकता थी कि आपकी सरकार बनने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा और साथ ही साथ किसानों को उसकी फसल के लागत मूल्य से 50 फीसदी ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाएगा। मैंने इसके साथ–साथ यह भी बताया था कि आपकी पार्टी के मौजूदा कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी और माननीय सदस्य श्री सुभाष बराला जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले प्रदेश में अलग–2 जगहों पर जाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया था और यह कहा था कि किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2100/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया जाए। यह बात आज से 5 साल पहले की है। मेरे पास उस समय की अखबारों की कटिंग्ज भी हैं जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन्होंने मांग की थी कि गेहूं की फसल का समर्थन मूल्य 2100/– रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से घोषित किया जाए। अखबारों की कटिंग्ज की अलग–अलग तस्वीरों में श्री ओम प्रकाश धनखड़ और श्री सुभाष बराला जी के अलावा भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी प्रदर्शन में शामिल थे। आज से 5 साल पहले गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए प्रदर्शन किया गया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2100/– रुपये प्रति क्विंटल देने की मांग की थी परन्तु आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गेहूं का समर्थन मूल्य 1840/– रुपये प्रति क्विंटल है जबकि गेहूं का समर्थन मूल्य लागत से 50 फीसदी ज्यादा देने की बात की गयी थी। फसलों के समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इसके लिए प्रदेश की सरकारों द्वारा प्रत्येक वर्ष अलग–अलग फसलों के मूल्य के विवरण केन्द्र सरकार को लिखकर भेजे जाते हैं कि कौन–कौन सी फसलों का कितना लागत मूल्य है ? उदाहरण के तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में धान का लागत मूल्य 2074/– रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं का लागत मूल्य 2219/– रुपये प्रति क्विंटल लिखकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। इसी तरह से बाजरे का लागत मूल्य 1530/– रुपये प्रति क्विंटल और कपास का लागत मूल्य 5250/– रुपये प्रति क्विंटल लिखकर केन्द्र सरकार को भेजा गया था। वर्ष 2017–18 में धान का

लागत मूल्य 2657/– रुपये प्रति क्विंटल बताया गया था परन्तु जब धान के मूल्य की सिफारिश की गयी थी उस समय धान का लागत मूल्य 2860/– रुपये प्रति क्विंटल बताया गया था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार की तरफ से गेंहू पर 2469 रुपये, बाजरे पर 2217 रुपये और कपास पर 6256 रुपये प्रति क्विंटल की लागत मूल्य के लिए केन्द्र सरकार को सिफारिश की गई थी । आज की तारीख में किसानों को इसके बावजूद भी न तो गेंहू का समर्थन मूल्य मिल पाया है और न ही सरकार द्वारा बाजरे की पूरी खरीद की गई है। जब किसान अपना बाजरा बेचने के लिए बाजार में गया तो जहां सरकारी एजेंसी की जिम्मेवारी बनती थी कि उस बाजरे की खरीद करे लेकिन खरीद के साथ–साथ उसके ऊपर एक कैप लगा दी गई कि एक किसान से एक एकड़ का 4 क्विंटल से ज्यादा बाजरा नहीं खरीदा जायेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि किसान का 4 क्विंटल बाजरा नहीं बल्कि 8 क्विंटल बाजरा खरीदने के लिए बोला गया था। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हर बात की लीपापोती करने के लिए हर बात को गलत कह देते हैं । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कहां पर 8 क्विंटल बाजरा खरीदने की बात लिखी हुई है । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, कल सदन में कैप्टन साहब भी कह रहे थे कि 15–15 लाख रुपये की कोई बात नहीं हुई थी । (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे पास श्री नितिन गडकरी जी की स्टेटमैंट है (विघ्न) इनको आगे से आगे सही बात को गलत साबित करने की आदत पड़ गई है ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक किसान से एक एकड़ के लिए अधिकतम 8 क्विंटल बाजरा खरीदने की लिमिट रखी गई थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी किसान के 8 क्विंटल की खरीद का डाटा दिखायेंगे ? (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को इसका रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया जायेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप केवल और केवल हाउस में खड़े होकर के बाजरा नहीं खरीद सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, अभय सिंह जी सदन को गलत जानकारी दे रहे हैं । एक किसान से एक एकड़ के लिए अधिकतम 8 क्विंटल बाजरा खरीदने की लिमिट रखी गई थी । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी किसान से खरीदे गए बाजरे का पूरा रिकॉर्ड दिखा दें जिससे 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बाजरा खरीदा गया हो।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पूरे हरियाणा प्रदेश का डाटा दे दूंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह डाटा कब तक उपलब्ध करवा देंगे ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आज शाम तक किसान से खरीदे गये बाजरे का पूरा डाटा दे दूंगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बात के साक्षी हैं कहीं माननीय मंत्री जी अपनी बात से मुकर न जाएं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमने इस बार किसानों से 18 लाख क्विंटल बाजरा खरीदा है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं 18 लाख क्विंटल बाजरे की बात नहीं कर रहा हूं । मैं किसान से एक एकड़ के हिसाब से 4 क्विंटल बाजरा खरीदने की बात कर रहा हूं ।

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक किसान से एक एकड़ के लिए अधिकतम 8 क्विंटल बाजरा खरीदने की लिमिट रखी गई थी और 4 क्विंटल की कोई लिमिट नहीं रखी गई थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बाजरे की खरीद पर एक कैप लगाकर किसानों को सस्ते में बाजरा बेचने पर मजबूर किया । किसानों के साथ

सरसों खरीदते वक्त भी इसी तरह का बर्ताव किया गया था । मैं कल गन्ने की बात भी कर रहा था । गन्ने को लेकर मंत्री जी बड़े जोर–शोर से कह रहे थे कि हम गन्ना किसानों की पैमेंट कर रहे हैं लेकिन इस बात की खबर आज समाचार–पत्रों में भी छपी है । अब तक जो प्राइवेट मिल्ज़ है और सरकारी मिल्ज़ है, इन दोनों मिल्ज़ में किसानों के गन्ने की पैमेंट बकाया है। अब तक गन्ना किसानों को पूरी पैमेंट नहीं दी गई है । अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मिल्ज़ में 281.21 करोड़ रुपये गन्ना किसानों की पैमेंट बकाया है और जो सहकारी शुगर मिल्ज़ हैं उनमें गन्ना किसानों की 343.89 करोड़ रुपये बकाया है । यदि इन दोनों मिल्ज़ का पूरा विवरण चाहते हो तो मैं सदन में पढ़कर सुना देता हूं । (विघ्न)

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, गन्ने का अभी क्रेसिंग सीजन चल रहा है और इसी क्रेसिंग सीजन की ही पैमेंट बकाया है। पिछले सीजन की कोई पैमेंट बकाया नहीं है । अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी को एक पैड पर भी लिखकर दिया था । (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो अखबार में जो छपा हुआ है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है । कल इस बात का जवाब सदन में दे दिया गया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौटाला साहब, आपको सदन के माध्यम से इस बात का जवाब दे दिया गया था । (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बेवजह ही खड़े हो जाते हैं । उस वक्त श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सदन में उपस्थित नहीं थे । सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गन्ना किसानों की बकाया पैमेंट 15 दिन के अंदर–अंदर दे दी जाये । मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि गन्ने की लेट हुई पैमेंट ''पंजाब केन एक्ट'' के मुताबिक 14 प्रतिशत ब्याज के साथ सरकार को देनी होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गन्ने की लेट हुई पैमेंट पर किसानों को 14 प्रतिशत ब्याज के साथ ''पंजाब केन एक्ट'' के मुताबिक पैसा देगी? जब माननीय मुख्यमंत्री जी रिप्लाई देंगे तो इस बात का भी जवाब दें । मैं मुख्यमंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जिन–जिन शुगर मिल्ज़ के ऊपर किसानों का अभी तक बकाया है उसका भुगतान कब तक करवा दिया

जायेगा अर्थात किसान का पैसा उसके पास कब तक पहुंच जायेगा? जो प्रदेश की शुगर मिल्ज़ की आज खराब हालत है उसको कब तक दुरूस्त करवाया जायेगा यह भी बताया जाये। सरकार द्वारा पानीपत में नई शुगर मिल के निर्माण के लिए डाहर गांव में मिल का शिलान्यास तो कर दिया गया लेकिन उसके बाद आगे कुछ भी नहीं किया गया है। इससे पानीपत के गन्ना किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि पानीपत की पुरानी शुगर मिल सही ढंग से नहीं चल रही है और जो नई शुगर मिल बननी है उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से करनाल शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने की बात थी उसकी क्षमता को भी अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। इससे भी गन्ना किसानों को परेशानी हो रही है। इन सब कारणों से मजबूरीवश हरियाणा के किसानों को अपना गन्ना दूसरे राज्यों में जाकर बेचना पड़ रहा है। जहां एक ओर सरकार किसान हितैषी सरकार होने की बात करती है वहीं दूसरी ओर किसान की फसल के ऊपर चाहे वह गन्ने की फसल हो, बाजरे की फसल हो, गेहूं की फसल हो या फिर चाहे सरसों की फसल की बात हो उसमें किसान के सामने 100 तरह की परेशानी खड़ा करने की कोशिश करती है। इसी प्रकार से लगातार पराली को जलाने को लेकर भी एक बड़ी समस्या प्रदेश में आती रहती है। बहुत से किसानों के ऊपर पराली जलाने के लिए मुकद्दमें भी दायर किये गये हैं। बहुत से किसानों से पराली जलाने के लिए 3000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना भी वसूल किया गया है। मैंने यह पहले सत्र में भी कहा था कि प्रदूषण विभाग के एक एस.डी.ओ. द्वारा किसानों से पराली जलाने के नाम पर पैसा ले लिया लेकिन उसको सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया गया। इस प्रकार से प्रदूषण विभाग के एस.डी.ओ. ने यह घोटाला किया था। मैंने उसके बारे में यहां पर कहा था कि सरकार यह बताये कि सरकार द्वारा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? जब सदन के नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब दें तो इस बारे में भी बतायें। जो खेतों में पराली को जलाने की बात है इस सम्बन्ध में कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस इशू पर चर्चा हुई थी। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि किसान की पराली जलाने वाला जो सिस्टम है उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि खेतों में पराली जलाना खुद बंद नहीं होगा इसलिए सरकार द्वारा इसके लिए किसान को सबसिडी देने के बारे में विचार करना चाहिए। अगर सरकार सीधे–सीधे किसान के खाते के अंदर कोई पैसा सबसिडी के रूप में डाल

देगी तो फिर किसान उस पराली को 100 फीसदी जलाने के बजाये उस को निकालने का काम करेगा और इसी प्रकार से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसके साथ ही साथ जहां एक ओर किसान को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर हमारे प्रदेश का जो सरकारी कर्मचारी है वह भी सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण बुरी तरह से परेशान है। सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। सरकारी कर्मचारी का काम सरकार की विभिन्न योजनाओं की इम्पलीमैंटेशन करवाने का होता है जिससे लोगों को सुख–सुविधाओं की प्राप्ति हो। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सरकार की कुदृष्टि पड़ी हुई है। कभी सरकार उनके ऊपर एस्मा लगाती है, कभी लाठी चार्ज़ करवाती है और कभी उनको टर्मिनेट करती है। सरकार अगर उनकी बात को सुनने की बजाय उनको इस बात के लिए मजबूर करेगी कि वे स्ट्राईक करें और हंगर स्ट्राईक करके उसको लम्बे समय तक चलायें जिससे सरकार को नुक्सान हो यह किसी के भी हित में नहीं है। यह सरकार की सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनती है कि हडताल पर बैठे कर्मचारियों को बुलाकर उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाये। मुझसे पहले भी इस बारे में यहां पर बात की गई है। जो नैशनल हैल्थ मिशन के तहत हजारों कर्मचारी हरियाणा प्रदेश में लगाये गये थे उन्हें सरकार द्वारा आज तक भी पक्का नहीं किया गया है। वे सभी कर्मचारी पिछले 18 दिन से लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। उनमें से बहुत से लोगों ने हंगर स्ट्राईक भी की हुई है जिनमें से तीन लोगों की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि उनको कभी भी ट्रीटमैंट की जरूरत पड़ सकती है। उनकी हालत आज इतनी खराब है कि उनकी जान भी जा सकती है। उनकी हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर गई है। उनकी केवल एक ही डिमाण्ड है कि उनको पक्का किया जाये। भारतीय जनता पार्टी के मैनीफैस्टो में यह बात कही है कि हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। इसी प्रकार से पक्के लगे हुए कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने की बात भी जगह–जगह पर मैनीफैस्टो में कही गई थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वे गैस्ट टीचर्ज़ हैं और चाहे विभिन्न डिपार्टमैंट्स में लगे हुए दूसरे कच्चे कर्मचारी हैं आज तक उनमें से एक को भी पक्का नहीं किया गया है। आज भी वे सारे के सारे कच्चे कर्मचारी कहीं न कहीं आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको आंगनवाड़ी के हैल्पर्स के बारे में बताना चाहूंगा कि आज वे भी भूख हड़ताल पर हैं। चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो या कर्मचारियों

के पंजाब के समान वेतनमान देने की बात हो, कोई भी काम सरकार ने नहीं किया है। इसी प्रकार से पुरानी पैन्शन बहाली की मांग आज कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही है। नई पैन्शन स्कीम से कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। रिटायरमैंट के बाद अगर किसी कर्मचारी को पैन्शन मिलती है तो उस पैसे से वह अपने घर का खर्च चला सकता है। नई पैन्शन स्कीम में कर्मचारी को रिटायरमैंट के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा इसलिए पुरानी पैन्शन बहाल की जाये। अभी तक सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त समान काम के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से कैशलैस मेडिकल सुविधा भी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है तथा जन सेवाओं का निजीकरण भी किया जा रहा है। अभी सदन में नैशनल हैल्थ मिशन के कर्मचारियों का मामला भी उठा था। सरकार के आश्वासन के बाद भी एन.एच.एम. के कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया है इसलिए उनको मजबूर हो कर आज सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। सरकार के बार–बार पक्का करने के आश्वासन के बाद भी उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार से कल हाउस में डी–ग्रुप के 18 हजार कर्मचारी लगाने की बात कही गई थी तथा कुल मिला कर सरकार द्वारा 54 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। हाउस में ढोल पीटा जा रहा था कि बिना पर्ची और बिना पैसे के लेनदेन के सरकार द्वारा ये नौकरियां दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले से पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि नौकरियों में सबसे बड़ी दिक्कत गांवों के बच्चों को आती है। किसी ने 10वीं पास की है, किसी ने 12वीं पास की है तथा किसी ने इधर–उधर से पैसे लेकर बी.ए. पास भी कर ली है लेकिन उसके बावजूद भी वे आज ग्रुप–डी की नौकरी से वंचित रह गये हैं। उसका कारण यह है कि आपने जो ग्रुप–डी के लिए विज्ञापन निकाला था उसमें योग्यता दसवीं पास रखी गई थी। उसमें माली, चौकीदार, हैल्पर, वेटर तथा बेलदार इत्यादि की वैकेंसीज थी और इनके लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास रखी गई थी। लेकिन इन वैकेंसीज के लिए एम.एस.सीज, एम.फिल, पी.एच.डी., बी.टेक तथा नेट क्वालिफाई लोगों ने आवेदन कर दिया। जिन लोगों को लैक्चरर लगना था या टैक्निकल साइड में जाना था उन लोगों को मजबूर हो कर ग्रुप–डी की नौकरी करनी पड़ रही है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम 2 से 5 लाख लोगों को हर साल रोजगार और नौकरी देंगे लेकिन वह नहीं दिया गया। सरकार ने वायदा

किया था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे लेकिन न तो सरकार द्वारा लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया और न ही उनको रोजगार के साधन मुहैया करवाये गये जिससे उनको रोजगार मिल सके। सरकार दावा कर रही है कि हम योग्यता के आधार पर तथा मैरिट के आधार पर नौकरी देंगे लेकिन जिस बच्चे ने गांवों से 10वीं और 12वीं पास की है तो आप 100 फिसदी यह मानकर चलिए कि वह इस नौकरी में नहीं लग पाया। वह इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने तो दसवीं और 12वीं पास की थी। वह गरीब घर से सम्बन्ध रखता था और वह बी.ए. की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ था। उसके मां–बाप इस बात के लिए असहाय थे कि हम अपने बच्चे को आगे पढ़ाई करा सकें। गांवों के स्कूलों में टीचर्स की कमी के कारण भी वे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सके। जब उन्होंने फार्म भरे और आपने मैरिट बनाई तो वे बच्चे कम मार्क्स होने की वजह से मैरिट में नहीं आ सके। जो बेलदार, चपरासी, माली इत्यादि की नौकरी गरीब घरों के बच्चों के लिए होती हैं यदि आप उन नौकरियों पर बी.ए., एम.ए. या बी.टेक पास लोगों को लगा देंगे तो वे गरीब बच्चे कौन सी नौकरी करेंगे? मुझे किसी साथी ने बताया था कि दो लड़कियां जिन्होंने पी.एच.डी. कर रखी था उन दोनों को नहर विभाग में बेलदार के पद पर नौकरी लगा दिया। विभाग ने उनसे यह भी पूछा है कि आपको रात के समय भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है तो उन्होंने कहा कि पी.एच.डी. पास होने के बावजूद जब हमने ग्रुप–डी का फार्म भर दिया तो मान कर चलिए कि हमारे सामने कितनी बड़ी मजबूरी थी। अगर हमें रात के समय भी ड्यूटी करनी पड़ेगी तो हम करेंगी। हमें अपना घर चलाना है और आगे अपने बच्चों का पालन–पोषण करना है इसलिए हमें रात की ड्यूटी से भी ऐतराज नहीं है। इस तरह से जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरियां और रोजगार मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। जो बच्चे उसके हकदार थे उन पर सरकार ने अंकुश लगा दिया है और जो बच्चे दसवीं व बारहवीं पास थे उनको सरकार ने आगे नहीं बढ़ने दिया । उनको सरकार ने बेरोजगार कर दिया है । आज मैं अपने घर की बात बताता हूं । सरकार की तरफ से मेरे अपने घर के अन्दर सुबह एक माली काम करने के लिए आया था ।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है । आप वाईंड अप कीजिए ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, आप बात तो गलत नहीं कर रहे हैं लेकिन टाईम की तो लिमिट है क्योंकि बाकी सदस्यों को भी बुलवाना है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले जो साथी बोले थे उनको बोलने के लिए आपने काफी समय दिया था लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को जल्दी खत्म करते हुए अपनी दो–चार बातें कहना चाहूंगा । मैं सुबह अपने लॉन में बैठा चाय पी रहा था । वहां मेरे अपने घर के अन्दर जो माली काम करने के लिए आया था उसने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी । उस पर अच्छी टी–सर्ट और जाकेट पहन रखी थी । मैंने सोचा कि आज यह कोई नया कर्मचारी घर में आया होगा। मैंने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं ? उसने कहा कि मैं माली हूं। उसने वहां आते ही अपने हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करनी शुरू कर दी । मैंने उससे पूछा कि आपकी एप्वायंटमैंट कब हुई है ? उसने कहा कि जो अभी ग्रुप–डी की भर्ती हुई है उसमें मेरी एप्वायंटमैंट हुई है। वह लड़का एम.एस.सी. मैथ है जिसके 10वीं कक्षा में 80 प्रतिशत अंक हैं, 12वीं कक्षा में 61 प्रतिशत अंक हैं । अब जिसने एम.एस.सी कर रखी है । आज वह माली है और घास काट रहा है, झाड़ू लगाकर गन्दगी साफ कर रहा है तो फिर यह मानकर चलो कि उस बेचारे ने एम. एस.सी. क्यों की ? अगर यही काम करना था तो उसको एम.एस.सी. करने की जरूरत ही नहीं थी । इस काम के लिए तो उसको इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। यह काम तो वह किसी प्राईवेट कोठी में जाकर भी कर सकता था। कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर भी यह काम कर सकता था । अध्यक्ष महोदय, सरकार को जिनकी जैसी योग्यता है उनको उसी योग्यता के मुताबिक नौकरी देनी चाहिए । आपने जो यह योजना बनाई है कि हमने मैरिट के आधार पर नौकरी देनी है इससे केवल हमारे जो 70 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण आंचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनको नौकरी से वंचित करने की योजना बनाई गई है । आज आप यह मानकर चलें कि जिन लोगों ने ग्रुप–डी की नौकरी के लिए फॉर्म भरे थे और जो लोग इस नौकरी में आए हैं उनमें से 70 प्रतिशत लोग फिर से पुलिस की भर्ती में चले गये । वहां जाकर भी उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। अब जिस बच्चे ने एम.ए., पी.एच.डी. व नैट का एग्जाम पास कर लिया है उसके लिए पुलिस का एग्जाम पास करना कोई मुश्किल नहीं है इसलिए कम से कम जिस नौकरी के लिए जो योग्यता रखी गई है उसी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए ताकि बच्चों का अपमान न हो । अगर आज कोई एम.ए., एम.एस.सी, पास करके किसी के

घर में माली बनकर जाएगा तो 100 फीसदी उसका अपमान होगा । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य मेरी बात के बीच में बोल रहे हैं आप उनके बोलने पर अंकुश लगा कर रखिए । मेरी बात के बीच में कोई भी सदस्य कुछ भी बोल देता है । राज्यपाल के अभिभाषण में विशेष रूप से एस.वाई.एल. नहर को लेकर जिक्र आया हुआ है । खुद महामहिम ने इसको पढ़ा है । इसमें लिखा है कि मेरी सरकार एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध है । आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए दृढ़ता से कटिबद्ध हैं अर्थात सरकार इसको बनाना चाहती है । दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आया हुआ है जिसको आए हुए दो साल से ज्यादा का समय हो गया है । इसका फैसला 10 नवम्बर 2016 को आया था । उस फैसले में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इस नहर को बनाने में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है । केन्द्र की सरकार इसका निर्माण किसी भी एजेंसी से करवा सकती है । मुख्यमंत्री जी आपने इस संबंध में स्वयं एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हम सभी लोग भी शामिल थे । उस दिन मीटिंग में यह तय हुआ था कि अब इस को बनाने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है । इसलिए जल्दी ही इस नहर का निर्माण करवाने के लिए हमें देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री जी से भी मिलना चाहिए । उसके कुछ दिन बाद हम सभी पार्टियों के लोग देश के राष्ट्रपति जी से जाकर मिले । हम सभी ने उनसे आग्रह किया था कि आप केन्द्र की सरकार से इस नहर के निर्माण का काम शुरू करने के लिए कहें ताकि इस नहर का निर्माण हो सके । तब हमें यह उम्मीद जगी थी कि सरकार 100 फीसदी इस मामले में सीरियस है और चाहती है कि एस.वाई. एल. नहर का निर्माण हो जाये लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह सरकार एस.वाई.एल. नहर के विषय पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री से टाईम तक नहीं ले सकती और न ही इस विषय पर सभी पार्टियों के संयुक्त दल को प्रधानमंत्री जी से मिलावाने के लिए तैयार है। अध्यक्ष महोदय, आज तक एस.वाई.एल. नहर जैसे महत्वपूर्ण इशू पर केन्द्र सरकार की तरफ से कोई भी एजेंसी मुकर्रर नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि वे हाउस में इस बात को बतायें कि 10 नवम्बर, 2016 के बाद से आज की तारीख तक, इन्होंने एस.वाई.एल. नहर के निर्माण संबंधी विषय पर अपनी तरफ से कितनी बार प्रधानमंत्री जी से बात की है? कितनी बार इन्होंने इस विषय पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से बात की? अगर बात की है तो उसका ब्यौरा सदन को दें?

अध्यक्ष महोदय, एक बार मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर यह बात कही थी कि मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और हमने उनसे आग्रह किया था कि उस चिट्ठी की कॉपी हमें भी दिखाई जाये ताकि हमें भी पता चले सके कि उस चिट्ठी में सरकार ने क्या लिखा था और हमें भी यह अहसास होता कि वास्तव में हमारे प्रदेश की सरकार, प्रदेश के किसान के हित के लिए, एस.वाई.एल. नहर के निर्माण के लिए कितनी सीरियस है? इसके अलहदा जहां तक महामहिम अभिभाषण में 3 अलग–अलग डैम बनाने का जिक्र किया गया है, इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये डैम कब तक बनेंगे और इन डैम्स से हरियाणा प्रदेश को क्या फायदा होगा? डैम्स में ज्यादातर बरसाती पानी ही मिलता है लेकिन यह बरसाती पानी तो दादूपुर नलवी नहर से भी मिल रहा था लेकिन सरकार ने पहले से बनी इस दादूपुर–नलवी नहर को, जिससे हरियाणा प्रदेश के तीन जिलों की 2 लाख 25 हजार एकड़ जमीन सिंचित हो रही थी और जमीन के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था, सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि कोर्ट की तरफ से एनहांसमैंट का ज्यादा पैसे देने के आदेश किए गए थे। अध्यक्ष महोदय, किसान दिन–रात मेहनत करके अपने गाढ़े खून–पसीने की कमाई को टैक्स के रूप में सरकार को देता है। जब उस किसान के फेवर में हाई कोर्ट ने ज्यादा एनहांसमैंट के आदेश दे दिए तो एनहांसमैंट का यह ज्यादा पैसा किसान को देने की बजाय, सरकार ने दादूपुर–नलवी नहर को बंद करके किसानों को उजाड़ने का ही काम किया है। सरकार किसान हित की बात करती है और कहती है कि किसानों के लिए ये करेंगे–वो करेंगे लेकिन असल में जब किसान को फायदा देने की बात आती है तो यही सरकार किसान से छीनने का काम करती है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा न. 6 में लिखा है कि गरीब आदमी का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए उनको सरकार की तरफ से पौष्टिक आहार दिया जायेगा परन्तु बड़ी हैरानी की बात यह है कि इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते है तो यह भी लिखा हुआ पाते हैं कि गरीब आदमी को 2 लिटर सरसों का तेल और एक किलो चीनी सबसिडी देकर मुहैया करवाने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक किलो चीनी कौन सा पौष्टिक आहार है जिससे गरीब आदमी की सेहत ठीक हो सके? सरकार बताये तो सही? मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम प्रदेश की सारी सरसों खरीदने का काम करेंगे और उसका तेल निकालकर गरीब लोगों में बाटेंगे। तेल बाटा या नहीं बाटा यह तो अलग बात है लेकिन गरीब का

तेल जरूर इस सरकार ने जरूर निकाल दिया है। अध्यक्ष महोदय, दो–चार– पांच या दस रूपये की सबसिडी के द्वारा एक किलो सस्ती चीनी देकर सरकार गरीबों को कौन सा पौष्टिक आहार मुहैया करवाने जा रही है या चीनी के माध्यम से ऐसा कौन से विटामिन देने जा रही है जिससे उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से अरावली का जो मामला है वो भी बहुत चिंताजनक इशू है। आज अरावली को लेकर एक नई नीति बनाई जा रही है। अरावली की जमीन हरियाणा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण फॉरेस्ट एरिया है। हरियाणा में वैसे ही फारेस्ट के कुछ गिने चुने स्थान हैं जैसे कलेसर, मोरनी या शिवालिक या अरावली की पहाड़िया। अरावली की जो पहाड़ियां हैं वहां पर बहुत छोटी संख्या में फारेस्ट विद्यमान है और अगर अरावली के एरिया को भी फारेस्ट से बाहर काउंट किया जायेगा तो जो दिल्ली के सराउंडिंग आज प्रदूषण का बुरा हाल है वह प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज गुड़गांव के लोगों को ठीक ढंग से सांस लेने तक में भी दिक्कत होती है अगर उस प्रदूषण को छोटा–मोटा कोई रोकने का काम कर रही है तो वह अरावली की पहाड़ियां ही कर रही है। अगर ये पहाड़ियां काट दी जाती है और बिल्डर्ज को काम करने का मौका दिया जाता है तो फिर यह मानकर चलो कि बिल्डर्ज इस प्रोसैस में जरूर कमाई करेंगे और अन्य लोगों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो जायेगी। जो गुरूग्राम विकसित होना चाहिए था, जिस गुरूग्राम का नाम वर्ल्ड के नक्शे पर आना चाहिए था, उसकी बजाए सौ फीसदी गुरूग्राम का नाम प्रदूषण के नाम पर देश में सबसे बड़ा माना जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो–जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उन सब प्रश्नों का जवाब क्रम वाईज सदन के नेता जरूर दें। धन्यवाद।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमें बहुत उम्मीद थी कि सरकार के इस अंतिम बजट सत्र में सरकार कुछ जन हित के फैसले लेगी। ऐसी नई परियोजनाएं लागू की जायेंगी जिससे प्रदेश का निश्चित तौर पर भला होगा। लेकिन अभिभाषण को पढ़ने के बाद सरकार का निराशाजनक रवैया नजर आया है। इस अभिभाषण पर चर्चा के माध्यम से कल उप–चुनाव के बारे में भी जिक्र किया गया था। अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याक्षी डॉ0 कृष्ण लाल मिड्ढा चुनाव जीतकर विधान सभा में आए हैं। हरियाणा

के लोग यह कह रहे हैं कि 'मूसे को मिली हल्दी की गांठ और पंसारी बन बैठा'। भाजपा ने उपचुनाव क्या जीत लिया कि आपे से बाहर होते नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा अहंकार भाजपा नेताओं में सदन के अंदर और बाहर देखने को मिल रहा है। सरकार के विधायकों के कपड़ों के रंग जो बदल रहे हैं उसी तरह उनके बर्ताव के रंग बदल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम हरियाणा प्रदेश के अढ़ाई करोड़ जनता के कस्टोडियन होने के नाते बड़ी जिम्मेवारी के साथ जन हित के मुद्दे सदन में रखते हैं। यह ठीक है कि सरकार अपनी बातें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं रख पाई है। आज हरियाणा के नौजवानों की हालत क्या है, यह बात हम सभी जानते हैं। Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India के National Drug Dependence Treatment Centre (N.D.D.T.C.) ने 'Magnitude of Substance use in India' के बारे में जो रिपोर्ट दी है वह बहुत भयंकर है, अगर अध्यक्ष महोदय आप चाहे तो मैं इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने के लिए भी तैयार हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट कहती है कि नशे के मामले में हरियाणा कहीं दूसरे नम्बर पर है, कहीं तीसरे नम्बर पर है और कहीं चौथे नम्बर पर है। जब प्रदेश में नशा बढ़ रहा है तो नशे को रोकने के लिए सरकार क्या–क्या कदम उठा रही है? यह बात सरकार को सदन में बतानी चाहिए। आज हमारे बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं लेकिन ड्रग माफिया के लोग हमारे बच्चों को नशे की लत लगवाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की रिपोर्ट यह कह रही है कि Cannabis के प्रयोग में हरियाणा पूरे देश के अंदर छठे नम्बर पर आता है। Opiate में भी हरियाणा 8.68 प्रतिशत के हिसाब से पूरे देश के अंदर छठे नम्बर पर आता है। Sedative में भी हरियाणा 2.78 प्रतिशत के हिसाब से छठे नम्बर पर आता है। कोकिन में भी हरियाणा का नौजवान 0.9 प्रतिशत के हिसाब से नशा करता है। हरियाणा के 55358 लोग ड्रग्स के इंजैक्शन लगाते हैं । अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य बाकी राज्यों की तुलना में नशे के मामले में बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। हम उम्मीद करते थे कि यह सरकार नौजवानों का भविष्य बनाने के लिए काम करेगी लेकिन ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के नौजवानों का भविष्य केवल नशे के कारण ही आज खराब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नशे को रोकने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज के दिन प्रदेश में नंबर 2 का नशा, नंबर 2 की शराब और नंबर 2

की दवाईयां मिल रही हैं जो युवाओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं इसको रोकने के लिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है । हम उम्मीद करते थे कि सरकार क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट लागू करेगी क्योंकि हमें इस विषय को उठाते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं । लोगों को इलाज के लिए बार–बार अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है । प्राइवेट अस्पतालों में मरीज को एडमिट करते ही लाखों रूपये ले लिए जाते हैं और उनकी सेहत को और अधिक खराब किया जाता है । आज सरकारी अस्पतालों में न दवाइयां हैं, न डॉक्टर हैं और प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को मनमाने तरीके से लूटा जा रहा है । प्राइवेट अस्पतालों ने बहुत बड़े–बड़े धंधे किये हुए हैं । इनमें विदेशों से बसें भरकर आती हैं और कहीं लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कहीं किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, कहीं बिना जरूरत के ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है । इनमें मरीजों को बीमारी कुछ होती है और लोगों का इलाज कुछ किया जाता है । इसके अलावा अगर किसी पेशेंट के परिवारजनों द्वारा इलाज के दौरान बने बिलों पर एतराज उठाया जाता है तो वहां पर अस्पतालों ने बाउंसर रखे हुए हैं जोकि उनकी बेइज्जती करते हैं और उनकी पिटाई करते हैं । वर्ष 2014 में भारत सरकार ने क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट बनाया था और हरियाणा में प्रदेश सरकार ने भी यह एक्ट बनाया था । हमने उस एक्ट में हर क्लीनिक को इनवॉल्व किया था । यदि किसी को किसी अस्पताल या किसी क्लीनिक से कोई शिकायत है तो वह इस एक्ट के तहत उस वक्त बनने वाली बॉडीज़ को शिकायत कर सकता था । मुझे अफसोस है कि अपने आपको ईमानदार कहने वाले हैल्थ मिनिस्टर ने हरियाणा विधान सभा में अनाउंस कर चुके हैं कि हम क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट लागू करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । यह बात ठीक है कि हैल्थ एक स्टेट सब्जैक्ट है लेकिन उस समय भारत सरकार ने जो क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट बनाया था उसमें लोगों की तमाम सुविधाओं का ख्याल रखा गया था । हरियाणा सरकार ने पिछले से पिछले विधान सभा के सत्र में जो क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट पास किया था उसमें कम से कम 50 बैडिड हॉस्पिटल्स को शामिल किया गया था । मेरा कहना है कि इससे कम बैडिड कैपेसिटी के हॉस्पिटल्स के लिए अभी तक कानून बनाकर उसे नोटिफाई नहीं किया गया है जबकि गरीब आदमी इन्हीं हॉस्पिटल्स में ज्यादा इलाज करवाते हैं। स्पीकर सर, मैं ईमानदार स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि वे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गरीब लोगों पर इतना जुल्म करने की कानूनी तौर पर इजाजत क्यों

12:00 बजे

दे रहे हैं ? उन्हें इस क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट को फोरन लागू करना चाहिए जिससे आम आदमी सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ और डॉक्टर के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करवाने जाता है तो वे उसे मनमाने तरीके से न लूट सकें । इन अस्पतालों में मरीज के एडमिट होते ही उनके परिजनों को 2–2, 5–5 लाख रूपये जमा करवाने के लिए कह दिया जाता है । इसके बाद फिर वह मरीज जितने दिन तक अस्पताल में एडमिट रहता है तब तक उससे रोज लाखों रूपये जमा करवाने के लिए कहा जाता है । इसके अलावा इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्ट्र्स पेशेंट के लिए जो दवाइयाँ लिखते हैं वे दवाइयाँ उन हॉस्पिटल्स के प्रीमिसिज में बने मैडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध होती हैं । जब वे दवाइयां बच जाती हैं तो हॉस्पिटल स्टाफ उनको वहीं पर बेच देता है । इस लूट और धोखे से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार को क्लीनिकल एस्टैब्लिशमैंट एक्ट को नोटिफाई करके हरियाणा के लागों पर मेहरबानी करनी चाहिए । सरकार को इस एक्ट में अमैंडमैंट करके कम से कम 50 बैडिड हॉस्पिटल्स के दायरे को खत्म करके हर क्लीनिक को इसमें शामिल किया जाना चाहिए । स्पीकर सर, कैंसर एक खतरनाक बीमारी है । आज दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ग्लोबल वॉर्मिंग से बचने के लिए जितने भी प्रयास कर सकते हैं, कर रहे हैं । आप हमारी बदकिस्मती देखिये कि हरियाणा प्रदेश से गुजरने वाली यमुना नदी में कैमिकलयुक्त पानी छोड़ा जा रहा है । इससे फरीदाबाद, पलवल और मेवात डिस्ट्रिक्ट्स की सभी नहरों में पानी जाता है जिस वजह से इन क्षेत्रों का ग्राउंड वाटर खराब हो चुका है । इन एरियाज के इंसान और पशु इस दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं । मैंने कैंसर से संबंधित पिछले सैशन में सवाल पूछा था । मुझे पता चला कि हरियाणा प्रदेश में कैंसर के मरीज सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं । मैं आदरणीय सदस्य हुड्डा साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश की इस दिक्कत को समझा और झज्जर में कैंसर का बड़ा इंस्टीच्यूट बनवाया लेकिन पूरे प्रदेश में कैंसर का केवल एक इंस्टीच्यूट खोलने से लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये हर जिले के हॉस्पिटल्ज में कैंसर के मरीजों के ईलाज के संबंध में एक कमेटी बना दें और जिन–जिन जिलों में कैंसर के मरीज हैं उनको सरकार की गाड़ियां ही हॉस्पिटल्ज में लेकर जाएं और उनका ईलाज एम्स या दूसरे हॉस्पिटल्ज में करवाएं। इसके अतिरिक्त

सरकार द्वारा मरीजों को मंहगी दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए भी बंदोबश्त करना चाहिए। हमारे पलवल जिले का रूदी गांव ब्राह्मणों का गांव है और माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी भी इस गांव में कई बार गये हैं। इस गांव में कैंसर की वजह से हर महीने 1–2 लोगों की मौत हो जाती है। सरकार द्वारा इस बीमारी को पैदा करने वाले कारणों के बारे में कोई सर्वे नहीं करवाया गया है कि इस गांव के पानी में कोई कमी है या वातावरण में कमी है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने ओलावृष्टि के बारे में एक कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया है। हमारे क्षेत्र में बवंडर के कारण बहुत से लोगों के घरों की छतों को नुकसान हुआ है और बिजली के खंभों व खेतों में ट्यूबवैल्ज को भी नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त बवंडर के कारण भारी संख्या में पेड़ भी उखड़ गये हैं। हमने गांवों के बुजुर्गों से पूछा कि आपने पहले कभी ऐसा बवंडर देखा था तो उन्होंने बताया कि पिछले 50–60 सालों में उन्होंने ऐसा बवंडर पहले कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा बवंडर पहले कभी नहीं देखा। इसलिए आज पर्यावरण को ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास हिन्दुस्तान टाईम्स अखबार की कटिंग है जिसमें फरीदाबाद जिले के बारे में लिखा है कि 'Aravalli area is not a forest.' सरकार एक बिल्डर को लाभ देने के लिए माननीय कोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि उन्हें संबंधित एरिया में बिल्डिंग बनाने में कोई आपति नहीं है क्योंकि उस बिल्डर ने सरकार की जेबों में सोने–चांदी के सिक्के डाल दिये होंगे। सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है और कह रही है कि अरावली फोरेस्ट एरिया नहीं है। जबकि पूरे देश में ट्री प्रोटैक्शन एक्ट लागू है और इस एक्ट में यह लिखा हुआ है कि पेड़ चाहे किसी ने लगाया हो परन्तु उस पेड़ को काटा नहीं जा सकता। सरकार संबंधित बिल्डर का भला करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की मान्यताओं को भी दरकिनार करते हुए एफिडेविट देकर बिल्डर को कॉलोनी बनाने के लिए कह रही है। इस एरिया में लगभग 7 हजार पेड़ लगे हुए हैं और सरकार इन पेड़ों को काटकर बिल्डर को लाईसेंस देने की बात कह रही है। स्पीकर सर, मैंने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि पी.एल.पी.ए. (पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, 1900) अंग्रेजों के द्वारा सन् 1900 में बनाया गया था। अंग्रेजों को यह देश अपना दुश्मन समझता है परन्तु उन्होंने हमारे बाल–बच्चों को बचाने व बसाने के लिए सन् 1900 में कानून बनाया कि इस एरिया से कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। मैं सरकार को बताना चाहूंगा

कि अगर सरकार केवल कान्त एन्कलेव को बचाना चाहे तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि वहां पर लोगों के मकान बने हुए हैं। सरकार ने बिल्डर के साथ मिलकर कान्त एन्कलेव की आड़ में 1 हजार करोड़ रुपये का स्कैम किया है। फरीदाबाद जिले में रहने वाले लोगों की हालत खराब है और सबसे भयानक हालत गुरूग्राम जिले के लोगों की है क्योंकि ये जिले highest seismic zone में फॉल करते हैं। भगवान न करे कि इन जिलों में छोटे–मोटे अर्थ क्वेक आए तो इन जिलों में highest seismic zone में होने के कारण हालात बिगड़ सकते हैं। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि इन जिलों की न तो हवा शुद्ध है और न ही पानी शुद्ध है तो फिर वहां पर और लोगों को बसाने की क्या जरूरत है ? मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए कि सरकार को बिना जरूरत के पी.एल.पी.ए. एक्ट में अमैंड करने की क्या आवश्यकता थी ? इसके अलावा सरकार साधारण तरीके से कहती है कि डिवलैपमेंट प्लान में पी.एल.पी.ए. की धाराओं को समाप्त कर देंगे परन्तु इन जिलों में तो सारा ही डिवलैपमेंटल प्लान है। फरीदाबाद जिले के अलावा पलवल, मेवात जिलों में जो नवजात बच्चे जन्म ले रहे हैं वे पैरों व हाथों की बीमारियों के अलावा दिल की बीमारियां लेकर पैदा हो रहे हैं। सरकार इस बारे में रिपार्ट मंगवाकर देख ले। इस तरह से पलवल, गुरूग्राम, फरीदाबाद और मेवात जिलों में 25 प्रतिशत अपंग बच्चे जन्म ले रहे हैं क्योंकि ये सब बीमारियां हवा और पानी शुद्ध न होने के कारण हो रही हैं। इसलिए सरकार द्वारा पी.एल.पी.ए. को एक हजार करोड़ रुपये की रिश्वत के एवज में अमैंड करके हमारे क्षेत्र के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार की इस धारणा की जांच की जानी चाहिए। इनको किसने कह दिया कि इस तरह से पी.एल.पी.ए. को बदलें । अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी ट्रांसपोर्ट के बारे में निवेदन किया था कि अपने चहते लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो रोडवेज की बसों में हमारे स्कूल के लड़के–लड़कियों और खासकर के महिलाओं को घरों के नजदीक इज्जत के साथ पहुंचा दिया करते थे । आज यह सरकार जानबूझकर रोडवेज की बसों को ठिकाने लगा रही है और प्राइवेट जो ट्रांसपोर्टर हैं उनसे बसें ली जा रही हैं । पंजाब और राजस्थान में 22–23–24 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से प्राइवेट बसें किराये पर ली गई हैं जबकि हरियाणा में 36 रुपये, 37 रुपये प्रति किलोमीटर या इससे भी ज्यादा रुपये में किराये पर ली हैं, इनको बताना चाहिए कि ऐसी क्या जरूरत पड़

गई कि इतनी महंगी प्राइवेट बसें लेनी पड़ रही है? अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है । मैं इसके बारे में भी बताना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बड़ा घपला उजागर हुआ है इस बारे में अखबार में भी छपा है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम भी पास नहीं किए थे उनके नाम और रोल नम्बर तक भी रिकॉर्ड में नहीं थे । ऐसे लोगों को इस सरकार ने नौकरी देने का काम किया है लेकिन सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जहां तक कॉरपोरेशंज़ की बात है तो आदरणीय कॉ–ओपरेटिव मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। आपको जानकार बड़ी हैरानी होगी कि पानीपत शुगर मिल में मंत्री जी ने अपने एक चहते अधिकारी श्री बीर सिंह एच. सी.एस. जो रिटायर हो चुका है। उसको पानीपत शुगर मिल में एम.डी. लगाने के लिए नियमों की अवहेलना करके लगाया गया है क्योंकि वह मंत्री जी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम था।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी ने जैसे कि ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में चर्चा की है। हमने 710 प्राइवेट बसें यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर हायर करनी थी । हमारे पास 4100 बसों का बेड़ा है और 3900 बसें रनिंग में चल रही हैं । प्राइवेट बस के मालिक का ही ड्राईवर होगा और कंडक्टर परिवहन विभाग का होगा, बस का जो परमिट है, वह भी परिवहन विभाग का होगा और जो बस की रिकवरी आनी थी वह भी परिवहन विभाग के पास आनी है। इस बारे में बताना चाहूंगा कि 510 बसों के टेंडर जरूर हुए थे। इसमें 53 ऑपेरेटर्ज़ ने एप्लाई किया था और 49 इलिजिबल पाये गये थे । अभी तक विभाग की तरफ से किसी एक बस की भी अप्रूवल नहीं दी गई है। जहां तक नियुक्तियां की बात की है तो ट्रांसपोर्ट विभाग में एक सिंगल पद हमारी ओर से डायरेक्ट रिक्रूटमैंट नहीं किया गया है चाहे वह ड्राईवर हो या कंडक्टर हो क्योंकि हमारे विभाग में सभी नियुक्तियां हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन द्वारा होती है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, अखबार में लिखा हुआ है कि रोडवेज चालक भर्ती में बड़ा गोलमाल है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, यह कहीं आपका ही बयान न हो?

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, बीर सिंह, रिटायर्ड एच.सी.एस. ऑफिसर आये दिन ब्यान देते रहते हैं कि बड़ी ईमानदारों की सरकार है ।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, सरकार बयान से ईमानदार नहीं बनती है । लोगों के विश्वास से सरकार बनती है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात बताना चाहता हूं कि शुगर मिल में घटिया सामग्री लगाकर के सैंकड़ो करोड़ रुपये मंत्री जी की जेब भरने के लिए अपने एक चहते अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से एम.डी. पानीपत शुगर मिल लगाया गया । वह अधिकारी मंत्री जी की सेवाओं में लगा हुआ है और मिल को दोनों हाथों से लूटता रहा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनीष कुमार ग्रोवर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ये सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें । श्री करण सिंह दलाल जी हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और सरकार पर झूठे आरोप लगा रहे हैं । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की तरफ से अखबारों में रोज बयान आते हैं कि एक पूर्व–मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया गया है और दूसरे को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इनकी तरफ से इस प्रकार के बयान आये दिन समाचार पत्रों के माध्यम से आते रहते हैं। ये लोग खुद ही शिकायतकर्त्ता हैं, वकील भी खुद है और जज भी खुद बन जाते हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि मुझे बताएं कि मैं कौन सी जेल में चलूं, अभी मेरे साथ चलो। मैं सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपने–अपने पदों की गरिमा बनाये रखें । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब को कहना चाहूंगा कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य शिकायतकर्त्ता नहीं हैं । यह सदन इस बात का साक्षी है कि हुड्डा साहब बार–बार कहते थे कि मेरी इन्क्वायरी करवाओ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़डा : स्पीकर सर, मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि मेरे मामले में ये खुद ही जज क्यों बन रहे हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ इंक्वॉयरी करवा ली। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये मेरे खिलाफ और इंक्वॉयरी

करवा लें। जो भी सरकार के बस में हो उस मामले में मेरी इंक्वॉयरी करवा लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सभी प्रकार की इंक्वॉयरीज़ से पाक–साफ होकर निकल जाउंगा क्योंकि मैंने वर्तमान सरकार के मंत्रियों की तरह कोई घोटाले नहीं किये हैं। जब वर्तमान सरकार के मंत्रियों के खिलाफ उनके द्वारा किये जा रहे घोटालों के लिए कार्रवाई होगी तब सभी को इनकी असलियत का पता चल जायेगा।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को देश के न्याय तंत्र और दूसरी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। इनको जांच एजेंसियों के साथ को–आपरेट करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी फैसला हो सके। हम रोज़–रोज़ अखबारों में इस आशय की खबरें पढ़ते हैं कि आज फिर एडजर्नमैंट हो गई है। मेरा इनको सुझाव है कि ये को–ऑपरेट करें और इंक्वॉयरी को जल्दी से जल्दी कंकल्युड करवायें। जल्दी ही यह फैसला हो जायेगा कि ये कहां रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे।

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, आप अपनी बात कम्पलीट करें।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, मैं हरियाणा की सरकार से जो अपने आपको ईमानदार सरकार बता रही है उसको बताना चाहूंगा कि माननीय हाई कोर्ट ने बीर सिंह, एच.सी.एस. अधिकारी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सरकार यह जानती थी कि उस अधिकारी की वहां नियुक्ति नहीं हो सकती थी। 200 करोड़ रूपये के करीब पानीपत मिल के अंदर जो मशीन्स ली गई हैं व दूसरी खरीददारी हुई है उनको अपनी जेबों में भरने के लिए उस अधिकारी को गैर कानूनी तरीके से वहां पर लगाया गया। मेरी यह मांग है कि उस अधिकारी के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज़ किया जाये। उससे सारे पैसे की वसूली की जाये। इस मामले की जांच करवाई जाये कि उस अधिकारी के समय के दौरान जितने भी काम हुए हैं उनमें क्या–क्या गलतियां रही हैं? इसी प्रकार से मैं मोलेसिस के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे आदरणीय को–ऑपरेटिव मंत्री महकमा नहीं चलाते बल्कि ये तो अपने रिश्तेदारों की कम्पनी चलाते हैं। इनके रिश्तेदार शुगर मिल्ज़ से मोलैसिस खरीदते हैं। शराब को बनाने में मोलेसिस का बड़ा भारी योगदान है। आहूजा सप्लाई के नाम से जो कम्पनी है वह इनके रिश्तेदारों की ही है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे सदन में बतायें कि इस कम्पनी के मालिकों से इनका क्या रिश्ता है? क्यों हरियाणा प्रदेश में स्थित सभी शुगर मिल्ज़ के ठेके इनको दिये गये? मोलेसिस के

सम्बन्ध में एक निर्धारित कानून है कि अगर किसी ने मोलेसिस को खरीद लिया तो उसको तुरन्त ही उसको उठाना होगा। पहले तो आहूजा सप्लाई नाम की कम्पनी ने हरियाणा में स्थित सभी शुगर मिल्ज़ के मोलेसिस के ठेके ले लिये और जब मोलेसिस सस्ता हो गया तो उसने सभी मिल्ज़ से मोलेसिस को उठाना बंद कर दिया। इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि ये महकमे के मंत्री के रिश्तेदार हैं। इस सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर भी प्रदेश के लोगों को बरगलाने का काम चल रहा है कि हम इतने स्मार्ट सिटीज़ बनायेंगे। हमें तो फरीदाबाद के बारे में ही पता है। फरीदाबाद जिले के हमारे साथी विधायक यहां पर बैठे हैं। इनको पता होगा कि वहां पर स्मार्ट सिटी के नाम पर चाईनीज़ कम्पनी की घटिया सामग्री के स्मार्ट टॉयलेट्स और स्मार्ट जिम बनाकर पार्कों में लगा दिया है जो कि हर रोज़ खराब हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर फरीदाबाद के अंदर आज अगर कोई काम हुआ हो तो उसके बारे में यहां पर बताया जाये। वहां पर लोगों को पानी भी खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में गाड़ियों की नम्बर प्लेट्स का धंधा सरकार के संरक्षण में चल रहा है। जो टैक्नीकल नम्बर प्लेट्स हैं वे हरियाणा में मनमाने ढंग से बेची जा रही हैं इसके खिलाफ भी कोई बोलने वाला नहीं है। यह एक अजीब सरकार है। हमने इस सदन की मर्यादा को देखा है कि अगर यहां पर किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने खड़े होकर कोई आश्वासन दिया तो उस आश्वासन को पूरा किया जाता है। एक्स–ग्रेसिया स्कीम के बारे में मैंने हरेक विधान सभा सत्र में सवाल लगाये हैं। मुख्यमंत्री जी ने मेरे सवाल के जवाब में बाकायदा यह कहा है कि हां, हम एक्स–ग्रेसिया स्कीम को हरियाणा प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हरियाणा प्रदेश में एक्स–ग्रेसिया स्कीम का कोई नामोनिशान नहीं है। आज सरकार को इस प्रकार के फैसले लेने की जरूरत है जो जनमानस को फायदा पहुंचायें। ऐसे ही हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था डांवाडोल है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। माननीय मंत्री श्रीमती कविता जैन जी यहां पर बैठी नहीं हैं। सोनीपत के अंदर ग्राम पंचायत, बड़ौली के बाकायदा कम से कम 200 पंचों ने चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को हस्ताक्षर करके एक पत्र दिया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि श्रीमती कविता जैन जी और इनके परिवार के लोगों का वहां पर हुई हत्या में हाथ है। (विघ्न)

श्री जय तीर्थ : स्पीकर सर, मैंने इस आशय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया हुआ है जो कि सरकार के पास पैंडिंग है। ग्रुप–डी की नौकरियों के लिए डेढ़ करोड़ रूपये इक्ट्ठा किया गया है। इस मामले में एक मंत्री का खास तौर पर नाम भी आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : जय तीर्थ जी, आप कृपया करके बैठ जायें क्योंकि ग्रुप–डी की भर्तियां किस प्रकार से हुई हैं यह सभी को पता है।

श्री करण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम तो गांव वाले ले रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं इस पत्र को सदन की टेबल पर रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष : दलाल जी, आप एक मिनट के लिए बैठें और मत्री जी को अपनी बात कहने दें।

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री मनीष कुमार ग्रोवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो आरोप लगा रहे हैं वे तथ्यों से परे हैं, वे झूठ बोल रहे हैं। इनकी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में 26 गांवों की पंचायतों ने मुझे लिख कर दिया है और मैंने वह पत्र कर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया है कि यह एक गम्भीर मामला है इसकी सी.बी.आई. जांच करवाई जाये। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं लेकिन यह एक गम्भीर मामला है इसलिए इसकी सी.बी.आई. जांच करवाई जानी चाहिए। वहां के 26 गांवों की मांग है इसलिए इसकी सी.बी. आई. जांच करवाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकार हर काम में सी.बी.आई. की जांच करवाती है तो इस मामले की भी सी.बी.आई. जांच करवा दी जाये।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि सी.बी.आई. सरकार का तोता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस मामले की जांच सी.बी.आई. से करवाई जाये। क्या आप सी.बी.आई. की जांच से संतुष्ट होंगे?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों की मांग है कि इस मामले की सी.बी.आई. जांच करवाई जाये।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय जी ने अपने अभिभाषण में सरकारी नौकरियों का बखान किया है कि सरकार ने 18 हजार ग्रुप–डी की

नौकरियां दी हैं। ऐसा तमाशा हमने पहले कभी नहीं देखा कि 18 हजार नौकरियों के नाम पर इस हरियाणा प्रदेश में मां–बाप अपने नौजवान बेटे–बेटियों को एक जिले से 200–200 किलोमीटर दूर इम्तिहान दिलवाने के लिए लेकर गये। न उनके पास ठहरने की कोई जगह थी और न ही कोई अन्य इंतजाम थे। इस प्रकार से सरकार ने नौकरियों के नाम पर तमाशा बना दिया है। सरकार का कहना है कि हमने बहुत ईमानदारी से नौकरी दी हैं लेकिन मैं कहता हूं कि इन नौकरियों में बहुत धांधली हुई है इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। हरियाणा की जनता की आंखों में धूल झौंक कर अपने चहेतों को सरकार द्वारा नौकरी दी गई हैं। एक तरफ तो सरकार 18 हजार को नौकरी दे रही है और दूसरी तरफ जो कांट्रैक्चुअल बच्चे नौकरी पर लगे हुये थे उन 35 हजार को सरकार के द्वारा निकाला जा रहा है। इस हरियाणा में हजारों करोड़ रुपये का कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों का स्कैम हर महकमें में चल रहा है। कांट्रैक्चुअल कर्मचारियों का ई.एस.आई. तथा प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत गम्भीर बात कह रहे हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि इनके पास अगर इस बात के कोई साक्ष्य हैं तो वे यहां पर प्रस्तुत कर दें और अगर साक्ष्य यहां पर उपलब्ध नहीं हैं तो वे एफ.आई.आर. भी दर्ज करवा सकते हैं। केवल मात्र किसी बात का जिक्र कर देना और उसका प्रूफ न देना अच्छी बात नहीं है। आज इनके खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं उन सभी में या तो कोर्ट से आदेश हुये हैं या किसी ने शिकायत की है उसमें आदेश हुये हैं या किसी ने एफ.आई.आर. दर्ज करवाई है उसमें कार्रवाई चल रही है। हम इसको गम्भीरता से लेना चाहते हैं लेकिन उसके लिए कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। ये किसी अदालत में जायें या लोकायुक्त के पास जायें या कोई शिकायत दर्ज करवायें या एफ.आई.आर. दर्ज करवायें, ये कुछ तो करवायें इसकी जांच के लिए कोई प्रूफ तो होना चाहिए। यहां पर बोल कर मीडिया में छपवा दें कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि इनके अपने मन में अपराध बोध है। इनके 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने 18 हजार लोगों को नौकरी दी थी जो कि 5 साल की एक टर्म के हिसाब से 9 हजार बनती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार में जिसका जिक्र महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी किया गया है कि 73 हजार लोगों को बिना पर्ची बिना सिफारिश नौकरी मिलने वाली हैं। इनसे 8 गुणा ज्यादा

नौकरियां हमारी सरकार ने दी हैं। इनके समय में पर्ची और सिफारिश चलती थी यह सबको पता है। आज जो भर्ती हमारी सरकार ने की है उसके बारे में हरियाणा की किसी भी अदालत में कोई केस नहीं हुआ है कि इस भर्ती में कोई धांधली हुई है या कोई गड़बड़ हुई है। यह इनके मन की तकलीफ है जो झूठ बयानी से निकल कर आ रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनको आदेश करें कि जो भी ये आरोप लगा रहे हैं उनके प्रमाण लेकर आयें।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला प्रमाण तो यह है कि एच.एस.एस.सी. के चेयरमैन और उनसे जुड़े हुये दूसरे आदमियों के खिलाफ आपकी अपनी सरकार ने ही मुकदमा दर्ज किया है जो नौकरियों में पैसे का लेनदेन करके भ्रष्टाचार कर रहे थे। उस बारे में हाई कोर्ट ने क्या कहा यह भी देख लिया जाये। दूसरी बात यह है कि सभी महकमों में आउटसोर्सिंग से भर्ती करने का एक स्कैम चल रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की बहुत बड़ी–बड़ी बातें करते हैं लेकिन इस सरकार के लगभग सभी मंत्री और इनके चहेते लोग जो सरकार में ताकत रखते हैं उन्होंने एक प्रकार की रिक्रुटमैंट ऐजेन्सीज खोली हुई हैं। वे आउटसोर्सिंग में अपने चहेतों को भर्ती करते रहते हैं, उनको पूरा पैसा नहीं देते हैं तथा आउटसोर्सिंग पर लगवाने के लिए उनसे रिश्वत लेने का काम भी चल रहा है। हॉस्पिटल्स में तथा दूसरे डिपार्टमैंट्स में उनका जो प्रोविडैंट फंड तथा ई.एस.आई. स्कीम का पैसा आता है वह उनको नहीं दिया जा रहा है। दुनिया भर के लोगों ने जगह–जगह अखबरों के माध्यम से और वहां जा–जाकर एन.एच.एम. के कर्मचारियों की मिट्टी पलीत की है । वे बेचारे एन.एच.एम. के कर्मचारी सड़कों पर मारे–मारे फिर रहे हैं । उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं है । हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप कॉआपरेटिव सोसायटी बैंक, होस्पिटल्ज और दूसरे विभागों में पुराने कर्मचारियों को हटाकर दूसरे नये कर्मचारियों को क्यों लगा रहे हैं? जबकि पुराने कर्मचारी ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं । अध्यक्ष महोदय, सरकार के वे चहेते लोग जो सरकार में ताकत रखते हैं वे उन कर्मचारियों के पी.एफ. और ई. एस.आई. फैसीलिटीज के सैंकड़ों करोड़ रुपये के घोटालों में लिप्त हैं इसलिए वे उन कर्मचारियों को पक्का नहीं करना चाहते हैं । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कपास की खरीद में जी.एस.टी. स्कैम के ऊपर जो बेनामी एफ.आई.आर. दर्ज हुई हैं उनके बारे में आज तक यह नहीं बताया गया कि ये एफ.आई.आर. किसके खिलाफ दर्ज की गई हैं । आज सरकार के इशारों पर सरकार के चहेतों से जी.एस.टी के

अन्दर सैंकड़ों करोड़ रुपये की चोरी करवाई जा रही है । अगर कोई ऊपर से कोर्ट का या लोगों का दबाव बनता है तो बेनामी एफ.आई.आर. दर्ज करवा दी जाती हैं लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। स्पीकर सर, इसी तरह से आज राईस सेलर्स में जो धंधा चल रहा है मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं कि पिछले चार साल से मिलिंग के लिए जो चावल दिया जाता है । वह तमाम चावल बिहार व गरीब प्रदेशों से खरीद कर दे दिया जाता है । जिससे मंत्री और विभाग के अधिकारियों की पो–बारह हुई पड़ी है । अगर आप उस चावल खरीद की लिस्ट लेना चाहें तो हम अखबारों में छपी इन सारी बातों की लिस्ट दे सकते हैं। अखबार में यह खबर छपी है कि जो ट्रक बिहार से चावल लेकर आ रहा था उसको बाकायदा पुलिस ने पकड़ा है । मुख्यमंत्री जी, आपको तो शायद आपके चहेते इन बातों की भनक भी नहीं पड़ने दे रहे हैं । आज मिलिंग के नाम पर राईस मिल्स में बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है । स्पीकर सर, इसी तरीके से पिछले सैशन में आप जो इंडियन स्टाम्प एक्ट का कानून लेकर आए थे उस समय हम भी सदन में थे और वह कानून सदन में पास भी हुआ था । उस कानून के अन्दर यह है कि जो किसान कर्जा लेने के लिए एफिडेविट देता है तो उसकी वैल्यू दो हजार रुपये कर दी गई है । उस संबंध में बाकायदा बैंक के अधिकारियों ने सरकार को लिख कर भेजा है कि किसानों के साथ यह एक बहुत बड़ी जाद्ती है क्योंकि पहले कर्जा लेने के लिए किसानों से दस रुपये का स्टाम्प लिया जाता था ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात को स्पष्ट करना चाहता हूं । इन्होंने जो विषय उठाया है उस संबंध में पिछली बार हमारी सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट के अन्दर स्टाम्प फीस में संशोधन किया था । उसके बाद जो विषय माननीय सदस्य बता रहे हैं यह विषय जब हमारे नॉलिज में आया तो हमने तुरन्त बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनसे मीटिंग करने के बाद उनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन रिसीव करके एस.एल.बी.सी. में भेजी है जिसके ऊपर हम कंसीडिरेशन कर रहे हैं । स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वासन देता हूं कि हम उस स्टाम्प फीस में परिवर्तन करके उसको बहुत जल्दी बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लेकर आएंगे ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह मामला 6 महीने से कंसीडरेशन में चल रहा है । मंत्री जी को इस मामले पर तुरन्त फैसला लेना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मेरी अगली बात यह है कि दिल्ली एक छोटा सा प्रदेश है और दिल्ली

सरकार ने अपने किसानों के हितों के लिए स्वामी नाथन रिपोर्ट के आधार पर गेहूं और धान के रेट को 2600 और 2200 रुपये प्रति क्विंटल किया है । आज दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा बसा हुआ है । जब दिल्ली में किसान की उपज का अधिक दाम मिलता है तो हमारे हरियाणा के किसानों के मन में भी तकलीफ होती है कि हम भी अपनी उपज को दिल्ली में ले जाकर अधिक रेट पर बेचें । हरियाणा की मंडियों के अन्दर आज किसानों की हालत देखने लायक होती है । आज कोई भी एजेंसी खुद एम.एस.पी. रेट पर खरीद न करके किसान को व्यापारियों के भरोसे लूटने के लिए छोड़ देती है । जब दिल्ली सरकार किसानों की फसल को एम.एस. पी. रेट पर खरीद सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं खरीद सकती ? जबकि स्वामी नाथन रिपोर्ट का नारा तो हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया था । स्पीकर सर, दिल्ली हमारे हरियाणा के साथ लगता स्टेट है तो फिर हरियाणा सरकार हमारे किसानों की फसलों को दिल्ली सरकार के रेट के बराबर रेट देकर क्यों नहीं खरीद रही है ? हरियाणा में आज भी मार्किट फीस 4 प्रतिशत है और सरकार कहती है कि हमने जी.एस.टी. लागू कर दिया है । इसके बावजूद भी यहां किसानों से 4 प्रतिशत जी.एस.टी. भी लिया जा रहा है और मण्डी का टैक्स भी लिया जा रहा है । इसमें किसानों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा, मैं आदरणीय करण सिंह दलाल जी को बहुत सालों से जानता हूं । जब हम पढ़ते थे तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में सीनियर होते थे और ये एम.बी.ए. में पढ़ते थे । हम देखते थे कि यह अपने आप को बड़े ही उदयमान राजनीतिज्ञ समझते थे जिसको हरियाणा के अन्दर एक समय में सितारा कहा जाता था लेकिन मैंने यहां आकर जो देखा उसके बारे में मैंने इनको एक बार कहा भी था कि हमने सितारे डूबते हुए भी इसी सदन में देखे हैं । सदन में कोई भी बात प्रमाण के साथ कहनी चाहिए । दलाल साहब अपनी बात को प्रमाण सहित नहीं कह पा रहे हैं । उनसे मेरा निवेदन है कि वे कोई भी बात कहें तो प्रमाण के साथ कहें । मैं उनकी बात को स्पष्ट कर देता हूं कि आज किसी भी प्रकार के एग्रीकल्चर के ऊपर कोई जी.एस.टी. लागू नहीं है और न ही जी.एस. टी. लिया जा रहा है । बल्कि उसमें किसानों को फायदा हुआ है । पहले जो 4 प्रतिशत वैट लगता था वह वैट अब पूरी तरह से माफ हो गया है । अब वह वैट 0 हो गया है । आज किसी भी वैट के बदले में जी.एस.टी. नहीं लग रहा है । पहले

किसानों से जो 4 प्रतिशत वैट लिया जाता था वह भी अब जीरो हो गया है यानि कि पहले से कम हुआ है । इसलिए मैं आपके माध्यम से श्री दलाल साहब को निवेदन करता हूं कि वे यह जानकारी थोड़ी सी दुरूस्त कर लें ।

श्री करण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, लगता है कैप्टन साहब की डिग्री को चैक करना पड़ेगा? वैसे यह फौज में भी रहे हैं लेकिन शक है कि यह पढ़े लिखे भी है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सैस की बात कर रहा हूँ। मंडियों में चार परसेंट सैश लिया जा रहा है लेकिन सदन में सैश को समाप्त करने की बात कही जा रही है। अतः निवेदन है कि इस संबंध में कृषि मंत्री जी खड़े होकर स्पष्ट करें। बार–बार वैट की बात कही जा रही है, जब वैट रहा ही नहीं है तो यह लगेगा कैसे?

कैप्टन अभिमन्युः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी सदन में यह कहा था कि मंडियों में जी.एस.टी. लिया जा रहा है, आपने जी.एस.टी. शब्द का प्रयोग किया था और इसलिए मैंने जी.एस.टी. के बारे में बताया। यदि माननीय सदस्य को विश्वास नहीं है तो रिकॉर्ड चैक कर सकते हैं?

श्री करण सिंह दलालः सर, सुप्रीम कोर्ट ने सैस के संबंध में स्पष्ट रूलिंग दी है कि सैश इज ए टैक्स और यह टैक्स आज भी मंडियों के अन्दर लिया जा रहा है। गन्नौर के अंदर जो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मंडी बनाने का सपना हुड्डा जी की कांग्रेस की सरकार ने देखा था, वह आज ठिकाने लगा पड़ा है और स्पीकर सर जो हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत के समय में हर जेब में पैसा हुआ करता था, हर चेहरे पर खुशी हुआ करती थी तथा हर हाथ के पास काम हुआ करता था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हरियाणा को ऐसा बर्बाद कर दिया है कि लोगों के चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। न रोजगार है, न कानून व्यवस्था है और जहां हुड्डा जी के शासन काल में यूनिवर्सिटीज बना करती थी, नहरें बना करती थी, कॉलेज बना करते थे उसी के मद्देनज़र आज मैं राम बिलास जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने सदन में कहा कि इनके राज में बहुत जगहों पर कॉलेज खोले गए हैं, अध्यक्ष महोदय, आज हरियाणा प्रदेश के कालेजों में यह हालात हैं कि वहां पर न लैक्चरर हैं और न ही कोई स्टॉफ है। एक लैक्चरर पूरे कॉलेज को चला रहा है। इस तरह के हालात आज प्रदेश में बने हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश में हमारे ऐसे बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने इतने अच्छे सपने देखे कि अगर उनकी बातों को मान लिया जाता तो शायद आज हरियाणा की दशा बदल सकती थी।

मेरा निजी तौर से आपसे निवेदन है जैसाकि सबको पता है कि स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने 2 अगस्त, 1949 को कांस्टीट्यूंट एसेंबली में यह बात कही थी कि आने वाले दिनों में जो पंजाब है इसका बंटवारा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारा हरियाणा प्रदेश चारों तरफ से दिल्ली के साथ सटा हुआ है और दिल्ली से सटा हुआ इलाका एन.सी.आर. का एरिया माना जाता है जहां पर सब तरह की सुविधायें होनी चाहिंए लेकिन यहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं कि यह कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यदि सरकार दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बना ले तो इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। इसका फायदा यह होगा कि आने वाले दिनों में हमारे हरियाणा के बच्चों का सुनहरा भविष्य होगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली कोई प्रदेश नहीं है तो क्यों न इस दिल्ली को हरियाणा की राजधानी बना दिया जाये? अध्यक्ष महोदय, यह बात रिकॉर्ड पर आये ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जब इसको पढ़े तो उन्हें अहसास हो कि हमारे बुजुर्गो ने हरियाणा प्रदेश की खुशहाली के लिए क्या–क्या सपने देखे थे। अगर दिल्ली हरियाणा की राजधानी बनती है तो दिल्ली की भी दिक्कतें खत्म हो जायेंगी और हरियाणा की बेरोजगारी भी खत्म हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर पूरे देश के लोगों को रोजगार मिलता है और हरियाणा की राजधानी बनने के बाद एन.सी.आर. के क्षेत्र में भी सुधार आयेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे हाथ में वे डॉक्यूमैंट्स हैं जिनमें वर्ष 1949 में कांस्टीट्येंट एसेंबली में खड़े होकर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा ने कहा था कि पंजाब का बंटवारा होने वाला है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के डॉक्यमैंट्स, सदन की कार्यवाही का हिस्सा जरूर होने चाहिएं ताकि डिबेट में छप सकें। अतः निवेदन है कि इन डॉक्यूमैंट्स को स्वीकारते हुए रिकॉर्ड में लाया जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक है, आप इस रिकॉर्ड को मुझे दे दो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

(इस समय श्री करण सिंह दलाल द्वारा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा द्वारा वर्ष 1949 में कांस्टीट्येंट एसेंबली में खड़े होकर दिए गए बयान वाले डॉक्यूमैंट्स के कागजात श्री अध्यक्ष को सुपुर्द किए गए।)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (डबवाली) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय दोगुणा करने की तो दूर की बात

रही, आज किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। (इस समय उपाध्यक्ष महोदया पदासीन हुई।) उपाध्यक्ष महोदया, किसान अपनी फसल एम.एस.पी. से कम रेट पर बेचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि किसानों की मुख्य आय फसल ही है। किसानों की मुख्य मांग स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदया, अभी इसी महीने फरवरी, 2019 की 13 व 14 तारीख को डबवाली के ऐसे गांव हैं जहां पर भयंकर ओलावृष्टि हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि सरकार स्पेशल गिरदावरी करवा कर उन किसानों की खराब हुई फसल का उचित मुआवजा दे। उपाध्यक्ष महोदया, डबवाली क्षेत्र के लोगों को वर्ष 2018 का ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला इसके लिए वहां के किसानों ने दिसम्बर महीने की कड़ाके की सर्दी में भी हड़ताल की थी। इस संबंध में मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी से भी बात की थी लेकिन सरकार का कोई अधिकारी वहां नहीं पहुँचा था। इस तरह से उन किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे लगता है कि उन किसानों ने 10 दिन तो भूख हड़ताल की थी। फिर भी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया और न ही आज तक कोई मुआवजा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। इस तरह से हरियाणा के लोगों की सबसे ज्यादा आमदनी का जरिया कृषि ही है। आज हरियाणा के अंदर खाद की भारी किल्लत है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, यदि में पशु धन की बात करूं तो पहले यह कहा जाता था कि 'देसा में देस हरियाणा जहां दूध दही का खाणा'। उपाध्यक्ष महोदया, गायों के बारे में सदन से कहना चाहती हूँ कि सरकार एक तरफ तो यह कहती रहती है कि हम गायों के लिए ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। गऊशाला में एक गाय का खर्चा निकाला जाए तो औसत 40 रुपये प्रति दिन प्रति गाय के हिसाब से चारे का खर्च आता है। आज हर सड़क पर गायें घूमती नजर आयेंगी और सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा गायों की मौत होती है। फतेहाबाद से आगे निकलेंगे तो बड़ोपन गांव और सिरसा से जाओ तो सत्ताखेड़ा गांव के आस–पास सबसे ज्यादा आवारा पशु सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, गायों में टैगिंग सिस्टम लगा होता है और वो गाएं भी सड़कों पर घूमती हुई नजर आती हैं। क्योंकि गऊशाला के लोग गायों को चारे के लिए बाहर छोड़ते हैं। हमारे प्रदेश में जो पशु मेला लगता है, उसमें लोग राजस्थान से पशु लाकर हरियाणा में छोड़ देते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से

सदन से कहना चाहती हूँ कि जो पशु मेला लगता है उसके अंदर चैकिंग होनी चाहिए कि जितने पशु बिकने के लिए आते हैं उनमें से कितने पशु बिके और कितने पशु वापिस जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो गाएं आवारा घूमती रहती हैं उनको सरकार गऊशाला में छोड़ने का काम करे। मैं तो यहां तक कहना चाहूँगी कि जिस भी गऊशाला की गाएं सड़कों पर मिलती हैं उस गऊशाला की ग्रांट सरकार को बंद करनी चाहिए ताकि भविष्य में गऊशालाएं अपनी गायें गऊशाला में रख सकें। उपाध्यक्ष महोदया, यदि मैं जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बातें करूँ तो इसमें भी भारी कमियां हैं। डबवाली क्षेत्र के किलवाना गांव में पीने के पानी की भारी किल्लत है, क्योंकि वहां पर पानी की डिग्गियां बहुत छोटी हैं और नहरी पानी का कोई भी प्रबंध नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, एक तो उन डिग्गियों को बड़ा बनाया जाये और स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, आजकल तो हमारे डबवाली हल्के में स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा फैला हुआ है। अभी हाल ही में पन्नीवाला गांव में एक व्यक्ति और डबवाली शहर में 2–3 व्यक्तियों की मौत इस बीमारी से हुई है। उपाध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सिरसा शहर के आस–पास कोई भी कैंसर अस्पताल नहीं है। डबवाली हल्का पंजाब से लगता हुआ क्षेत्र है और हर रोज 1–2 मरीजों की मौत कैंसर के कारण हो रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल का यह अन्तिम वर्ष है, इसलिए सिरसा शहर में एक कैंसर अस्पताल की सौगात देने की कृपा करनी चाहिए इसके लिए सरकार की बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उपाध्यक्ष महोदया, डबवाली में नागरिक अस्पतालों से पता लगता है कि 74 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और 54 प्रतिशत प्रेग्नेंट महिलाएं कुपोषित हैं, इसलिए हर रोज अंडर वेट और कुपोषण के कारण मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहती हूँ कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में मल्टी विटामिंस और आयरन की दवाइयां देने के लिए एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जाए। उपाध्यक्ष महोदया, गरीब तबके की महिलाएं प्राईवेट डॉक्टर के पास अपना इलाज नहीं करवा सकती हैं, इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कोई–न–कोई सैमिनार चला कर या महिलाओं को जागरूक करके कुपोषण की समस्या को दूर करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं आपके माध्यम से कानून एवं व्यवस्था के बारे में सदन में कहना चाहती हूँ। मैंने स्वयं सिरसा के पास दिल्ली पुल पर दुर्गा शक्ति वाहिनी को

खड़ा देखा है। 'दुर्गा शक्ति वाहिनी' में शायद महिला पुलिस कांस्टेबल्स की ही ड्यूटी लगती है । वे पुलिसकर्मी सारा दिन वॉट्सएप आदि पर व्यस्त रहती हैं । उनकी नाक के नीचे बलात्कार, चोरी, किडनैपिंग इत्यादि की घटनाएं आये दिन होती रहती हैं । मेरा कहना है कि आप 'दुर्गा शक्ति वाहिनी' के कमिश्नर रैंक के अधिकारी से कहकर इनको मोबाइल से दूर करवाइये । इनकी ड्यूटी शहर में होती है । अगर ये दिन में शहर के 2–3 चक्कर लगा लें तो इससे जनता को विशेषतः लड़कियों/महिलाओं को हौंसला बनेगा कि आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस शहर में घूम रही है। मैं माननीय मंत्री कविता जैन जी से कहना चाहूंगी कि उन्हें प्रदेश के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए ध्यान देना चाहिए । इसके अलावा अगर हम महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सर्वे रिपोर्ट्स देखें तो पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश किनैपिंग, बलात्कार आदि के मामले में पूरे देश में पांचवे पायदान पर पहुंच चुका है। हरियाणा ने इस सूचि के मुताबिक बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है जबकि पहले कहा जाता था कि बिहार में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं । पहले बिहार का नाम महिला असुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा लिया जाता था लेकिन आज हरियाणा में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं । प्रदेश की हालत ऐसी है कि आज महिलाओं को घर से बाहर निकलते हुए भी डर लगता है । आज महिलाओं को सुबह घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए भी चैन स्नैचिंग करने वालो, मोटरसाइकिल से लात मारने वालो, पिस्टल लेकर घूमने वालों से डर रहता है । हमारे प्रदेश में पिस्टल लेकर घूमने वालो की तादाद बहुत बढ़ गई है । मुझे लगता है कि हरियाणा में कोई बहुत भारी मात्रा में पिस्टल्स सप्लाई कर रहा है जिसकी वजह ये यंग बच्चों के पास सबसे ज्यादा हथियार हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि इनको प्रदेश की कानून–व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए । सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का बहुत बड़ा नारा दिया है । इस सरकार ने सैक्स रेशो के अंतर को घटाकर बेटियों की संख्या को बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया था उसके विषय में मैं कहना चाहूंगी कि इससे प्रदेश में बेटियों की तादाद में काफी वृद्धि हुई है। इसके साथ–साथ सरकार को बेटियों की शिक्षा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मेरे सिरसा जिले के गांवों के स्कूल अभी तक अपग्रेड नहीं किये गए हैं। मैं जब अपनी कांस्टीच्यूएंशी में जाती हूं तो स्कूल्ज की लड़कियां अपना स्कूल छोड़कर भी मुझसे मिलने आती हैं। वे कहती हैं कि "मैम, हमारे स्कूल्ज को अपग्रेड करवाइये

ताकि हमें आगे की पढ़ाई के लिए शहर में न जाना पड़े।" उनको शहर में आने–जाने के लिए परिवहन की बहुत दिक्कत आती है । अब मैं परिवहन के विषय पर माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि चौटाला गांव से चंडीगढ़ के लिए बस चलाने के लिए पिछले साढ़े चार साल में दस बार कह चुकी हूं। पहले जब इस रूट पर बस चलती थी तो उसमें बहुत–से विद्यार्थी, अधिकरीगण और अन्य लोग सफर करते थे । इस रूट पर कुछ दिन पहले 15 दिनों के लिए एक बस चलाई गई थी लेकिन उस बस को भी बंद कर दिया गया है । उस बस को चलाने के लिए एक महिला विधायक होने के नोते मैं सरकार से बार–बार कह रही हूं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि जब वह बस सुचारू रूप से चल रही थी तो फिर उस बस को बंद क्यों कर दिया गया ?

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, वह बस हमने ट्रायल बेस पर चलाई थी लेकिन उस पर रिसीट्स कम आई थी । इस वजह से हमने उस बस को बंद कर दिया । हम अपनी बस घाटे में नहीं चला सकते ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, इस बस का घाटे में रहने का कारण कोहरा था, इसलिए अब मंत्री जी इसे दोबारा से 4 महीनों के लिए चलाकर देखिये ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : उपाध्यक्ष महोदया, मेरा कहना है कि हरियाणा रोड़वेज की बस दूध ढ़ोने के लिए नहीं चलती हैं बल्कि सवारियों को ढ़ाने के लिए चलती हैं । अब मैं माननीय सदस्या के कहने पर इस बस को चौटाला से चंडीगढ़ रूट पर 15 दिन के लिए दोबारा से ट्रायल बेस पर चलवा सकता हूं । अगर इस बार भी रिसीट्स कम आई तो हम इसे दोबारा से बंद कर देंगे ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं अपने देश के सैनिकों के विषय में बोलना चाहूंगी। अभी 7–8 दिन पहले पुलवामा में हमारे देश के लगभग 40 सैनिक शहीद हुए थे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनकी विधवा पत्नी और बच्चों के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाना चाहिए। शहीद सैनिकों के परिवारों को कोई दिक्कत न हो, उसके लिए सरकार को बजट में कोई अलग से प्रावधान करना चाहिए। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एक योजना बनायी गयी थी जिसमें शहीद सैनिकों के परिवारों को पैट्रोल पैम्प

और गैस एजेंसीज वितरित की जाती थी। इससे संबंधित शहीद सैनिकों के परिवारों की रोजी–रोटी चलती है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि वे दूसरी चीजों में कटौती करके शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अलग से कोई ब्लॉक बनाएं ताकि अगर कोई सैनिक शहीद हो जाए तो उसके परिवार को आजिविका चलाने में कोई दिक्कत न हो। सरकार शहीदों के परिवारों को पैसे दे रही है, यह अच्छी बात है परन्तु उन पैसों से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): उपाध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार शहीद सैनिकों के परिवार के सदस्यों को नौकरी भी देती है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं इस बात के लिए हरियाणा सरकार की सराहना करती हूं कि सरकार शहीदों के परिवारों के लिए जो भी कर रही है, वह अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि शहीद सैनिकों के परिवारों की आजीवन रोजी–रोटी के लिए बजट में अलग से प्रावधान करना चाहिए ताकि उनके परिवारों को सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि प्रदेश के पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिवारों के कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष काम किये हैं। हरियाणा प्रदेश में आज के दिन शायद ही कोई पूर्व सैनिक बेरोजगार होगा क्योंकि सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने 4500 नये एस.पी.ओज. की वैकेन्सीज 18,000/– रूपये प्रति महीने सैलरी के हिसाब से निकाली हैं। इसके अतिरिक्त पहले भी सरकार द्वारा लगभग 3,000–4,000 एस.पी.ओज. की भर्ती की जा चुकी है। हमारी सरकार ने शहीदों के परिवारों को नौकरी देने का एक नया रिकार्ड बनाया है। पिछली सरकार ने अपने 10 साल के कार्याकाल में शहीद सैनिकों के परिवारों को केवल 18–20 नौकरियां ही दी थी और उससे पहले के 6 सालों में 40–42 नौकरियां कारगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को दी गयी थी। हमारी सरकार ने 4 सालों में 255 लोगों को नौकरियां दी हैं जिसमें 1971 में शहीद हुए सैनिक परिवारों की तीसरी पीढ़ी के सदस्य भी शामिल हैं। आज हरियाणा प्रदेश में कोई ऐसा शहीद नहीं है जिसने अपने देश की माटी के लिए प्राण न्यौछावर किये हों और उसके परिवार के सदस्य को हरियाणा सरकार ने नौकरी न दी हो।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश की गेस्ट टीचर्ज दिव्यांग महिलाओं ने अपनी रोजी–रोटी के लिए सिर मुडंवा कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। वे महिलाएं सरकार के खिलाफ कई दिनों तक धरने पर भी बैठी रही और उन्होंने अनशन भी किया था।

कैप्टन अभिमन्यु: उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या जो बात कह रही हैं वह अलग विषय है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं पर्यावरण के बारे में बात करूं तो उसमें राज्यपाल महोदय ने ईको क्लब के बारे में बताया है।

उपाध्यक्ष महोदया: नैना जी, आप वाईंड अप करें।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगी कि प्रत्येक कैन्टीन में पॉलिथीन पायी जाती है फिर वह चाहे सरकारी कैन्टीन हो या स्कूल्ज/कॉलेजिज की कैन्टीन्ज हों। इन कैन्टीन्ज में बहुत ज्यादा पॉलिथीन का यूज किया जा रहा है। यही कारण है कि हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉलिथीन गलियों में पड़ी हुई मिलती हैं। सरकार साढ़े 4 सालों में पॉलिथीन को बन्द नहीं कर पायी है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगी कि प्रदेश में बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं तथा जितने भी एन.जी.ओज. सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको बुलाकर पॉलिथीन का यूज न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने में मद्द करने के लिए आग्रह करना चाहिए। जब तक हम पॉलिथीन का यूज बन्द नहीं करवा पाएंगे तब तक जलवायु परिवर्तन होने से नहीं रोक सकते। हम प्रायः देखते हैं कि कुछ गाय पॉलिथीन खाकर मर जाती हैं या बीमार हो जाती हैं तो उनके पेट के अन्दर से 20–20 किलो पॉलिथीन निकलती हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री (श्री विपुल गोयल): उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या ने जो सवाल उठाया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने पॉलिथीन के यूज पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। पॉलिथीन के यूज को बन्द करने के लिए ईको क्लब के माध्यम से अवेरनैस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो लोग पॉलिथीन बेचते हुए पाए जाते हैं उनके एगेंस्ट चालान करने का भी प्रावधान किया गया है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि भाषण बाजी से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी

डबवाली में जाकर देख लें और हिसार बाईपास पर चलकर देख लें, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिथीन पड़ी हुई हैं।

श्री विपुल गोयलः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पॉलिथीन के यूज पर दो साल पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिया था और चैकिंग के लिए रेगूलर कैम्पेन चलाया हुआ है। इसके अतिरिक्त संबंधित लोगों के चालान भी किये जा रहे हैं।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि वे प्रदेश के डंपिंग ग्राउंड्स को जाकर देखेंगे तो उनको वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिथीन पड़ी हुई मिलेंगी। इसके अतिरिक्त राजगढ़ रोड के नये बाईपास पर अपने तामझाम के साथ जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां पर कम से कम सैकड़ों क्विंटल पॉलिथीन पड़ी हुई हैं। डबवाली शहर में जाकर देख लें, वहां पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलिथीन पड़ी हुई मिलेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी कैन्टीन में जाकर देख लें, अगर कैन्टीन से फूड पैक करवाएंगे तो वे फूड को पॉलिथीन में ही डालकर देंगे। सरकार ने प्रदेश में पॉलिथीन बन्द करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया अगर सरकार प्रयास करती तो हरियाणा में पॉलिथीन के यूज को पूरी तरह से बन्द कर सकती थी। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पॉलिथीन की जगह पर पेपर बैग का यूज करवाया जाए। ईको ग्रीन का काम सरकार का ही नहीं ब्लकि पूरे हरियाणा के निवासियों की मुहिम है। इस काम में सभी मिलकर साथ देंगे तो हम पॉलिथीन के यूज को बंद करवा सकते हैं। ईको ग्रीन हरियाणा सरकार का ही नहीं बल्कि यह पूरे हरियाणा प्रदेश की मुहिम है। अगर हम सभी लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो पॉलिथीन के यूज को बन्द करवा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश में जितनी भी गऊशालाएं हैं वे ''गऊशाला आयोग'' के अंडर आती हैं । मैं ''गऊशाला आयोग'' के चेयरमैन से कहना चाहूंगी कि आये दिन गऊशाला में कथा करने के लिए कथावाचक आते रहते हैं और गऊशालाओं में महिलाएं कथा वगैरह सुनने के लिए भारी तादाद में इक्ट्ठी होती हैं। वे लोग भी लोगों को पॉलिथीन के नुकसान के बारे में जानकारी दें। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि एक ऐसी टीम का गठन करने का काम करें जो घर–घर जाकर लोगों को पॉलिथीन के प्रति जागरूक करने का काम करें। इस मुहिम में प्रदेश की जनता शामिल हो जाये तो हम पॉलिथीन को हरियाणा प्रदेश से मुक्त

करने का काम कर सकते हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि सभी पंचायतें तो सरकार के अंडर आती हैं। मैं इसके साथ यह भी कहना चाहती हूं कि हर घर में हर महिला के पास पुराने सूट या बैडशीट्स होती हैं । वे महिलाएं उन पुराने कपड़ों से छोटे–छोटे थैले बना सकती हैं, जिससे कि बाजार से फल फ्रूट/सब्जियां वगैरह आसानी से घर पर ला सकती हैं। पहले भी तो महिलाएं हाथ से बने हुए थैले बाजारों में ले जाती थी और इस तरह के थैले बाजारों में भी नहीं मिलते थे। हर महिला के पास हथकरघा से बना हुआ थैला होता था। उस समय लोग उस थैले को एक महीने नहीं बल्कि उस थैले को सालों तक यूज करते थे । आज हम हाथ से बने हुए थैले यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं बेरोजगारी की बात करना चाहूंगी आज के दिन जो बेरोजगार बच्चे हैं। वे सबसे ज्यादा नशा करते हैं, जिसका समाज पर गहरा असर पड़ता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मुझे देश की तो पूरी जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी मैं हरियाणा प्रदेश के पूरे जिलों की ही बात करूंगी कि धीरे–धीरे बच्चे नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। इसका एक ही मुख्य कारण है कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने हल्के डबवाली के बारे में कहनी चाहूंगी कि घर–घर में बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां के बच्चे सबसे ज्यादा नशा चिट्टे का ही करते हैं क्योंकि चिट्टा बहुत ज्यादा मात्रा में सप्लाई हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मेरे डबवाली हल्के में एक टीम बनाकर के घर–घर भेजी जाये ताकि जो बच्चे नशे की चपेट में आ गये हैं उनको जागरूक करने का काम किया जा सके क्योंकि दिनोंदिन हमारे समाज के नौजवानों को नशा खोखला करता जा रहा है। जिससे सभ्य समाज भी खत्म होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं । धन्यवाद ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रेवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदया, मेरे साथी देशवासी इस महान सदन की दर्शक दीर्घा में विराजमान हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर काफी अच्छी चर्चा चल रही है । मैं इस सदन को बधाई देते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की इतनी साफ–सुंदर, मजबूत और जनकल्याणकारी सरकार बनी है, जिसने प्रदेश के

नागरिकों को भ्रष्टचार मुक्त पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान किया है। यह हरियाणा प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बधाई के पात्र हैं। **(इस समय मेजें थपथपाई गई)** उपाध्यक्ष महोदया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सराहनीय काम किये हैं और उसी की बदौलत आज हरियाणा का जन–जन इस सरकार की प्रशंसा कर रहा है जिससे चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, पिछले चुनावों को देखें या आने वाले चुनावों की झलक देखें तो हमारे विपक्षी साथी अपने दिल में अनुभव भी कर रहे हैं और उनके भाव से यह बात स्पष्ट तौर पर पता लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में कितनी जन प्रिय हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदया, इसका सीधा–सीधा कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी पक्षपात के हरियाणा एक और हरियाणवी एक, समान विकास की एक सोच दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को अपना परिवार मान करके जो काम करने का प्रयास किया है ये सभी कुछ उसी का प्रतिफल है। यहां पर सबसे ज्यादा बात किसानों की हुई है। मनोहर सरकार ने हरियाणा प्रदेश में पहली बार किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है। हमारी सरकार ने हमारे इलाके के पिछड़े किसानों के बाजरे का भाव 1950 रूपये प्रति क्विंटल दिया है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है। इसके लिए मैं अपने कृषि मंत्री और पूरी सरकार को बधाई देता हूं। यहां पर विपक्ष के साथियों द्वारा यह चर्चा की गई थी कि सरकार द्वारा किसानों से केवल चार क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ही बाजरे की खरीद की गई है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने चार क्विंटल प्रति सकड़ के हिसाब से बाजरे की खरीद नहीं की अपितु यह मात्रा आठ क्विंटल प्रति एकड़ थी। इस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों के बाजरे के एक–एक दाने की खरीद की गई है। इसके लिए मैं अपने पूरे क्षेत्र की तरफ से सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारी सरकार द्वारा गन्ने का भाव भी किसानों को 340/– रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देना तय किया गया है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। यह हमारे प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार से प्रदेश के 10 लाख किसानों को 2000/– रूपये की पहली तिमाही किश्त जल्दी ही पहुंचाई जा रही है। मैं इसके लिए भी अपनी सरकार को बहुत–बहुत बधाई देना

चाहता हूं। किसानों के लिए चाहे फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे ओलावृष्टि का मुआवजा देने की बात हो इन सभी मामलों में हमारी सरकार ने रिकार्ड स्थापित किये हैं। हरियाणा प्रदेश में पिछली सरकारों द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। हमारी सरकार ने किसानों को जो मुआवजा दिया है उतना मुआवजा तो पिछली सभी सरकारों का टोटल मिलाकर भी नहीं हो पाया। बेरोजगारी को समाप्त करने के बारे में भी हमारी सरकार ने गम्भीरतापूर्वक कार्य किया है। पहले ऐसा लगता था कि हरियाणा प्रदेश का युवा जो राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए था वह रोजगार के अभाव में भटक गया था और ऐसा लगता था कि ये लोग अब have or have not की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हमारी हरियाणा सरकार ने पहली बार 26000 से अधिक भर्तियां मैरिट के आधार पर की हैं। इसके अलावा 17000 भर्तियों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि पहले की सरकारों में सिफारिश से और पर्चियों से भर्ती होती थी और हमारे यहां के अच्छे पढ़े लिखे बच्चे यह सोचते थे कि हमारी कोई सिफारिश नहीं है इसलिए हम सरकारी नौकरी नहीं पा सकते हैं। वे ये भी सोचते थे कि वे गोल्ड मैडलिस्ट हो सकते हैं और टॉपर हो सकते हैं लेकिन सरकारी नौकरी उन्हें नहीं मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उस परिदृश्य को पूरी तरह से बदला है और आज जब योग्यता के आधार पर सरकारी पदों पर भर्तियां हो रही हैं तो गरीब से गरीब के घर में भी दिया जला है और गरीब से गरीब घर में खुशियां आई हैं। इस सबसे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों में पढ़ाई के प्रति विश्वास बढ़ा है। निष्पक्ष रोजगार देने से विद्वान युवकों को मौका मिल रहा है। इससे पूरे प्रदेश में एक संदेश गया है कि अगर शिक्षा से नौकरी मिलेगी तो उससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ना चाहिए। अब लोगों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए मंत्रियों के घरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज हर तरफ सरकारी नौकरियों के लिए कम्पटीशन हो रहा है और कोचिंग सैंटर खुल रहे हैं। कोचिंग सैंटर खुलने से कोचिंग सैंटर वालों को भी रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है। प्रदेश में सरकारी कालेजिज और प्राईवेट कालेजिज के साथ ही साथ प्राईवेट स्कूल्ज़ और सरकारी स्कूल्ज़ में भी कम्पीटीशन होने लग गया है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे पढ़ने लग गये हैं और हमारे अध्यापक भी अपनी जिम्मेदारी समझने लग गये हैं। पिछली सरकार के शासनकाल में यह होता था कि कोई भी छात्र फेल नहीं

होगा लेकिन इस सरकार ने यह फैसला लिया है कि इग्जाम भी होगा और फेल भी हो सकते हैं। इस प्रकार से प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, शिक्षा बढ़ेगी तो प्रांत बढ़ेगा और प्रांत बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा और इस प्रकार से गौरवशाली भारत, वैभवशाली भारत, शक्तिशाली भारत तथा एक जागरूक भारत बनेगा। इस तरीके से भारत एक महान भारत बनने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सोच के लिए पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने का काम किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र को सर्वाधिक नौकरियां मिलने का पहली बार सौभाग्य मिला है। कुछ समय पहले हाउस में चर्चा हो रही थी कि पढ़े लिखे लोग ग्रुप–डी की नौकरियों में आने लगे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने नौकरी देने के बारे में नहीं सोचा जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। यही कारण है कि आज लोग बेरोजगार की दौड़ में जा रहे हैं। हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। केवल नौकरी का नाम ही रोजगार नहीं है, रोजगार का अर्थ व्यापार, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग तथा और क्या–क्या रास्ते हम सोचें जिससे हमारे बेरोजगार लोगों को काम मिल सके। उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" के रुप में एक बहुत सुन्दर योजना सरकार द्वारा दी गई है। अभी हमारी बहन नैना चौटाला जी कह रही थी कि हमारा लिंगानुपात सुधरा है। आज हरियाणा प्रदेश का लिंगानुपात 914 हो गया है जिसके लिए वे सरकार को बधाई दे रही थी। आज न केवल विपक्ष के हमारे साथी सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं बल्कि प्रदेश की जनता भी सरकार की प्रशंसा कर रही है जिसके लिए श्री मनोहर लाल जी की सरकार बधाई की पात्र है। "आपकी बेटी–हमारी बेटी" योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर उनके खातों में 21,000/– रुपये की राशि प्रति बालिका जमा करवाई गई है जो परिपक्व होने पर लगभग एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदया, एक दम से सबकुछ नहीं हो सकता है लेकिन सबकुछ करने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है, हम सबकुछ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी जनता को इस सरकार में विश्वास है कि यह सरकार प्रयास में लगी हुई है और जो कुछ रह गया है उसको भी यही सरकार पूरा कर सकती है। हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री तथा सभी विधायकों के प्रयासों से हमारे रेवाड़ी के मनेठी में एम्स बनाने की जो घोषणा हुई है उसके लिए मैं सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इससे पहले यहां के रोगियों को या

13:00 बजे तो दिल्ली लेकर जाया जाता था या जयपुर जाया जाता था। यहां सदन में बाढसा की चर्चा हो रही थी। हम चाहते हैं कि बाढ़सा में भी एम्स बने लेकिन मनेठी में बनने पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए हरियाणा सरकार को जितनी भी बधाई दी जाये उतनी कम है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे दक्षिण हरियाणा में पानी का बहुत ज्यादा अभाव था, पानी हमारी अस्मिता का सवाल था, हम पानी के लिए बार–बार चिल्लाते थे। पिछली सरकारों के समय में पूरा दक्षिण हरियाणा पानी के बिना मर रहा था। आज पहली बार हमारी कल्याणकारी सरकार ने हमारे क्षेत्र में टेल एण्ड तक अर्थात आखिरी छौर तक पानी पहुंचाने का काम किया है । इसके लिए हरियाणा की सरकार बधाई की पात्र है । अब हमारे क्षेत्र में साहबी, कृष्णावती और दोहान नदी में भी पानी जा रहा है जिससे वहां का जल स्तर मीठा होने के साथ–साथ ऊपर भी आ रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, जल संरक्षण के मामले में 25 तारीख को माननीय गडकरी जी रेवाड़ी को राष्ट्रीय पुरस्कार देने जा रहे हैं । इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूं । आज हमारी सरकार की रहनुमाई में यमुना नदी के अप स्टीम पर रेणुका, किसाऊ, लखवार बांधों के निर्माण कार्य के प्रयास हो रहे हैं जिनकी विद्यमान क्षमता को 8800 क्यूसिक से बढ़ाकर 13300 क्यूसिक किया जाएगा जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है । यह हमारे क्षेत्र की आवश्यकता भी थी और हमारी जरूरत भी थी। इसके लिए मैं हरियाणा सरकार को बहुत–बहुत बधाई देता हूं क्योंकि आज दक्षिणी हरियाणा की जरूरत पूरी हो गई है । इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा जे.एल.एन. फीडर की क्षमता को बढ़ाकर 3541 क्यूसिक तक किया जा रहा है और आंशिक क्रियान्विन क्षमता को बढ़ाकर 10 हजार क्यूसिक से अधिक किया जा रहा है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत–बहुत बधाई देता हूं । मैं कहा करता था कि सरकार के चार मोटे काम होते हैं– पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जिनमें हर जगह हमारी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ा है ।

उपाध्यक्ष महोदया : कापड़ीवास जी, प्लीज, आप वाईंडअप कीजिए ।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, सडकों के बारे में तो मैं बाद में बताउंगा वरना यह हो जाएगा कि मैं अपने क्षेत्र के मंत्री की तारीफ कर रहा हूं क्योंकि नरबीर सिंह जी भी दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र से हैं । मैं पहले ही कह देता हूं कि राव नरबीर सिंह जी व माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत तारीफ होनी चाहिए । हमारी सरकार ने सभी 90 विधान सभाओं में समान विकास किया है । राव नरबीर

सिंह जी को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंनें जो सड़कें बनाई हैं वे बिना पक्षपात और गुणवता के साथ बनाई हैं । यही नहीं आर.ओ.बी., आर.यू.बी. जितने राव नरबीर सिंह जी के समय में बने हैं उतने अगर जोड़ेंगे तो पिछली कई सरकारों के समय में भी नहीं बन पाए थे । इसके लिए भी मैं भाई नरबीर सिंह जी को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको रेवाड़ी का एक उदाहरण देता हूं। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे रेवाड़ी में जी.एच. अर्थात सामान्य होस्पीटल के बारे में एक खबर छपती थी कि सरकारी हस्पताल केवल पोस्टमार्टम करने और भाई–भाई के झगड़े में एम.एल.आर. काटने की दुकानें बन रही हैं लेकिन जब से हमारी पार्टी की सरकार आई है तब से हमारे रेवाड़ी की ओ.पी.डी. 400 से बढ़कर 2600 हो गई है। अब आप अनुमान लगाएं कि यह पांच गुणा से ज्यादा तब हुई है जब लोगों को विश्वास हुआ है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है । आज सरकारी अस्पतालों में मशीनें अच्छी आई हैं, डॉक्टर ज्यादा आए हैं और सरकार ने फ्री दवाइयां दी जा रही हैं । यही कारण है कि आज प्रदेश में इस तरह की बानगी है। जब रेवाड़ी में ये हाल है तो पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य की दृष्टि से कितनी तरक्की हुई है इसका अंदाजा हम सभी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं माननीय विज साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारी यूनिवर्सिटी के साथ 300 कॉलेज जोड़कर एक तरह से बहुत बड़ा कमाल किया है। पहले हमारी यूनिवर्सिटी मात्र रीजनल सैंटर बनकर रह गई थी। पहली बार हमारी यूनिवर्सिटी को पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है और यही कारण रहा है कि आज यहां पर विभिन्न प्रकार की फैकल्टीज भी आई हैं और इसके साथ ही हमारे माननीय मंत्री राव नरवीर जी ने एक कदम और आगे बढते हुए यूनिवर्सिटी के साथ जितनी भी सड़कें लगती हैं, उनको 18 फुट चौड़ा करने का भी बहुत बड़ा काम किया है। मेरे क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक ब्वॉयज कालेज भी दिया है। जहां तक "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं" की अवधारणा की बात है, के परिपेक्ष्य में बताना चाहूंगा कि पहले मेरे क्षेत्र में 2300 लड़कियां पढ़ती थी लेकिन आज उनकी संख्या 4600 अर्थात डबल हो गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मेरा अनुरोध है कि लड़कियों के लिए एक हास्टल बनाया जाये तथा साईंस ब्लॉक भी बनाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, हर क्षेत्र में गुणात्मक सुधार हुए हैं। मेरे धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में तथा बावल औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में उद्योग लगे हुए हैं। पहले जब इंस्पेक्टरी राज हुआ करता था तो

इंस्पेक्टर, प्रदूषण विभाग वाले तथा लेबर डिपार्टमैंट के अधिकारी/कर्मचारी उद्योगों के लिए डिस्टर्बेंस पैदा किया करते थे। जानबूझकर पैसे ऐंठने के लिए चालान काटा करते थे, तरह तरह की गड़बड़ी किया करते थे लेकिन आज इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया है और आज हमारे व्यापारी व उद्योगपति अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं और सम्मान का जीवन जी रहे हैं, देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तथा लोगों को रोजगार भी मुहैया करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापरियों व उद्योगपतियों को इज ऑफ डूंईग बिजनेस के जरिये अपने उद्योगों को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है जिसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार बधाई की पात्र है और यही कारण है कि आज बिजनेस के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश का पूरे भारत वर्ष में तीसरा नम्बर है। सफाई व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। बिजली में सुधार हुआ है और उर्जा को बढ़ावा मिला है। हमारे माननीय मंत्री राव नरवीर जी ने 7 रोड़ों के लिए 500 किलामीटर लंबी सड़कें देने का काम किया है वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग की चार सड़कों के लिए 126 किलोमीटर लंबी सड़कें देन का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। यही नहीं कला, संस्कृति तथा पुरातत्व के क्षेत्र में भी बहुत सुधार हुआ है। जहां तक जनस्वास्थ्य क्षेत्र की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में पानी आया है लेकिन अभी पानी के टैंक बनने बाकी हैं और इसके लिए गोकुलगढ़ गांव की पंचायत अपनी पंचायती जमीन कलेक्टर रेट पर देने के लिए तैयार है। मेरे क्षेत्र में वर्तमान में 42 हजार करोड़ लिटर पानी की जरूरत है। (विघ्न)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो माननीय सदस्य को बहुत पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ कि वे जमीन उपलब्ध करवायें, विभाग इनको एडिशनल पानी के टैंक बनाकर दे देगा।

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : उपाध्यक्ष महोदया, आज सच बात तो यह है कि हाल ही में हमारी सरकार में जो भर्तियाँ हुई हैं, शिक्षा, सड़कों और पानी की व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, उस चमत्कार को जनता हमेशा याद रखेगी। आज हमारी सरकार गन्ना किसानों को गन्ने का रेट सबसे ज्यादा दे रही है, उस चमत्कार को भी जनता हमेशा याद रखेगी। उपाध्यक्ष महोदया, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल व कैबिनेट मंत्रीगण बधाई के पात्र हैं। सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के लिए भी बधाई की पात्र है। उपाध्यक्ष महोदया, आज हरियाणा के लोग कहने लगे हैं कि मनोहर सरकार ईमानदार और निष्पक्ष सरकार है जोकि बहुत

बढ़िया कार्य कर रही है। हरियाणा के लोग आज यह भी कहने लगे हैं कि मनोहर सरकार के विधायक बहुत ही ईमानदार, शालिन, मिलकर चलने वाले और जनता की सेवा करने वाले विधायक हैं। उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ। जय हिन्द। जय भारत।

श्री जय प्रकाश (कलायत) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने हरियाणा सरकार का विजन डॉक्यूमेंट्स सदन के पटल पर रखा है और उस अभिभाषण को हमने बड़ी गहराई से देखा और पढ़ा है। कल डॉ0 पवन सैनी ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का अनुमोदन किया था और मेरे से पहले श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास तक बहुत से विधायकों ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चाएं की थी। उपाध्यक्ष महोदया, इस अभिभाषण के दौरान यह कहा गया था कि नौकरियों में पारदर्शिता बरती गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सदन में 2–3 बातें कहना चाहता हूँ। यह अच्छी बात है कि ग्रुप–डी के माध्यम से हरियाणा के नौजवानों को रोजगार दिया गया है। हमें इसमें किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। लेकिन इसमें मेरा सरकार से यह विरोध है कि जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी, डी.सी. रेट या कांट्रेक्ट बेसिज़ पर नौकरी लगे हुए थे, उनको नई भर्ती के बाद निकाल दिया गया है। सरकार एक तरफ तो नौजवानों को रोजगार दे रही है और दूसरी तरफ रोजगार छीन रही है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका जवाब सदन में जरूर देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदया, सरकारी नौकरी देना तो यह होता है जैसे अभी पंजाब सरकार ने मेला लगाकर नौकरियां दी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यदि सरकार ने हरियाणा के नौजवानों की बात नहीं मानी तो इस सत्र के बाद हम सब मिलकर विरोध करेंगे। उपाध्यक्ष महोदया, जो 32 हजार से लेकर 35 हजार तक बच्चे नौकरी से हटाए गए हैं, उनका आगे का भविष्य क्या होगा? यह बात ठीक है कि सरकार ने 17–18 हजार बच्चों को डी–ग्रुप के माध्यम से नौकरियां दी हैं। उपाध्यक्ष महोदया, यह काम सरकार ने केवल वोट हासिल करने के लिए किया है। आज नौजवानों के साथ इतना बड़ा अन्याय और जुल्म किया गया है कि उन्हें स्पष्ट तौर पर यह नहीं

बताया गया कि तुम किस–किस पद पर नियुक्त होंगे। सरकार ने यह नहीं बताया कि हम उसको वार्ड बॉय लगाएंगे, बारबर का काम देंगे, सड़क का बेलदार लगाएंगे या नहर का बेलदार लगाएंगे। सरकार को एक पोस्ट ग्रैजुएट हॉल्डर बच्चे को इस तरह के काम नहीं देने चाहिए। यह सरकार का डी–मैरिट है । यह नौजवानों के साथ अन्याय है। वह बच्चा जो बारबर लगाया है वह कान भी काटेगा और सरकार का नाक भी काटेगा क्योंकि उनको बारबर का ज्ञान ही नहीं है । मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक पोस्ट ग्रैजुएट हॉल्डर लड़की को सरकार ने फर्स्ट बटालियन में रोटी पकाने वाली लगा दिया है। सरकार को उन बच्चों को यह बात पहले ही बतानी चाहिए थी कि हम आपको कुक लगाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे या फिर बारबर लगाएंगे । सरकार को इसे दुरूस्त करना चाहिए और जिस बच्चे ने जैसी तालीम हासिल की हो उसे वैसी ही नौकरी देनी चाहिए । अब मैं भ्रष्टाचार के विषय पर बात करना चाहूंगा लेकिन मैं किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं । आज तक हरियाणा प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उनमें से चाहे किसी के शासन में सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हों लेकिन नौकरियों में अगर कभी भ्रष्टाचार हुआ तो उसमें गिफ्तारियां हुई हैं । बड़े दुःख की बात है कि इस सरकार में एच.एस.एस.सी. के मुलाजिमों की गिरफ्तारी हुई है जबकि मुलाजिमों को तो किसी को नौकरी देने का अख्तियार नहीं होता है । इसमें न तो एच.एस.एस.सी. के किसी मैम्बर को जिम्मेवार ठहराया गया और न ही चेयरमैन को जिम्मेवार ठहराया गया। अतः आपको इसे चैक करवाना चाहिए। तीसरा, मैं सिंचाई से संबंधित लखवार–व्यासी बांध और रेणुका–किशाऊ बांध पर बात करना चाहूंगा । वर्ष 2015 में जब मैं लोकसभा सदस्य था और माननीय सदस्य भूपेन्द्र सिंह हुड्डा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय जब भारत सरकार द्वारा लखवार–व्यासी बांध को बनाने की बात आई तो हुड्डा साहब ने भी प्रदेश सरकार के हिस्से के अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 100 करोड़ रूपये जमा करवाये थे । यह अच्छी बात है कि मौजूदा सरकार ने भी इसमें पैसा दिया है । तालाबों के गन्दे पानी की निकासी के लिए इस सरकार ने एक बिल पास करके एक प्राधिकरण का गठन किया था । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने तालाबों का गंदा पानी बाहर निकाला गया है और उसके लिए क्या सिस्टम अडॉप्ट किया गया है ? मैंने इस संबंध में 3 साल पहले विधान सभा में एक प्रस्ताव भी रखा था । मैं हाउस में बालू गांव का जिक्र करना चाहूंगा । इस गांव में बहुत बड़े–बड़े तालाब हैं । हमारे

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय को इस गांव में लेकर भी गए थे और वहां पर कहकर आऐ थे कि उसका गंदा पानी निकाला जाएगा। जब माननीय सदस्य श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और मैं लोकसभा का सदस्य था उस समय बालू गांव को प्रदेश का पहला मॉर्डन गांव बनाया गया था और उस गांव के विकास के लिए 22 करोड़ रूपये दिए गए थे । उस गांव में गलियां तो पक्की बन गई हैं लेकिन जब उसमें प्रवेश करते हैं तो गंदे पानी की बदबू से उसमें प्रवेश करना भी मुश्किल हो जाता है । इससे वहां के अच्छे किये हुए काम भी खराब हो जाते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने तालाबों की सफाई के लिए प्राधिकरण तो बना दिया लेकिन कितने दिनों में 10 हजार की आबादी के गांव शेरदा, 25 हजार की आबादी के गांव बालू और बात्ता, खरक–पांडवा, दुब्बल, गुलियाना, रामगढ़ आदि गांवों के तालाबों की सफाई हो जाएगी ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गांवों की सफाई व्यवस्था के लिए केवल माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी के हल्के के लिए ही पैसा खर्च किया है या हमारे हल्के की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा ? अब मैं रोजगार के विषय पर बात करना चाहूंगा । मैं माननीय मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि पुलिस ने कितने कर्मचारियों की पिटाई की है ? हरियाणा की बेटियां जब 6–6 महीने के बच्चों को गोद में उठाकर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए चण्डीगढ़ की तरफ बढ़ती थी तो उन पर कितनी बार पानी की की बौछारें, पुलिस का डंडा बरसाकर अत्याचार किया गया ? पुलिस द्वारा इस तरह की ज्यादतियां कर्मचारियों के साथ की गई हैं । प्रदेश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता । आज एन.एच.एम. के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं । आपको चाहिए कि उनकी युनियन को बुलाया जाए और उनकी समस्याओं का बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाए । मेरा कहना है इस प्रदेश की सरकार में हर कर्मचारी और मतदाता का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा हिस्सा माननीय मुख्य मंत्री महोदय का है । अतः सरकार को उनको चर्चा के लिए बुलाना चाहिए । सरकार ने पिछले दिनों ए.एन.एम./जी.एन.एम. कर्मचारियों पर मेंटेनैंश ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (मीशा) ही लगा दिया था । मैं माननीय सदस्य कापड़ीवास साहब से कहना चाहूंगा कि इनको इन चीजों को भी उठाना चाहिए । सरकार जहां भी किसी के साथ ज्यादती या अन्याय करेगी मैं उसका विरोध करूंगा । माननीय मंत्री जी ने तो धन–धन सतगुरू के संस्थापक रामपाल के फॉलोअर्स को यहां बुलाकर उन पर देशद्रोह के पर्चे तक दर्ज करवा

दिए थे । इन्होंने उनको यहां घेरकर पानी की बौछारें करवाई और फिर उनकी पुलिस से पिटाई करवाई । मैं कहता हूं कि इससे बढ़िया सरकार पूरे देश में कहीं नहीं मिल सकती । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं और मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र के बालू, बात्ता, खरक पांडवा गांवों की समस्या का जिक्र किया है। हरियाणा प्रदेश में 6745 गांव हैं और मैं क्लेम कर सकता हूं कि पिछले 35 सालों में 5,000 से ज्यादा गांवों में गया हूं। माननीय सदस्य की समस्या जायज है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय विधायक जी बड़े अनुभवी नेता हैं और बहुत से जिम्मेवार पदों पर भी रहे हैं परन्तु विपक्ष में बैठते ही पता नहीं क्या हो जाता है उनके शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। आदरणीय डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी भी कई वर्षों तक विधान सभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान रहे हैं और मेरे साथ मंत्रीमंडल में कॉ–आपरेटिव मिनिस्टर भी रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी भी अपनी बात कह रहे थे। उपाध्यक्ष महोदया, इस राजनीतिक गंगा में तो पता नहीं कब कौन शामिल हो जाए ? माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने 25 सितम्बर, 2017 को अपनी जुबान से इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की प्रशंसा की थी। मैंने कल ही सदन में एक विषय पर माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी के भाषण की दो पंक्तियां भी पढ़कर सुनाई थी। पिछले सैशन के दौरान एक कॉलिंग अटैंशन मोशन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था और माननीय सदस्य डॉ0 रघुवीर सिंह कादियान जी ने भी यह माना था कि सरकार ने पुलिस की भर्ती में ट्रांसपैरेंसी बरती है। नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी ने बताया कि सरकार ने एम.एस.सी. पास लड़के को माली के पद पर लगा दिया है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी और माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश जी ने भी ग्रुप –डी की भर्ती के बारे में अपनी राय प्रकट की है। माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल जी कह रहे थे कि सरकार ने लड़कियों को बेलदार के पद पर लगा दिया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि Government is Government. सरकार ने 18,218 बच्चों को ग्रुप डी में भर्ती करने का निर्णय कैबिनेट की मीटिंग में लिया था। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक विज्ञापन भी दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ग्रुप –डी की भर्ती के

लिए केवल परीक्षा होगी, there will be no interview. पहले की सरकारों पर यह आरोप लगते थे कि सरकार इन्टरव्यू के नाम पर अपने चहेतों को भर्ती करती है परन्तु हमारी सरकार ने कोई इन्टरव्यू नहीं रखा और मैरिट के आधार पर भर्ती की हैं। Ours is the first Government in the country कि जिसने यह काम किया हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला कि ग्रुप –डी में आवेदन के लिए मूल बेसिक क्वॉलिफिकेशन 10वीं पास होगी और उसमें नियमानुसार कोई भी एप्लाई कर सकता है। इस भर्ती के लिए 12 लाख बच्चों ने एप्लायी किया था। हरियाणा स्टॉफ सलैक्शन कमीशन ने जल्दी भर्ती का प्रोसैस पूरा किया है लेकिन रिजल्ट के बारे में there is a contradiction in the statement of the Hon'ble Members. एक तरफ विपक्ष के सदस्य मान रहे हैं कि एम.एस.सी. पास बच्चे भर्ती परीक्षा में पास हुए हैं और सरकार भी यही कह रही है कि संबंधित परीक्षा में मैरिट में आने वाले परीक्षार्थियों के आधार पर भर्ती की गयी है। इसमें बच्चों ने जो परीक्षा में लिखा है उसी के आधार पर परिणाम घोषित किये गये हैं। इस रिजल्ट की सभी कॉपीज हरियाणा स्टॉफ सैलेक्शन कमीशन के पास सुरक्षित रखी हुई हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को शक हो कि इस भर्ती में कोई हेराफेरी या भाई–भतीजावाद हुआ है तो आज भी हम संबंधित कॉपीज उनके सामने रख सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही बाते हैं। हरियाणा स्टॉफ सलैक्शन कमीशन ने ग्रुप–डी के लिए विज्ञापन निकाला और बेरोजगारों ने फार्म एप्लाई किया तथा जो बच्चे परीक्षा में पास हुए वे ग्रुप –डी में भर्ती हो गए। हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य भी सरकार की परफार्मेंस पर मोहर लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बालू, बात्ता, खरक पांडवा के गांवों में गन्दा पानी भरने की समस्या उठायी है, इस समस्या का जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा: उपाध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिन बच्चों ने ग्रुप –डी का एग्जाम पास किया उन्हीं को भर्ती किया गया है। इंडियन एक्सप्रैस पेपर में जो बात छपी थी वह मैंने दिल्ली में पढ़ी थी जिसमें लिखा गया था कि बी.ए. से कम क्वॉलिफिकेशन के बच्चे संबंधित पेपर में पास नहीं हो सकते। इस ग्रुप–डी की परीक्षा में 12 लाख एप्लीकेशंज में से 11 लाख बच्चे तो 10वीं पास थे और 1 लाख बच्चे बी.ए. पास या उससे ऊपर की क्वॉलिफिकेशन के थे। इसलिए इन 11 लाख बच्चों में से कोई भी बच्चा संबंधित एग्जाम पास नहीं कर सकता। इस परीक्षा में क्वैश्चन ही काफी जटिल पूछे गये थे। जो गरीब आदमी थे

जिनके बच्चे 10वीं या 12 वीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके। ये नौकरियां सिर्फ उन्हीं के बच्चों के लिए थी परन्तु वे बच्चे इस परीक्षा को पास नहीं कर सके। इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है ? सरकार को एम.ए./बी.ए. पास बच्चों के लिए अलग से भर्ती निकालनी चाहिए। इस ग्रुप –डी की भर्ती के लिए क्वॉलिफिकेशन का क्राऐटेरिया बनाना चाहिए था परन्तु सरकार ने ऐसा पेपर दिया जो 10वीं पास बच्चा पास नहीं कर सकता था। इसको एग्जामिन करवाया जाना चाहिए।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, हुड्डा साहब ने इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जो पढ़ा है, वह बात सही है। एक क्राईटेरिया होता है। जब हमें इस तरह की बातों के बारे में पहले से ही पता होता है कि इसमें ये बच्चे आ रहे हैं और उसमें वे बच्चे आ रहे हैं । हुड्डा साहब, आपने अपने समय में हरियाणा में लगभग 25 हजार जे. बी.टी. टीचर्ज़ भर्ती किए थे, जिनके अंगूठों के निशान गलत पाये गये थे । हमने उन टीचर्ज़ को सांईटिफिक प्रशिक्षण करके भर्ती किया है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, वर्तमान सरकार ने जे.बी.टी. टीचर्ज़ को भर्ती करने के लिए चार साल तक जानबूझकर लटकाये रखा था और बाद में इनके अंगूठों के निशान सही पाये गये थे तभी तो सरकार ने उनको भर्ती किया है। इनमें से एक भी कैंडीडेट गलत पाया गया हो तो माननीय मंत्री जी बता दें। जब इनके अंगूठों के निशान सही पाये गये थे तभी तो इनको सरकार ने भर्ती किया है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, मैं इनके साथ माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जे.बी.टी. टीचर्ज़ की भर्ती कोर्ट के आदेश के बाद हुई है ।

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि आप पुरानी बातों को क्यों छेड़ रहे हो? आपके पंथ मार्ग पर 22000 गेस्ट टीचर्स आमरण अनशन पर बैठे थे। उस वक्त हुड्डा साहब हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं खुद वहां गेस्ट टीचर्ज़ के धरने को उठवाने के लिए गया था और मैंने वहां पर एक डांट मारी थी कि मैं भी एक अध्यापक हूं । यदि आपने इनके आमरण अनशन को 12 घंटे के अंदर–अंदर नहीं तोड़ा तो मैं भी इनके साथ आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, आज सौभाग्य से हुड्डा साहब भी सदन में उपस्थित हैं । इनको बताना चाहूंगा कि यह एक समय है और समय हमेशा बदलता रहता है, यह एक जैसा नहीं रहता है। हुड्डा साहब, आपके कार्यकाल की एडिशनल चीफ सैक्रेटरी श्रीमती सुरेना राजन ने माननीय हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि 320 दिन के बाद इन सभी गेस्ट

टीचर्ज़ को हटा दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि 320 दिन दिसम्बर, 2014 में पूरे होते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद सरकार की तरफ से एक एफिडेविट माननीय हाई कोर्ट में दिया गया कि हम एक भी गेस्ट टीचर्स को नहीं हटायेंगे क्योंकि हमारे पास वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है । **(इस समय मेजें थपथपाई गई)** उपाध्यक्ष महोदया, हरियाणा प्रदेश के एक गेस्ट टीचर की बात नहीं है बल्कि 22000 गेस्ट टीचर्ज़ की बात है। हरियाणा प्रदेश में कोई गेस्ट टीचर 8 साल से, कोई 10 साल से और कोई 15 साल से कार्यरत है। आज हमें अपनी बात कहते हुए बड़ा संतोष होता है कि हमारी सरकार के समय में एक भी गेस्ट टीचर्ज़ को नहीं हटने दिया। हुड्डा साहब आप आने वाले दिनों में देखना कि हमारी सरकार ने जो जनता से वायदे किये थे उन वायदों को पूरा करने का काम किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, यदि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती तब भी गेस्ट टीचर्ज़ नहीं हटते । (शोर एवं व्यवधान)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार बेदी) : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में गेस्ट टीचर्ज़ की भर्ती में सबसे ज्यादा एस.सी. और बी.सी. रिजर्वेशन का वायलेशन हुआ था । (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने अपनी सरकार के समय में शिड्यूल कॉस्ट्स के बच्चों का गले काटने का काम किया था और रिजर्वेशन के नाम पर सत्यानाश के अलावा कुछ नहीं किया। आज ये लोग शिड्यूल कॉस्ट्स की बात करते हैं। इन लोगों ने रिजर्वेशन के कोटे के हिसाब से एक भी बच्चे को भर्ती नहीं किया जिसकी वजह से आज हरेक दलित वर्ग का व्यक्ति चिल्ला रहा है । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी बीच में खड़े होकर के बिना तथ्यों के ही बोलने लग जाते हैं। इनको शिष्टाचार ही नहीं निभाना आता है । (विघ्न)

श्री कृष्ण कुमार बेदी : उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय हुड्डा साहब को बताना चाहूंगा कि गेस्ट टीचर्ज़ की भर्ती में रिजर्वेशन का वायलेशन ही हुआ है। हमें रूल रेगुलेशन के बारे में सब पता है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदया, इन्होंने शिड्यूल कॉस्ट्स के बच्चों का गला काटने का काम किया है और आज ये लोग शिड्यूल कॉस्ट्स की बात कर रहे हैं । (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : बेदी जी, प्लीज बैठ जायें । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि ये गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं कर सकते थे तो इनको पक्का करने का वायदा इन्होंने क्यों किया? (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : हुड्डा जी, प्लीज बैठ जायें । मंत्री जी को बोलने दीजिए। (विघ्न)

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, जींद उपचुनाव के बाद आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी बहुत प्रसन्न है । ये हमारे बड़े भाई के समान है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं तो तब प्रसन्न होऊंगा जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का कांटा निकलेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सरकार ने ग्रुप–डी की भर्ती में पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट या एम.बी.ए. के बच्चों को भर्ती किया है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं । सरकार ने मैरिट के आधार पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है इसलिए मैं इस बात का भी विरोध नहीं करता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं केवल माननीय शिक्षा मंत्री जी का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे मान लो कोई कैंडीडेट 10 वीं या 12 वीं पास की योग्यता रखता है तो उसकी इस योग्यता के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बी.ए. पास योग्यता प्राप्त वाले कैंडीडेट हैं उनकी इस योग्यता के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं, तो ऐसे हालात में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 10वीं या 12वीं पास प्राप्त योग्यता वाले कैंडीडेट्स किस प्रकार से बी.ए. पास योग्यता प्राप्त वाले कैंडीडेट्स का मुकाबला कर पायेंगे? उपाध्यक्ष महोदया, जिन बच्चों ने गांव से 10वीं पास की है उनके लिए ऐसे इंतजाम हो और नौकरी के लिए जब कोई विज्ञापन निकाला जाता है तो उस विज्ञापन में गांव से शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अलग से कुछ प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि नौकरी में गांव के युवकों को तरजीह मिल सके क्योंकि यह हम सबको मालूम है कि गांव में शिक्षा की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे हालात में गांव से शिक्षा प्राप्त युवा किसी भी दृष्टिकोण से शहर से शिक्षा प्राप्त युवाओं से मुकाबला नहीं कर पायेंगे क्योंकि गांव में शिक्षा का स्तर काफी निचले स्तर पर है इसलिए मेरा यह कहना है कि इसको ठीक

किया जाये। मैं सरकार से यह भी कहना चाहूंगा कि 10 हज़ार ऐसे बच्चों को और सरकारी नौकरी पर लगाया जाये जो केवल मैट्रिक पास हों। डिप्टी स्पीकर मैडम, जहां तक शिक्षा का सवाल है। शिक्षा के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी और बहुत से दूसरे साथियों ने बात की है। मैं भी यह कहना चाहता हूं कि राम बिलास जी ने बहुत से अच्छे काम भी किये हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद भी करता हूं। कलायत के अंदर इन्होंने हमारे अनुरोध पर एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की इसके लिए भी मैं इनका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही इनसे मुझे एक शिकायत भी है कि मैंने इनसे अपने हल्के के लिए दो कॉलेजिज की डिमाण्ड की थी इन्होंने पहले तो दोनों को बनाने की हां भरी थी लेकिन बाद में उनमें से एक बनाया और दूसरे की ठगी कर गये। इन्होंने कलायत में तो कालेज बना दिया लेकिन राजौंद में कालेज स्थापना की डिमाण्ड को इग्नोर कर दिया। इससे सरकार की ट्रांसपैरेंसी में अंतर आ गया। मैं रामबिलास जी को रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि वे राजौंद में भी कॉलेज बनाने की घोषणा करें। उसके बाद ही मैं इनको यह बताउंगा कि उनके कार्य को मैं कितने नम्बर दूंगा ?

श्री राम बिलास शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया जी, हम जो सारे लोग हैं वे सभी एक छत के नीचे बैठने वाले लोग हैं। हमारे राजनीतिक दल अलग–अलग हो सकते हैं और यह भी स्पष्ट है कि हम अपनी–अपनी पार्टी को जीता रहे हैं। हमें अपने को आपस में दुश्मन नहीं समझना चाहिए और हमें अपने सामाजिक सम्बन्ध भी समाप्त नहीं करने चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदया जी, हम सभी को अपनी–अपनी मर्यादाओं का ध्यान होना चाहिए। जो भी माननीय सदस्य यहां पर अपने–अपने चुनाव क्षेत्र की और दूसरी जगह की बात रखते हैं हम उसको बहुत ही गम्भीरता से लेते हैं। जय प्रकाश जी ने कलायत के महाविद्यालय की बात कही जैसा कि सभी जानते हैं आज कलायत में महाविद्यालय चल रहा है। मैं जय प्रकाश जी को यह आश्वासन देता हूं कि हम राजौंद में भी महाविद्यालय बनायेंगे।

श्री जय प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदया जी, मैं इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। अब मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर बात करना चाहता हूं। जो स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था मैं भी उस समय सांसद था और इस आयोग का सदस्य रहा। यह बात सही है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सुधार के कार्यक्रम तो वर्ष 2006 में ही शुरू हो चुके थे। उसके बाद वे धीरे–धीरे बढ़ते गये। फिर चौधरी भूपेन्द्र सिंह

हुड़डा, प्रकाश सिंह बादल और एक मुख्यमंत्री और थे इन तीन चीफ मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया गया था। यह मामला उसमें भी आया था। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो बात भारत की सरकार ने कही थी कि हम किसान की उपज की लागत का डेढ़ गुणा दाम देंगे। अब गेहूं का दाम 1930/– रूपये प्रति क्विंटल का है। इसके लिए यहां से सर्वसम्मति से हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार के नाम एक रेजोल्यूशन डालना चाहिए कि अगली बार गेहूं का भाव कम से कम 2700/– रूपये प्रति क्विंटल किसान को मिले और जो गरीब आदमी हैं जो गेहूं मोल लेते हैं उनको भी राशन कार्ड पर सस्ती गेहूं दी जाये ताकि किसान के साथ ही साथ गरीब का भी भला हो। अंत में, मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि सरकार की किसानों से सम्बंधित एक योजना आई वह बहुत अच्छी योजना है चाहे अभी उसमें धनराशि कम रखी गई है। इसमें धनराशि कम है मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता मैं तो यही कहूंगा कि किसानों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यह एक बहुत ही अच्छी योजना शुरू की गई है। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना था। उन्होंने यह भी कहा था कि हम मज़दूरों को भी पैंशन देंगे लेकिन उसमें यह अभी तक क्लैरीफाई नहीं हुआ है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से सरकार से रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि जो खेतिहर मजदूर हैं, जो गांवों में हरिजन हैं अर्थात् दलित भाई हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है यह भी यहां पर स्पष्ट रूप से बताया जाये। मैंने यह सुना है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ है और हरियाणा सरकार भी किसान पैंशन योजना लागू करना चाहती है। अगर हरियाणा सरकार भी किसानों को 6000 रूपये वार्षिक पैंशन देगी तो मैं उसका स्वागत भी करूंगा लेकिन मैं इसमें एक बात जरूर जुड़वाना चाहूंगा कि किसान के साथ–साथ जो भूमिहीन किसान हैं अर्थात् जो किसान भूमि को पट्टे पर लेकर खेती करते हैं अर्थात् जो खेतिहर मज़दूर हैं उनको भी उस स्कीम में शामिल किया जाये। अंत में, मैं श्री रामबिलास शर्मा जी से एक बात और कहना चाहूंगा कि हरियाणा में आर्म्ज लाईसैंस की एक समस्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो ये आर्म्ज लाईसैंस पूरी तरह से बंद होने चाहिएं अर्थात् किसी का भी आर्म्ज लाईसैंस न बने या फिर इसमें ऐसा होना चाहिए कि इसके लिए कोई न कोई सिस्टम निर्धारित किया जाये क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई सिस्टम न होने के कारण हमारे नौजवानों के साथ बड़ी बेईमानी हो रही है क्योंकि किसी का आर्म्ज लाईसैंस

बन जाता है और किसी का नहीं बनता है। इन सभी बातों से परेशान होकर लोग हमारे पास आते हैं कि मेरा आर्म्ज लाईसेंस नहीं बन रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से कह कर इस काम को करवाया जाये क्योंकि आज के दिन आर्म्ज लाईसेंस रोजगार से जुड़ गया है। आज के दिन यदि किसी के पास लाईसेंसी हथियार है तो प्राईवेट सैक्टर में उनको गनमैन या पी.एस.ओ. की नौकरी मिल जाती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इसको ओपन कर देना चाहिए कि जो भी किसी से लिखवा कर ला दे कि इसको नौकरी के लिए आर्म्ज लाईसेंस चाहिए तो उनका लाईसेंस जल्दी से जल्दी बनाया जाये ताकि उन बच्चों को रोजगार मिल सके। आज जिला स्तर पर एस.पी. तथा डी.सी. के लेवर पर 200–200 लाईसेंस के केसिज पैंडिंग पड़े हुये हैं इसलिए इस समस्या को दूर करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदया, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कों के बारे में बोलना चाहता हूं। मैंने 3–4 सड़कों की बात माननीय मंत्री श्री नरबीर सिंह जी से की थी। श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास जी राव नरबीर सिंह जी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे लेकिन मैं उसी चीज की प्रशंसा करता हूं जो काम ठीक ढंग से किया गया हो। अच्छा करेंगे तो मैं प्रशंसा करूंगा। हमारी एक बहुत बढ़िया सड़क क्योड़क से तितरम तक जाती है जिसको फोरलेन बनवाने की बात कही गई थी लेकिन आज तक उस पर काम शुरू ही नहीं हुआ है इसलिए उसको फोरलेन बनवाया जाये। दूसरी सजूमा से लाम्बा खेड़ी की सड़क है उसको बनवाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलायत में घोषणा की थी लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ है इसलिए उसको भी बनवाया जाये। इसी प्रकार से कोलेखां से शिमला सड़क को बनवाने की भी घोषणा हो चुकी है लेकिन उस पर भी काम शुरू नहीं हुआ है। ये जो घोषणाएं हैं मैं अनुरोध करता हूं कि इन घोषणाओं पर एक महीने के अन्दर–अन्दर काम शुरू करवाया जाये ताकि हरियाणा प्रदेश के लोग यह समझें कि हमारे जो विधायक हैं वे कम से कम अपने इलाके की आवाज तो उठाते हैं, तथा हमारे काम करवाते हैं। अंत में मैं श्री रामबिलास शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि अगर आगामी सत्र से हमारा कॉलेज शुरू कर दिया तो मैं इनको 10 में से 10 नम्बर दूंगा । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री मक्खन लाल सिंगला : उपाध्यक्ष महोदया, सिरसा के थेड़ गांव के निवासियों को पुरातत्व विभाग ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हटा दिया है। वे लोग वहां पर

पिछले 70 साल से रह रहे थे। उनमें से कुछ परिवारों को रहने के लिए हाउसिंग बोर्ड के मकान दिये गये थे तथा बाकी लोगों को भी वहां से हटने के नोटिस दिये जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकानों में ठहराया गया है उनको अभी तक उन मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पहले उन लोगों को मकान बना कर दिये जायें तथा उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी जाये ताकि वे सही ढंग से रह सकें क्योंकि ये परिवार आर्थिक रुप से कमजोर हैं तथा मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 1984 में थेड़ गांव में 82 एकड़ जमीन थी और वहां पर हजारों लोग रह रहे थे। उस जमीन में पुरातत्व काल के सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और शिलालेख मिले हैं इसीलिए माननीय हाई कोर्ट के आदेशों से उस जमीन में पुरातत्व विभाग तथा उपायुक्त ने उन लोगों को सैक्टर 21 के हाउसिंग बोर्ड के मकानों में शिफ्ट करवा दिया है। वहां पर 1260 हाउसिंग बोर्ड के मकान थे जिनमें 649 परिवारों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस बारे में 26.10.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, पुरातत्व विभाग, उपायुक्त और हाउसिंग बोर्ड की आपस में तीन मीटिंग हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उनका समाधान कर दिया जायेगा।

श्री मक्खन लाल सिंगलाः उपाध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि ये हाउसिंग बोर्ड के मकान उनके नाम कर दिये जायें।

श्री ललित नागर (तिगांव): उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । पिछले दिनों से सदन में हमें भाजपा पार्टी के विधायकों की तरफ से सरकार के बारे में काफी कुछ सुनने को मिल रहा है । वह अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का बड़ा गुणगान कर रहे हैं । जबकि सच्चाई यह है कि अगर हम धरातल पर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है । मैडम, मैं फरीदाबाद क्षेत्र की बात करूं तो वहां चाहे बिजली विभाग है, चाहे राजस्व विभाग है, चाहे पुलिस विभाग है उनमें भ्रष्टाचार इतनी चर्म सीमा पर है जिसकी कोई सीमा नहीं है लेकिन यहां उसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है और न ही यहां कोई सुनने वाला है कि

फरीदाबाद में क्या हाल है ? इसी तरह से सदन में स्मार्ट सिटी का भी एक प्वाइंट आया था । मैं उसके बारे में बतना चाहूंगा कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था जिसके विकास के लिए सरकार की तरफ से दो–तीन किस्तों में पैसे भी आए थे लेकिन आज तक भी स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे यह कह सकें कि यह काम स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है । उसमें चाहे रोड्ज की बात हो, चाहे सीवरेज की बात हो । आज भी आप देखेंगे कि रोड्ज पर कूड़े के ढ़ेर पड़े हुए हैं । रोड्ज पर पशु मरे पड़े हैं । आज वहां इतना बुरा हाल है कि लोग यह कहने पर मजबूर हैं कि स्मार्ट सिटी से पहले जो सिटी था वही ज्यादा अच्छा था । इसी तरह से आज अगर हम किसानों की बात करते हैं तो मेरे तिगांव क्षेत्र के अन्दर 19 गांवों के जमीनदारों की जमीन एक्वायर हुई थी और वह 19 गांवों के जमीनदार हाई कोर्ट में भी गए थे कि हमें हमारी जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए । इसके साथ–साथ उन किसानों को उचित दाम पर प्लॉट दिये जाएं और जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है उनके परिवारों को एक–एक नौकरी भी दी जाए । आज उसके लिए उन किसानों को सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते हुए पांच वर्ष हो गए हैं । इसके लिए उन्होंने डी.सी. साहब को भी ज्ञापन दिया है । उन्होंने इसके लिए सभी जगह कहा है लेकिन आज तक भी उन किसानों को उनका बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया है और न ही उनको आज तक उचित रेट पर कोई प्लॉट दिए गए हैं । उन किसानों को कई बार आश्वासन भी दिए गए लेकिन आज तक उनको कुछ नहीं दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो यह कहते हैं कि हमने किसानों को सब कुछ दिया है । हमने किसानों को खुश कर दिया है । मैं कहता हूं कि आज किसानों की इतनी बुरी हालत है कि आज उनको कोई सुनने वाला नहीं है । उपाध्यक्ष महोदया, हमारे तिगांव क्षेत्र में आई.एम. टी. के किसान डेढ़–दो साल से धरने पर बैठे हुए हैं लेकिन उनकी बात को कोई भी सुनने वाला नहीं है । उनको कोई उनका अधिकार दिलाने वाला नहीं है । मेरे तिगांव क्षेत्र में 19 गांवों के किसान दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं उनको कोई सुनने वाला नहीं है । उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री और डी.सी. साहब को भी ज्ञापन दिया है लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी एक्वायर हुई जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिलवाया है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उन किसानों को उनकी जमीन का

बढ़ा हुआ मुआवजा व उचित रेट पर प्लॉट दिए जाएं । इसी तरह से मेरे तिगांव क्षेत्र के अन्दर बहुत सारा सैक्टर्ज एरिया है । उस सैक्टर्ज एरिया के अन्दर सैक्टर–37 में अशोका इन्कलेव है और आई.पी कॉलोनी, स्प्रिंग फिल्ड कालोनी है तथा राजीव नगर, संतोष नगर भी हैं जिनके अन्दर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है । आज भी वहां के लोग खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां खासकर महिलाएं रात के दो–दो बजे तक जागती हैं कि कब पानी आएगा और वे पीने का पानी भरेंगी । आज उस स्मार्ट सिटी फरीदाबाद के क्षेत्र में पानी की इतनी भारी दिक्कत है । इसी तरह से मेरे तिगांव क्षेत्र में पल्ला पुल से लेकर बसंत पुर तक लगभग लाखों आदमी कॉलोनीज के अन्दर रहते हैं और वहां पर लाखों घर बन चुके हैं लेकिन उन घरों के अन्दर न तो कोई बिजली की व्यवस्था है, न कोई सड़क की व्यवस्था है, न कोई गली पक्की है, न कोई नाली है, न सीवरेज है । पिछले दिनों सरकार के एक मंत्री ने वहां जाकर यह तो कह दिया कि हम 150 करोड़ रुपये देकर इन कॉलोनियों में सीवरेज लाईन डालेंगे लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक वहां कोई काम शुरू नहीं हुआ है। वहां एक भी गली पक्की नहीं हुई है। एक भी स्कूल नहीं बना है । एक भी पार्क नहीं बना है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करता हूं कि उन कॉलोनियों के अन्दर विकास कार्य शुरू किए जाएं । जहां तक शिक्षा का सवाल है हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहां बैठे हैं । मेरे तिगांव क्षेत्र के अन्दर कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर हुई पड़ी है । जिसके बारे में स्कूल ने भी लिख कर दे दिया है और प्रशासन ने भी उसको मान लिया है कि वह बिल्डिंग खतरनाक स्थिति में है लेकिन आज तक भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त कितने ही स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर तक नहीं हैं। सरकार बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ की बात बढ–चढकर करती है, जब स्कूलों में टीचर ही नहीं हैं, बिल्डिंग जर्जर पड़ी हुई हैं और गिरने को तैयार हैं तो ऐसे हालात में हमारी बेटियां कैसे पढ़ेगी? मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज कितने ही स्कूल ऐसे हैं जहां मास्टर नहीं है और ऐसा नहीं है कि यह हालत एक–दो महीने से है बल्कि यह हालत साल दर साल से बनी है। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कई ऐसी जगह हैं जहां पर लाखों की संख्या में घर बन चुके हैं। जैसेकि अगवानपुर, इस्माईलपुर, तिलपत या फिर पल्ला ही क्यों न हो। यहां पर गवर्नमैंट की जमीन

खाली पड़ी है जिस पर स्कूल या कॉलेज बनाया जा सकता है या फिर हस्पताल बनाया जा सकता है ताकि लोगों की शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें दूर हो जाए। यद्यपि यहां पर लाखों की संख्या में घर बस गए हैं लेकिन यहां पर हस्पताल की कोई सुविधा नहीं है अतः सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन है कि यहां पर हस्पताल की सुविधा जरूर प्रदान की जाये। उपाध्यक्ष महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मेरे जिले का नाम लेते हुए कहा गया है कि यहां पर 24 घंटे बिजली आती है। मैं चैलेंज करता हूँ अगर कोई इस बात की तसदीक कर दे कि यहां पर 24 घंटे बिजली आती है? उपाध्यक्ष महोदया, महज 8–10 घंटे ही यहां पर बिजली आती है। मेरे क्षेत्र के जमीदार सारी–सारी रात बिजली के इंतजार में बैठकर बिता देते हैं और थक हारकर बैठ जाते हैं लेकिन बिजली नहीं आती। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यह 24 घंटे बिजली देने की जो बात कही जा रही है, यह बिजली कहां पर आती है? उपाध्यक्ष महोदया, बिजली तो आती नहीं और जो बिजली के बिल दिए जाते हैं वे 50–50 हजार, 60–60 हजार तथा 70–70 हजार रूपये तक के दिए जा रहे हैं। मेरे पास इस तरह के बिजली के बिल मौजूद हैं और अगर सरकार चाहे तो मैं इन्हें दिखा सकता हूँ। सरकार द्वारा बड़े–बड़े दावे किए जा रहे हैं कि बिजली दो रूपये या अढ़ाई रूपये प्रति यूनिट कर दी गई है, अगर ऐसा है तो फिर यह भारी भरकम बिजली के बिल कहां से आ रहे हैं? मैं ऐसे भी सैंकड़ों बिल दिखा सकता हूँ जिनमें एक–दो तथा अढ़ाई लाख रूपये तक के बिजली के बिल भेज दिए गए और यह बिल ऐसे घरों के हैं जहां पर केवल दो कमरे और एक बरामदा मौजूद है या फिर एक कमरा और एक बरामदा है। ˙ उपाध्यक्ष महोदया, अभी पिछले दिनों मेरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा ओले पड़े थे और बारीश हुई थी। अखबारों में भी इस बारे में खबरें आई थी। ओलों की वजह से धरती सफेद हो गई थी और जिसके कारण फसलों को बहुत नुकसान हुआ था तथा सब्जियों को भी बहुत नुकसान हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि मवई, बादशाहपुर, पलवली, रिवाजपुर, टिकावली भतोला तथा बढ़ोली गांवों में पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा ओलावृष्टि हुई है इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इन गांवों का सर्वे करवाकर जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई जरूर करवाई जाये। उपाध्यक्ष महोदया, इसके अतिरिक्त हमारे क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत यह भी है कि हमारे तिगांव गांव के चारों तरफ एक किलोमीटर, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर तथा पांच

किलोमीटर के दायरे में 16 गांव आते हैं जिनको गलती से तिगांव से हटाकर दयालपुर तहसील के अंदर लाया गया है। दयालपुर तहसील, इन गांवों से 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन गांवों को दयालपुर तहसील से वापिस हटाकर तिगांव तहसील के साथ जोड़ा जाये। उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार एक अन्य विषय और है। जैसाकि पता चला है कि सरकार अरावली की पहाड़ियों के संबंध में एक बिल लेकर आ रही है। अरावली की पहाड़ियां दिल्ली से सटी हुई है और सोहना तक जाती हैं। यहां पर सुंदर–सुंदर पेड़ हैं, झीलें हैं और हर तरह का प्राकृतिक वातावरण इन पहाड़ियों में सुलभ है लेकिन जिस तरह से अरावली की पहाड़ियों के संदर्भ में बिल लाया जा रहा है, इससे ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर बिल्डरों और भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस बिल को सदन में पास कराने जा रही है। अगर ऐसा होगा तो अरावली की पहाड़ियों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इससे पोल्यूशन जैसी समस्या ज्यादा बढ़ेगी। मेरा निवेदन है कि सरकार को अरावली क्षेत्र को सेफ रखना चाहिए ताकि हमारा देश और प्रदेश पोल्यूशन से बचा रहे। इसी तरह से मैडम एक प्वॉयंट और कहना चाहूंगा। सरकार ने बी.पी.एल. की स्कीम निकाली है। हमें पता लगा है कि बी.पी.एल. के के कार्ड बनाये जा रहे हैं लेकिन आज तक तिगांव विधान सभा क्षेत्र में किसी भी विभाग के ऑफिसर ने मुझ से यह नहीं पूछा कि बी.पी.एल. की सूची में किस–किस के नाम डलवाने हैं। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : नागर जी, विभाग के ऑफिसर को आपसे नाम पूछना जरूरी नहीं है। (विघ्न)

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, तिगांव विधान सभा क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक नहीं है। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : नागर जी, आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सदन में इनैलो और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी मौजूद हैं। लगभग सवा चार साल पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम 'सबका साथ–सबका विकास' करेंगे। प्रत्येक हल्के के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये प्रत्येक विधायकों को ग्रांट के तौर पर देंगे। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज तक विधायकों को एक रुपया भी ग्रांट के रूप में नहीं मिला है। इस

प्रकार से सब हल्कों का विकास कैसे होगा? उपाध्यक्ष महोदया, मैंने मेरे क्षेत्र की जो–जो मांगे सदन में रखी हैं, उन सब मांगों को पूरा किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदया : नागर जी, आप वाईंड–अप कीजिए।

श्री ललित नागर : उपाध्यक्ष महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से सदन में एक बात यह कहना चाहता हूँ कि श्री टेक चंद शर्मा जी और श्री मूल चंद शर्मा जी मुझसे कह रहे थे कि सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए हम आगे चुनाव कैसे जीतेंगे? (विघ्न)

श्री मूल चंद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदया, नागर जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे यहां श्री मनोहर लाल जी की सरकार में 14 पुल, 3 कॉलेजिज, यमुनानगर के दो फ्लाई ओवर तथा अनेकों विकास के काम हुए हैं। नागर साहब तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार में पूरे फरीदाबाद का नाश हुआ था, किसानों का नाश हुआ था, कॉलोनियों का नाश हुआ था और उद्योगों का भी नाश हुआ था। पहले फरीदाबाद में चलने के लिए सड़कें नहीं थी, आज नागर जी श्री मनोहर लाल जी की सरकार की बातें कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदया, फरीदाबाद के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं है, जिसमें लाखों रुपयों का बजट न लगा हो। (विघ्न)

उपाध्यक्ष महोदया : मूल चंद शर्मा जी, कृपया करके आप बैठ जाइये। बहन बिमला चौधरी जी माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलेंगी। (विघ्न)

श्रीमती बिमला चौधरी (पटौदी) (एस.सी.) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे हल्के में एक बार नहीं दो–तीन बार ओलावृष्टि हुई है। उस ओलावृष्टि में किसानों की चाहे गोभी की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो या चाहे जौं की फसल हो वह बिल्कुल नष्ट हो गई है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बात और सदन में कहना चाहती हूँ कि मेरे से पहले बहन नैना चौटाला जी ने सदन में कहा था कि हरियाणा को पॉलिथीन मुक्त किया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, हमारा हरियाणा धीरे–धीरे पॉलिथीन मुक्त भी हो रहा है। इस अभियान में हमारी भागीदारी भी अहम होती है और सरकार की भी भागीदारी अहम होती है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक यह अभियान पूरा नहीं होगा। इसलिए हम अपने–अपने हल्के में तो इस अभियान की शुरूआत कर सकते हैं, इस प्रकार से पूरा हरियाणा प्रदेश ही नहीं

पूरा भारत पॉलिथीन मुक्त हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदया, गांव मेनेठी, जिला रेवाड़ी में हरियाणा का पहला एम्स स्थापित करने की केन्द्रीय बजट– 2019 में घोषणा की गई है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह को बधाई देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह के प्रयास से ही यह संभव हुआ है। उपाध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस सदस्यों द्वारा एक विषय यह आया था कि विकास के काम नहीं हुए हैं। लेकिन मैं यह बात दावे के साथ कहती हूँ कि विकास के काम पहली सरकार में नहीं हुए बल्कि इस सरकार में सबसे ज्यादा विकास के काम हुए हैं। चाहे पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो या फिर पंचायतों को गलियां–फिरनियां बनाने के लिए पैसे देने की बात हो हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा काम हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं 'सबका साथ सबका विकास' नारे के साथ चलने वाले माननीय मुख्य मंत्री महोदय का भी धन्यवाद करूंगी । 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की बात चली थी तो मैं कहना चाहूंगी कि इसमें भी पहले की बजाय काफी सुधार हो रहा है । उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री राम बिलास शर्मा जी से कहना चाहूंगी कि मुझे अपने हल्के के 5–6 स्कूल्ज का दर्जा बढ़वाने के लिए उनको रिकवैस्ट करते हुए 3 साल हो गए हैं । अतः वे इनका दर्जा बढ़ा दें और इसके लिए मैं इनका बहुत–बहुत धन्यवाद करूंगी ।

उपाध्यक्ष महोदया : राम चंद कम्बोज जी, अब आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिए । आपको बोलने के लिए सिर्फ 4 मिनट मिलेंगे ।

श्री राम चंद कम्बोज (रानिया) : उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं । उपाध्यक्ष महोदया, सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार का बहुत गुणगान हुआ है । अगर धरातल पर जाएं तो ऐसे काम नहीं हुए हैं । अभी जैसे माननीय सदस्य ललित नागर जी ने कहा कि सरकार ने जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में 5–5 करोड़ रूपये के विकास कार्य करवाने का वादा किया था । मेरा कहना है कि इन रूपयों के तो सरकार ने क्या काम करवाने थे सरकार ने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणाओं को ही पूरा नहीं किया । वर्ष 2015 में इसी हाउस में रानियां–बत्तावड़ में घग्गर नदी पर पुल बनाने की बात कही गई थी । इसके लिए बजट में 16.33 करोड़ रूपये निर्धारित कर दिए गए थे

लेकिन वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है । उपाध्यक्ष महोदया, फिलहाल सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय नहीं बैठे हैं । वे उस पुल को बनाने के लिए वहां पर जो लैण्ड एक्वायर की जानी है उसके लिए किसानों को 30 लाख रूपये प्रति किल्ले का आश्वासन देकर आए हैं । दुख की बात यह है कि उस पुल के निर्माण का कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है । इसके अलावा मेरी मांग है कि रानियां तहसील का दर्जा बढ़ाकर उप–मण्डल किया जाए । रानियां वर्ष 1989 से तहसील ही है । इसका अभी तक दर्जा नहीं बढ़ाया गया है । मेरा कहना है कि रानियां तहसील उप–मण्डल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी नॉर्म्स भी पूरा करती है । इसके साथ–साथ मेरी एक और मांग है कि रानियां में एक सब–तहसील भी बनाई जाए । उपाध्यक्ष महोदया, रानियां शहर में कैनाल बेस्ड वॉटर सप्लाई होती है जिसकी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके आस–पास के गांवों में पीने के पानी की ट्यूबवैल्ज से आपूर्ति की जाती है । ट्यूबवैल्ज का पानी बहुत विषैला है । उसे पीने के कारण लोगों को हैपेटाइटिस–बी, हैपेटाइटिस–सी और कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं । अगर स्वास्थ्य मंत्री जी चाहें तो इसे चैक भी करवा सकते हैं । मेरा कहना है कि अगर वहां पर नहर का पानी उपलब्ध करवाया जाए तो उनको इन बीमारियों से बचाया जा सकता है । उपाध्यक्ष महोदया, रानियां की सी.एच.सी. की जो बिल्डिंग है वह जर्जर हालत में है । उसका एस्टीमेट बना हुआ है लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है । पिछले बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि हम उसका जल्द ही शुरू करवा देंगे लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है । इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि रानियां नगरपालिका में मैम्बर और रानियां हल्के के गांवों में जब भी कोई नया सरपंच/नई सरकार बनती है तो वहां की पुरानी गलियों को उखाड़कर नया बनाया जाता है । मेरा कहना है कि उनका एक लैवल बनाकर सभी गांवों, नगरपालिकाओं, नगर परिषदों आदि के लिए स्ट्रॉम वॉटर सीवरेज की व्यवस्था की जाए । अब तो सैंटर गवर्नमैंट की तरफ से कई ऐसे कोष हैं जिनसे प्रदेश सरकार को काफी मदद मिल रही है । अतः मेरा निवेदन है कि इस सिस्टम को अपनाया जाए ताकि बार–बार गलियां उखाड़ने के काम से हमारी जान छूटे । (विघ्न)

14:00 बजे

बैठक का समय बढ़ाना

उपाध्यक्ष महोदया : यदि हाउस की सहमति हो तो बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, बैठक का समय 5 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री राम चन्द कम्बोज : उपाध्यक्ष महोदया, मैं सदन में एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूंगा । 'भारत माला प्रोजैक्ट सैंटर' का एक भारत माला प्रोजैक्ट आया था । इसके तहत बठिंडा को अजमेर शरीफ से जोड़ने के लिए 6 लेन का एक प्रोजैक्ट था । मुझे लगता है कि शायद हरियाणा सरकार इस प्रोजैक्ट को कंपलीट नहीं करना चाहती । इस प्रोजैक्ट में सिरसा जिले का 68 किलोमीटर का एरिया कवर होता है । आपकी सरकार 'सबका साथ सबका विकास' का नारा देती है । अतः इस 6 लेन के प्रोजैक्ट के लिए हरियाणा सरकार को केन्द्र सरकार के पास पत्र लिखकर भेजना चाहिए । इस बठिंडा से अजमेर शरीफ के प्रोजैक्ट के पूरा होने से श्रद्धालुओं को समस्या नहीं आएगी । इसके अलावा सरकार को घग्गर नदी की खुदाई करवानी चाहिए क्योंकि सिरसा जिले में पैडी की क्रॉप ज्यादा होती है । सरकार ने सिरसा, रानियां और ऐलनाबाद के एरिया को डार्क जोन घोषित किया हुआ है । मेरा कहना है कि सरकार को घग्गर नदी की एन.जी.सी. और एस.जी.सी. नहरों पर किसानों के स्पैशल मोघे देने चाहिए ताकि वहां के किसान अपनी फसल को तैयार कर सकें । वहां पर ग्राउंड वॉटर लैवल काफी नीचे गया हुआ है और डॉर्क जोन एरिया होने के कारण वहां पर ट्यूबवैल्ज आदि लगाने पर भी बैन लगा हुआ है । अगर घग्गर नदी की खुदाई होगी तो पानी सुचारू रूप से आगे जा सकेगा और बरसात के मौसम में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी । मैं कहना चाहूंगा कि सिरसा जिले की सीमाएं पंजाब और राजस्थान राज्य से लगती हैं । मेरे क्षेत्र में चिट्टे का नशा किया जाता है और इसके नशेड़ी दिन–ब–दिन बढ़ते जा रहे हैं । इस बारे में मैंने पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मिलकर चर्चा की थी । मेरे क्षेत्र में स्पैशल टास्क फॉर्स की एक टीम बनाकर सीमाओं के साथ लगती हुई चौकियों को अच्छी गाड़ियां देकर सशक्त बनाया जाए । इससे वे नशे के तस्करों को कंट्रोल कर सकेंगे और नशे की सप्लाई पर पाबंदी लग सकेगी । मैं निवेदन करूंगा कि बुखारा खेड़ा से खाई शेरगढ़ का एक सड़क के छोटे–से टुकड़े

की अगर मार्केटिंग बोर्ड से अप्रूवल हो जाए तो माननीय मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी होगी । इसके अलावा मैं कहूंगा कि सिरसा जिले में कैंसर जैसी बीमारियों के लिए एम्स या पी.जी.आई. की तर्ज पर कोई इंस्टीच्युट बनाया जाए क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद के क्षेत्र में कैंसर जैसी बीमारियों से लोग सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं । मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को एम्स की तर्ज पर कोई अच्छा हैल्थ इंस्टीच्युट स्थापित करने के लिए पत्र लिखा जाना चाहिए । इससे वहां के लोगों को कैंसर और हैपेटाइटिस–सी का इलाज करवाने की सुविधा मिल सकेगी । मैं कहूंगा कि हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एनाउंसमैंट की थी कि हर हल्के में 25 किलोमीटर तक की लम्बाई की सड़कें बनाई जाएंगी । उस समय उन्होंने कहा था कि ये सड़के जनप्रतिनिधियों की तरफ से रिकमैंड होकर बनाई जाएंगी । मैं कहना चाहता हूं कि अगर यह बात सच है तो इसका भी हमें ब्यौरा दिया जाए । उपाध्यक्ष महोदया, सरकार ने ढ़ाणियों के लिए सड़कें बनाने के लिए एक मुहिम चलाई थी । अतः इन सड़कों को बनाया जाना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदया, मैं कहूंगा कि नहरों के मोघों की सरकार ने जो 6000 रूपये प्रति किसान फीस जमा करवाई थी वह फीस लौटाई जानी चाहिए । अगर सरकार उन किसानों को इस तरीके से न नहर का पानी देगी और न ट्यूबवैल्ज के पानी के लिए पर्याप्त बिजली देगी तो किसान किस तरीके से धान की फसल तैयार कर पाएगा ? उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से कहना चाहूंगा कि किसानों को 6000 रूपये मोघों की फीस वापस लौटाई जाए ताकि किसान अपनी फसल की अच्छे ढ़ंग से सम्भाल कर सकें । उपाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे राज्यपाल अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदया, अभी मेरी कुछ बातें कहने से रह गयी हैं । यदि आप अनुमति दें तो मैं अपनी स्पीच में अपने हल्के की कुछ समस्याओं को एड करवाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप जो बातें एड करवाना चाहते हैं उसे सदन के पटल पर रख दीजिए । उसे आज की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बना दिया जाएगा ।

***श्री राम चन्द कम्बोज :** उपाध्यक्ष महोदया, मैं अपने हल्के की निम्नलिखित ढ़ाणियों के 25 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को आज की प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनवाना चाहता हूं :–

***चेयर के आदेशानुसार उपर्युक्त लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया ।**

1. रानियां–बालासर रोड़ से ढ़ाणी पंजाब वाली तक रास्ता पक्का करना ।
2. ओटू–झोतड़ रोड़ से ढ़ाणी बंगी तक रास्ता ।
3. बजी–बचेर रोड़ से ढ़ाणी प्यारा सिंह मुन्शी राम कम्बोज ढ़ाणी तक ।
4. रानियां–नानुआना रोडसे ढ़ाणी सरूप सिंह तक ।
5. घनुर–झोरड़नाली रोड़ से ढ़ाणी बिलासपुर तक रास्ता पक्का करना ।
6. करीवाला–बणी रोड़ से ढ़ाणी सोभा सिंह तक ।
7. केहरवाला–चक्का रोड़ से नत्थू राम मूंड (गिंदड़ा) की ढ़ाणी तक ।
8. झोरड़–झोरड़नाली रोड़ से ढ़ाणी–बंगी तक रास्ता पक्का करना है ।
9. खारिया गांव से ढ़ाणी विजयपाला कासनिया खारिया तक ।

उपाध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन आज दिनांक 22 फरवरी, 2019 को दोपहर 3:00 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है।

***2:04 बजे** **(तत्पश्चात् सभा शुक्रवार दिनांक 22 फरवरी, 2019, दोपहर 3:00 बजे (द्वितीय बैठक) तक के लिए स्थगित हुई ।)**